रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-73 REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 14, 1985/भाद्र 23, 1907
No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 14, 1985/BHADRA 23, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 19 अगस्त 1985

सूचना

का.आ. 4213.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री समीर कुमार सेन गुप्ता, एडवोकेट, हाई कोर्ट 10 ओल्ड पोस्ट रूम नं. 5ए लैफ्ट ब्लाक ग्राउन्ड फ्लोर, कलकत्ता ।

उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे कलकत्ता, 24-परगना व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए ।

2. उक्त व्यक्ति को नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए ।

[सं. 5(36) 85—न्या.]

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 19th August, 1985

NOTICE

S.O. 4213.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Samir Kumar Sengupta, Advocate, High Court, 10, Old Post Office St. Room No. 5A, Left Block, Ground Floor, Calcutta, for appointment as a Notary to practise in Calcutta and 24-Parganas.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(36)/85-Judl.]

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1985

सूचना

का. आ. 4214.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री चन्द्रकांत मोहनलाल छाजड, एडवोकेट पुना ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे पूना व्यवसाय के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(29)85 न्या.]

एस. गुप्तु, सक्षम प्राधिकारी

New Delhi, the 2nd September, 1985

NOTICE

S.O. 4214.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Chandrakant Mohanlal Chhajed, Advocate, Poona for appointment as a Notary to practise in Poona.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(29)/85-Judl.]

S. GOOPTU, Competent Authority

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1985

आयकर

का. आ. 4215.—इस कार्यालय की दिनांक 22-10-1983 की अधिसूचना सं. 5434 (फा. सं. 203/154/83-आ. क. नि. II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) (पैंतीस/एक/दोके प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

1. यह कि राजकोट कैंसर सोसायटी, राजकोट वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रहेगा।

2. यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष, 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

4. यह कि उक्त संस्था अनुमोदन की समाप्ति के 3 महीने पहले समयावधि बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली को आवेदन करेगा।

अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"राजकोट कैंसर सोसायटी, राजकोट"।

यह अधिसूचना 1-4-1985 से 31-3-1986 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6334 (फा. सं. 203/120/85-आ. क०नि०-II]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 19th July, 1985

INCOME-TAX

S.O. 4215.—In continuation of this Office Notification No. 5434 (F. No. 203/154/83-ITA. II) dated 22-10-1983, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Science and Technology, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

(i) That the Rajkot Cancer Society, Rajkot will maintain a separate account of the sums received by it for scientific reasearch.

(ii) That the said Society will furnish annual returns of its scientific rescarch activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Society will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

(iv) That the said Soiety will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

"Rajkot Cancer Society, Rajkot".

This Notification is effective for a period from 1-4-1985 to 31-3-1986.

[No. 6334 (F. No. 203/120/85-ITA. II)]

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1985

आयकर

का० आ० 4216.—इस कार्यालय की दिनांक 25-1-1982 की अधिसूचना सं. 4441 (फा. सं. 203/59/81-आ० क० नि.-II के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) (पैंतीस/एक/तीन) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

1. यह कि कर्वे इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, पुणे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का प्रथक् लेखा रखेगा।

2. यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

4. यह कि उक्त संस्थान अनुमोदन की समाप्ति के 3 महीने पहले समयावधि बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली को आवेदन करेगा। अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"कर्वे इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, पुणे"।

यह अधिसूचना 1-4-84 से 31-3-87 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6351 (फा. सं. 203/197/84-आ.क. नि.-II)]

New Delhi, the 31st July, 1985

INCOME-TAX

S.O. 4216.—In continuation of this Office Notification No. 4441 (F. No. 203/59/81-ITA.II) dated 25-1-1982, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Three) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

(i) That the Karve Institute of Social Service, Pune will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

(iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

"Karve Institute of Social Service, Pune".

This Notification is effective for a period from 1-4-1984 to 31-3-1987.

[No. 6351 (F. No. 203/197/84-ITA.II)]

का. आ. 4217.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

1. यह कि लाल बहादुर शास्त्री इंजीनियरिंग रिसर्च एंड कंसलटेंसी सेंटर, त्रिवेंद्रम वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रहेगा।

2. यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

"लाल बहादुर शास्त्री इंजीनियरिंग रिसर्च एंड कंसल्टेंसी सेंटर, त्रिवेंद्रम"।

यह अधिसूचना 11-5-84 से 31-3-1987 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6350 (फा. सं. 203/93/84-आ.क.नि-II

S.O. 4217.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions :—

(i) That the Lal Bahadur Shastri Engineering Research And Consultancy Centre, Trivandrum will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

"Lal Bahadur Shastri Engineering Research and Consultancy Centre, Trivandrum".

This Notification is effective for a period from 11-5-1984 to 31-3-1987.

[No. 6350 (F. No. 203/93/84-ITA.II)]

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1985

(आय-कर)

का. आ. 4218.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) (पैंतीस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

1. यह कि सेंटर फार अर्थ साइंस स्टडीज, त्रिवेंद्रम वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

2. यह कि उक्त केन्द्र अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त केन्द्र अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियों, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

4. यह कि उक्त केन्द्र अनुमोदन की समाप्ति से तीन मास पहले समयावधि बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को आवेदन करेगा। अनुमोदन की समाप्ति के बाद प्रार्थना पत्र को रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"सेंटर फार अर्थ साइंस स्टडीज त्रिवेंद्रम"

यह अधिसूचना 7-9-1984 से 31-3-86 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6360 (फा. सं. 203/175/84-आ०क०नि० II)]

गिरीश दवे, अवर सचिव

New Delhi, the 5th August, 1985

INCOME-TAX

S.O. 4218.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions :—

(i) That Centre for Earth Science Studies, Trivandrum will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Centre will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Centre will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets

liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

(iv) That the said Centre will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

"Centre for Earth Science Studies, Trivandrum".

This Notification is effective for a period from 7-9-1984 to 31-3-1986.

[No. 6360 (F. No. 203/175/84--ITA.II)]

GIRISH DAVE, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1985

आयकर

का.आ. 4119—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप खण्ड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 27-7-83 की अधिसूचना सं. 5326 (फा. सं. 398/29/83-आ.क. (ब.) का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एच. आर. कवादकर को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना, श्री एच. आर. कवादकर द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी ।

[सं. 6341/फा.सं. 398/15/85—आ.क. (ब.)]

बी. ई. अलैक्जेंडर, अवर सचिव

New Delhi, the 25th July, 1985

INCOME TAX

S.O. 4219.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Govt. of India in the Department of Revenue No. 5326 (F. No. 398/29/83-IT(B) dated the 27-7-83, the Central Government hereby authorises Shri H. R. Kawadkar, being a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri H. R. Kawadkar takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 6341 F. No. 398/15/85-IT(B)]

B. E. ALEXANDER, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1985

प्रधान कार्यालय संस्थापन

का.आ. 4220—केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का संख्यांक 54) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के अधिकारी श्री एस. आई. त्रिपाठी को, जो पिछले दिनों वाणिज्य मंत्रालय नई दिल्ली में अपर आयात तथा निर्यात नियंत्रक के रूप में तैनात थे, 26 जून, 1985 पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है ।

[फा. सं. क-19011/3/85-प्रशा. 1]

जे. एम. ट्रेहन, अवर सचिव

New Delhi, the 16th August, 1985

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT

S.O. 4220.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Central Board of Revenue Act, 1963 (54 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri S. I. Tripathi, an officer of the Indian Revenue Service (Income-tax) and formerly posted as Additional Controller of Imports & Exports in the Ministry of Commerce, New Delhi, as Member of the Central Board of Direct Taxes with effect from the forenoon of the 26th June, 1985 and until further orders.

[F. No. A-19011/3/85-Ad. 1]

J. M. TREHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1985

आदेश

स्टाम्प

का.आ. 4221.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दि एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लि. बम्बई को मात्र आठ लाख तैंतालीस हजार, सात सौ पांच रुपये के उस समेकित स्टाम्प शुल्क की अदायगी की अनुमति देती है, जो उक्त कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले कुल मिलाकर ग्यारह करोड़ पच्चीस लाख रुपये के अंकित मूल्य के ऋणपत्रों (एक करोड़ पच्चीस लाख रुपये के अंकित मूल्य के नी.ए.टे.ए.डी. ऋण की श्रृंखला तथा दस करोड़ रुपये मूल्य के अंकित मूल्य के डब्ल्यू. ए. डी. आई./जी. ए. जी. ए. एल. ऋण की श्रृंखला (ii) के रूप में बंध पत्रों पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है ।

[सं. 31/85-स्टाम्प/फा. सं. 33/27/85-वि.क.]

New Delhi, the 16th August, 1985

ORDER

STAMPS

S.O. 4221.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits The Associated Cement Companies Ltd., Bombay, to pay consolidated stamp duty of eight lakhs, forty-three thousand, seven hundred and fifty rupees only, chargeable on account of stamp duty on bonds in the form of debentures (Series I for CATAD loan of the face value of one crore and twenty five lakhs rupees and Series II for WADI/GAGAL loan of the face value of ten crores rupees) of the face value of eleven crores and twenty-five lakhs rupees only in total to be issued by the said Company.

[No. 31/85-Stamps/F. No. 33|27|85-ST]

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1985

आदेश

स्टाम्प

का. आ. 4222.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा हिन्दुस्तान विकास निगम लि. कलकत्ता को केवल चार लाख, पचास हजार रुपये के उस समेकित स्टाम्प शुल्क की अदायगी करने की अनुमति देती है जो उक्त कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले छः करोड़ रुपये के अंकित मूल्य के 15% असम्परिवर्तनीय ऋणपत्रों (श्रृंखला V) पर जिनकी क्रम संख्या 15,00,001 से 21,00,000 तक है, स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है।

[सं. 32/85-स्टाम्प/फा. सं. 33/28/85-बि० क०]

New Delhi, the 29th August, 1985

ORDER

STAMPS

S.O. 4222.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Hindustan Development Corporation Limited, Calcutta to pay consolidated stamp duty of Four lakhs and fifty thousand rupees only, chargeable on account of the stamp duly on 15 per cent Non-Convertible Debentures (Series V) bearing serial numbers 15,00,001 to 21,00,000 of the face value of Six crores rupees to be issued by the said Company.

[No. 32|85-Stamps|F. No.33|28|85-ST.]

आदेश

स्टाम्प

का. आ. 4223.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स दि ग्रेटईस्टर्न शिपिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई को मात्र नौ लाख अट्ठावन हजार एक सौ पच्चीस रुपये के उस समेकित स्टाम्प शुल्क की अदायगी करने की अनुमति देती है, जो उक्त कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले बारह करोड़ सत्तहत्तर लाख पचास हजार रुपये के अंकित मूल्य के संपरिवर्तनीय सौ-सौ रुपये के ऋणपत्रों (क्र. सं. 1 से 12 77,500 तक), के रूप में बंध पत्रों पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है।

[संख्या 33/85-स्टाम्प/फा. सं. 33/20/85-वि.क.]

भगवान, दास, अवर सचिव

ORDER

STAMPS

S.O. 4223.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits M/s. The Great Eastern Shipping Co. Ltd., Bombay, to pay consolidated stamp duty of Nine lakhs Fifty eight thousand, one hundred and twenty five rupees only, chargeable on account of stamp duty on Bonds bearing Sl. Nos. 1 to 12 77,500 of Rs. 100 each in the form of convertible debentures of the face value of Twelve crores Seventy Seven lakhs and Fifty thousand rupees only to be issued by the said Company.

[No. 33|85-Stamps|F. No. 33|20|85-ST]

BHAGWAN DAS, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 मई, 1985

आयकर

का.आ. 4224.—आयकर अधिनियम 1961, (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (IV) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "गुजरात इकॉलोजीकल एजूकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन" को कर निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1986-87 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 6239/फा.सं. 197/125/84 आ. क. (नि-1)]

New Delhi, the 31st May, 1985

(INCOME-TAX)

S.O. 4224.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Gujarat Ecological Education and Research Foundation" for the purpose of the said section for the period covered the assessment years 1983-84 to 1986-87.

[No. 6239|F. No. 197/125/84-IT(AI)]

नई दिल्ली, 10 जून, 1985

(आयकर)

का. आ. 4225.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 ग) के उपखंड (IV) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ "पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री का राहत कोष" को कर निर्धारण वर्ष 1981-82 से 1986-87 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करते है।

[सं. 6257/फा. सं. 197/60/83 आ. क. (नि.-1)]

New Delhi, the 10th June, 1985

(INCOME-TAX)

S.O. 4225.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "West Bengal Chief Minister's Relief Fund" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1981-82 to 1986-87.

[No. 6257/F. No. 197/60/83-IT (AI)]

नई दिल्ली, 13 जून, 1985

आयकर

का. आ. 4226.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (IV) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "दि इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया" को कर निर्धारण-वर्ष 1985-86 से 1987-88 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6267/फ़ा. सं. 197/157/77 आ.क. (नि. 1)]

New Delhi, the 13th June, 1985

(INCOME-TAX)

S.O. 4226.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Institute of Chartered Accountants of India" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6267/F. No. 197/157/77-IT (AI)]

नई दिल्ली, 18 जून, 1985

आयकर

का. आ. 4227:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "इंडियन एक्ससर्विसिज लीग" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6272/फ़ा. सं. 197-ए/107/82-आ.क. (नि. 1)]

New Delhi, the 18th June, 1985

(INCOME-TAX)

S.O. 4227.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Indian Ex-Services League" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6272/F. No. 197-A/107/82-IT (AI)]

आयकर

का. आ. 4228:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "विवेकानन्द मिशन आश्रम" को कर-निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1987-88 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6274/फ़ा. सं. 197/210/83-आ.क. (नि. 1)]

(INCOME-TAX)

S.O. 4228.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Vivekananda Mission Ashram" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1983-84 to 1987-88.

[No. 6274/F. No. 197/210/83-IT (AI)]

आयकर

का. आ. 4229:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "इण्डिया स्पोंसरशिप कमेटी बम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6275/फ़ा. सं. 197-ए/36/82-आ.क. (नि. 1)]

(INCOME-TAX)

S.O. 4229.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "India Sponsorship Committee, Bombay" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6275/F. No. 197-A/36/82-IT (AI)]

आयकर

का. आ. 4230:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान" को कर-निर्धार वर्ष 1985-86 से 1987-88 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6277/फ़ा. सं. 197/128/84-आ.क. (नि. 1)]

(INCOME-TAX)

S.O. 4230.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sevagram Ashram Pratishthan" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6277/F. No. 197/128/84-IT (AI)]

आयकर

का. आ. 4231.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "इन्दिरा गांधी मैमोरियल ट्रस्ट" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1989-90 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6278/फा. सं. 197/84/85-आ. क. (नि. 1)]

(INCOME-TAX)

S.O. 4231.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Indira Gandhi Memorial Trust" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1989-80.

[No. 6278/F. No. 197/84/85-IT(AI)]

आयकर

का. आ. 4232.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "सहकारी प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद" को कर निर्धारण-वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6279/फा.सं. 197/134/83-आ. क. (नि. 1)]

(INCOME-TAX)

S.O. 4232.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Institute of Co-operative Management, Ahmedabad" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1983-84, 1984-85 and 1985-86.

[No. 6279/F. No. 197/134/83-IT (AI)]

नई दिल्ली, 25 जून, 1985

(आयकर)

का. आ. 4233.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "सर रतन टाटा ट्रस्ट, बम्बई" को कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6283/फा.सं. 197-ए/106/82-आ. क. (नि.-1)]

New Delhi, the 25th June, 1985

(INCOME-TAX)

S.O. 4233.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sir Ratan Tata Trust, Bombay" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6283/F. No. 197-A/106/82-IT (AI)]

आयकर

का. आ. 4234.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "हरिजन सेवक संघ" को कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करता है।

[सं. 6285/फा. सं. 197/46/84-आ. क. (नि.-1)]

(INCOME-TAX)

S.O. 4234.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Harijan Sevak Sangh" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6285/F. No. 197/46/84-IT (AI)]

आयकर

का. आ. 4235.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "दि इण्डियन सैक्शन, दि थी-ओसोफ़िकल सोसाइटी वाराणसी" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6286/फा. सं. 197-ए/169/82-आ. क. (नि.-1)]

(INCOME-TAX)

S.O. 4235.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Indian Section, The Theosophical Society, Varanasi" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6286/F. No. 197-A/169/82-IT (AI)]

नई दिल्ली, 26 जून, 1985

आयकर

का. आ. 4236.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास में अनुसंधान हेतु केन्द्र" को कर-निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1986-87 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6291/फा.सं. 197/53/83-आ. क. (नि. 1)]

New Delhi, the 26th June, 1985

(INCOME-TAX)

S.O. 4236.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Centre for Research in Rural and Industrial Development" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1986-87.

[No. 6291/F. No. 197/53/83-IT(AI)]

(आयकर)

का.आ. 4237 :—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ "परिवार नियोजन संस्थापन" को कर निर्धारण वर्ष 1986-87 और 1987-88 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है ।

[सं. 6992 /फा.सं. 197/73/84-आ.क. (नि. 1)]

(INCOME-TAX)

S.O. 4237.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Family Planning Foundation" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1986-87 and 1987-88.

[No. 6292/F. No. 197/73/84-IT (AI)]

आयकर

का.आ. 4238 .—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ "फेडरेशन आफ इण्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री नई दिल्ली" को कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिये अधिसूचित करती है ।

[सं. 6293/फा.सं. 197/111/81-आ.क. (नि. 1)]

(INCOME-TAX)

S.O. 4238.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, New Delhi" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88

[No. 6293/F. No. 197/111/81-IT (AI)]

आयकर

का.आ. 4239 .—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ "दि नेशनल ऐसोसिएशन फार ब्लाइण्ड" को कर निर्धारण वर्ष 1985-86—वर्ष 1987-88 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है ।

[सं. 6294/फा.सं. 197-ए/248/82-आ.क. (नि.-1)]

(INCOME-TAX)

S.O. 4239.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The National Association for the Blind" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6294/F. No. 197-A/248/82-IT (AI)]

नई दिल्ली, 28 जून, 1985

आयकर

का.आ. 4240 .—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ "श्री कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन (धर्मार्थ औषालय) कालेरा जिला अजमेर" को कर निर्धारण वर्ष 1980-81 से 1985-86 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है ।

[सं. 6298/फा.सं. 197/33/84-आ.क. (नि० 1)]

New Delhi, the 28th June, 1985

(INCOME-TAX)

S.O. 4240.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Krishna Gopal Ayurved Bhawan (Dharmarth Aushdhalaya), Kalera, Distt. Ajmer" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1980-81 to 1985-86.

[No. 6298/F. No. 197/33/84-IT (AI)]

(आयकर)

का.आ. 4241.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ "दि भारत स्काउंटस एण्ड गाइडस" को कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है ।

[सं. 6299/फा.सं. 197-ए/69/82-आ.क. (नि. 1)]

(INCOME-TAX)

S.O. 4241.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Bharat Scouts and Guides" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985 86 to 1987-88.

[No. 6299/F. No. 197-A/69/82-IT (AI)]

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1985

आयकर

का० आ० 4242 :—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "आर्य वैद्य शाला, कोट्टाक्कल (केरल)" को कर निर्धारण वर्ष 1986-87 से 1988-89 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 6330/फा०सं० 197/171/84-आ०क० (नि० 1)]

New Delhi, the 19th July, 1985

(INCOME-TAX)

S.O. 4242.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Arya Vaidya Sala, Kottakkal (Kerala)" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1986-87 to 1988-89.

[No. 6330/F. No. 197/171/84-IT (AI)]

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1985

आयकर

का०आ० 4243.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "आन्ध्र महिला सभा, हैदराबाद" को कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 6355/फा०सं० 197/50/85—आ०क०(नि०-1)]

आर० के० तिवारी, अवर सचिव

New Delhi, the 1st August, 1985

(INCOME-TAX)

S.O. 4234.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Andhra Mahila Sabha, Hyderabad" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6355/F. No. 197/50/85-IT (AI)]

R. K. TEWARI, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1985

आदेश

का. आ. 4244.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/192/84-सी. शु.-8, तारीख 18-9-1984 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री इसाक रेमण्ड इसाक, निवासी 150/ए सादुर सदन (स्वेचन्द भवन), रोड-9 वडोदा, बम्बई-3 को बंबई केन्द्रीय जेल में निरुद्ध कर लिया जाय और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे माल की तस्करी करने और माल की तस्करी के लिए प्रेरित करने से और तस्करी के माल को लाने-ले-जाने का धन्धा करने से रोका जा सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके; और

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर अपर आयुक्त पुलिस अपराध ग्रेटर बम्बई के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/192/84-सी. शु.—VIII]

New Delhi, the 9th September, 1985

ORDER

S.O. 4244.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empawered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673|192|84-Cus. VIII, dated 18-9-84 under the said sub-section directing that Shri Isac Raymond Isaac residing at 150|A, Sadur Sadhan (Swechand Bhawan), Road-9, Wadoda, Bombay-3 be detained and kept in custody in the Bombay Central Prison, with a view to preventing him from smuggling goods and abetting the smuggling of goods and engaging in transporting smuggled goods.

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Gevernment hereby directs the aforesaid person to appear before the Aditional Commissioner of Police (Crime), Greater Bombay within 7 days of the publication of this order in the official Gazette

[F. No. 673|192|84-Cus. VIII]

का. आ. 4245.—भारत सरकार के अपर सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/13/84-सी. शु. viii, तारीख 28-6-84 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री मंगल सिंह पुत्र श्री हरिसिंह, 99, त्रिवेणी गंज, हापुड़ (गाजियाबाद) उत्तर प्रदेश को तस्करी के माल को लाने-ले जाने से निवारित करने की दृष्टि से सेन्ट्रल जेल, बरेली में निरुद्ध कर दिया जाय और अभिरक्षा में रखा जाए।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं सके; और

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/13/84-सीमा शुल्क-8]

S.O. 4245.—Whereas the Additional Secretary to the Government of India, specially empawered under sub-section (1) of section 3 of the Censervation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673|13|84-Cus. VIII, dated 28-6-84 under the said sub-section directing that Shri Mangal Singh, Son of Shri Hari Singh, 99, Triveniganj Hapur, (Ghaziabad), U.P. be detained and kept in custody in Central Jail, Barellly with a view to praventing him from engaging in transporting smuggled goods;

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is cancealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Aot, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Inspector General of Police, U.P., Lucknow within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673|13|84-Cus. VIII]

का. आ. 4246.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा सं 673/190/84-सी. शु. 8, तारीख 18-9-84 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री ताहेर तायब मोहियालदरीन उर्फ ताहेर सोनी ए-1—मदीना बिल्डिंग पहली मंजिल, गाफरस एवेन्यू, मार्लीभाई स्ट्रीट, बम्बई-8 को माल की तस्करी करने तथा माल की तस्करी हेतु दुष्प्रेरित करने तथा तस्करी के माल को लाने-ले-जाने का धन्धा करने से निवारित करने की दृष्टि से केन्द्रीय कारागार, बम्बई में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाए।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके, और

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर अपर पुलिस आयुक्त (अपराध) ग्रेटर बम्बई के समक्ष हाजिर हो ।

[फा. सं. 673/190/84-सी. शु.- 8]

S.O. 4246.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Censervation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673|190|84-Cus. VIII, dated 18-9-84 under the said sub-section directing that Shri Taher Tayal Moheyaldeen @ Taher Sony, residing at AI-Madina Building, Ist Floor, Cyrus Avenue Malibhai Street, Bombay-8 be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from smuggling goods and appear before the Additional Commissioner of Police the smuggled goods.

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Additional Commissionar of Police (Crime), Greater Bombay within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673|190|84-Cus. VIII]

का. आ. 4247.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है उक्त धारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/15/85-सी. शु.-8, तारीख 14-2-1985 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री परिमल चन्द्र घोष, पुत्र श्री अमूल्य चन्द्र घोष, तालापारा, नारायणगंज ढाका, बंगलादेश को प्रेसिडेंसी जेल कलकत्ता में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि वह माल की तस्करी न कर सके ।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके, और

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिरीक्षक पश्चिम बंगाल कलकत्ता के समक्ष हाजिर हो ।

[फा० सं० 673/15/85-सी० शु०-VIII]

S.O. 4247.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673|15|85-Cus. VIII, dated 14-2-1985 under the said sub-section directing that Shri Palimal Chandra Ghosh, Son of Shri Amullya Chandra Ghosh, Talapara, Narayanganj, Dhaka, Bangladesh be detained and kept in custody in the Presidency Jail, Calcutta with a view to preventing him from smuggling goods.

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Inspector General of Police, West Bengal Calcutta within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673|15|85-Cus. VIII]

का. आ. 4248.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है उक्त उपधारा के अधीन फा. सं. 673/16/85-सीमा शुल्क-8, तारीख 14-2-1985 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री सुभाष साह पुत्र श्री उपेन्द्र साह नवाबगंज, चौकीघाट पत्रालय अगला ढाका बंगलादेश को माल की तस्करी करने से रोकने की दृष्टि से प्रेसिडेंसी जेल कलकत्ता में निरुद्ध कर लिया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं सके; और

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिरीक्षक, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता के समक्ष हाजिर हो ।

[फा. स. 673/16/85-सीमा शुल्क-8]

S.O. 4248.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foregin Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673|16|85-Cus. VIII, dated 14-2-1985 under the said sub-section directing that Shri Subash Saha, son of Shri Upendra Saha, Nawabganj, Chowkighata, P.O. Agla Dhaka, Bangladesh be detained and kept in custody in the Presidency Jail, Calcutta with a view to preventing him from smuggling goods;

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Inspector General of Police. West Bengal, Calcutta within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/16/85-Cus. VIII]

का. आ. 4249.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया गया है उक्त उपधारा के अधीन फा. सं. 673/17/85-सीमा शुल्क-8, तारीख 14-2-1985 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि मोहम्मद अब्दुल खालिक पुत्र स्व. उजरूद्दीन बिश्वास, ग्राम महाबलातपुर शीशतबीघा (पत्रालय) जिला माल्दा को प्रेसिडेंसी जेल, कलकत्ता में निरुद्ध कर लिया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे सोने की तस्करी के धंधे को दुष्प्रेरित करने से और तस्करी के सोने को लाने-ले-जाने से और तस्करी के सोने को छिपा कर रखने से रोका जा सके ।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके; और

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिरीक्षक, पश्चिम बंगाल, के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/17/85-सीमाशुल्क-8]

S.O. 4249.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/17/85-Cus. VIII, dated 14-2-85 under the said sub-section directing that Md. Abdul Khaleque, son of Late Ujaruddin Biswas, Vill. Mahablatpur, Duishatabigha (P.O.), Distt. Malda be detained and kept in custody in the Presidency Jail, Calcutta with a view to preventing him from abetting smuggling of gold and engaging in transporting and concealing smuggled gold.

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Inspector General of Police, West Bengal within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/17/85-Cus. VIII]

का. आ. 4250.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 673/32/85-सी. शु.-8, तारीख 17-4-85 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि मुहम्मद मुस्ताक अहमद पुत्र मुहम्मद शमसुद्दीन, प्लैट 3/186, ए. के. अब्दुल कबीर रोड़, राजाबागान, कलकत्ता-44 को प्रेसिडेंसी जेल में निरुद्ध कर लिया जाये और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि वह तस्करी के माल को छिपाने और उसे अपने पास रखने का धन्धा न कर सके।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके, और

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, कलकत्ता के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 673/32/85-सी. शु.-8]
आर. के. तिवारी, उप सचिव

S.O. 4250.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/32/85-Cus. VIII, dated 17-4-1985 under the said sub-section directing that Md. Mostaque Ahmed, son of Md. Samsuddin, Z-3/186, A.K. Abdul Kabir Road, Raja Bagan, Calcutta-44 be detained and kept in custody in the Presidency Jain with a view to preventing him from engaging in concealing and keeping smuggled goods;

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Calcutta within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/32/85-Cus. VIII]
P. K. TIWARI, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 8 जुलाई 1985

आयकर

का०आ० 4251.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "जे०आर०डी० टाटा ट्रस्ट, बम्बई" को कर निर्धारण-वर्ष 1985-86 से 1987-88 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 6305/फा० 197-ए/145/82-आ०क० (नि० 1)]

New Delhi, the 8th July, 1985

(INCOME-TAX)

S.O. 4251.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "J.R.D. Tata Trust, Bombay" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6305/F. No. 197-A/145/82-IT (AI)]

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1985

आयकर

का०आ० 4252.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "कस्तूरबा गांधी कन्या गुरुकुलम, वेडरनियम तंजावुर डिस्ट्रिक्ट" को कर-निर्धारण-वर्ष 1984-85 से 1986-87 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 6324/फा०सं० 197/67/84-आ०क० (नि० 1)]

New Delhi, the 16th July, 1985

(INCOME-TAX)

S.O. 4252.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Kasthurba Gandhi Kanya Gurukulam, Vedaraniam, Thanjavur District" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1984-85 to 1986-87.

[No. 6324/F. No. 197/67/84-IT (AI)]

का०आ० 4253.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा के 10 खंड (23ग) के उपखंड (4) द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "डी०ए०वी० कालेज प्रबन्ध समिति" को कर-निर्धारण-वर्ष 1984-85 से 1986-87 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 6325/फा०सं० 197/81/83-आ०क०(नि-1)]

पी० सक्सेना, उप सचिव

S.O. 4253.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "D.A.V. College Managing Committee" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1984-85 to 1986-87.

[No. 6325/F. No. 197/81/83-IT(AI)]

P. SAXENA, Dy. Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1985

का.आ. 4254—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और उपधारा (2) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एस. एस० नादकर्णी को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त करती है।

[सं. एफ. 7/16/85-बी.ओ. I (I)]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 29th August, 1985

S.O. 4254.—In pursuance of clause (a) of sub-section (1) and of sub-section (2) of section 6 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964), the Central Government hereby appoints Shri S. S. Nadkarni as the Managing Director of the Industrial Development Bank of India for a period of three years with effect from the date of his taking charge.

[No. F. 7/16/85-BO.I(1)]

का.आ. 4255—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री एस. एस. नादकर्णी को उस तारीख से जिस तारीख से उन्होंने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रबंध निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के निदेशक मण्डल का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[सं. एफ. 7/16/85-बी.ओ. 1(2)]

S.O. 4255.—In pursuance of clause (a) of sub-section (1) of section 6 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964), the Central Government hereby appoints Shri S. S. Nadkarni, who has been appointed as the Managing Director of the Industrial Development Bank of India, to be the Chairman of the Board of Directors of the Industrial Development Bank of India with effect from the date of his taking charge as Managing Director of Industrial Development Bank of India.

[No. F. 7/16/85-BO.I(2)]

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1985

का. आ. 4256—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड 8 के उपखंड (1) के साथ पठित खंड 3 के उपखंड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् श्री आर. श्रीनिवासन को 6 सितम्बर, 1985 से आरम्भ होने वाली और 5 सितम्बर, 1988 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इलाहाबाद बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करती है।

[सं. एफ. 9/41/85-बी. ओ. 1(1)]

(Banking Division)

New Delhi, the 30th August, 1985

S.O. 4256.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3 read with sub-clause (1) of clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby re-appoints Shri R. Srinivasan as the Managing Director, of Allahabad Bank for a period commencing on September 6, 1985 and ending with September 5, 1988.

[No. F. 9/41/85-BO.I(-)]

का. आ. 4257—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड 7 के साथ पठित खंड 5 के उपखंड (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् श्री आर. श्रीनिवासन को, जिन्हें 6 सितम्बर, 1985 से इलाहाबाद बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, उसी तारीख से इलाहाबाद बैंक के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. एफ. 9/41/85-बी. ओ. 1(2)]

एस. एस. हसूरकर, निदेशक

S.O. 4257.—In pursuance of sub-clause (1) of clause 5, read with clause 7, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government after consultation with the Reserve Bank of India, hereby, appoints Shri R. Srinivasan who has been re-appointed as Managing Director of Allahabad Bank with effect from September 6, 1985, to be the Chairman of the Board of Directors of Allahabad Bank with effect from the same date.

[No. F. 9/41/85-BO.I(2)]

S. S. HASURKAR, Director

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1985

आदेश

का. आ. 4258—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए वैक्युम फलास्क को निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लाने के लिए कतिपय प्रस्ताव के अलावा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना स. का. आ. 1616, तारीख 7 मई, 1968 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम–11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 963, तारीख 9 मार्च, 1985 के अधीन भारत के राजपत्र भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 9 मार्च, 1985 में प्रकाशित किए गए थे ;

और ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन से 45 दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 21 मार्च, 1985 को उपलब्ध करा दी गयी थी ;

उक्त प्रारूप प्रस्तावों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है ।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् अपनी यह राय होने पर कि भारत निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा–

2. (1) अधिसूचित करती है कि वैक्युम फलास्क का निर्यात से पुर्व क्वालिटी नियंत्रण निरीक्षण किया जाएगा ;

(2) वैक्युम फलास्क का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1985 के प्रारूप के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो ऐसी वैक्युम फलास्क पर निर्यात से पुर्व लागू होगा।

(3) निम्नलिखित को मान्यता देती है :—

(क) सुसंगत भारतीय मानकों या अन्य राष्ट्रीय मानकों को ;

(ख) इस बात के अधीन रहते हुए कि उत्पाद इस आदेश के उपाबंध में विनिर्दिष्ट न्युनतम विशेषताओं की पूर्ति करता है, संविदात्मक विनिर्देशों को ;

(ग) निर्यातकर्ता द्वारा निर्यातकर्ता और विदेशी क्रेता के बीच निर्यात संविदा के स्वीकृत विनिर्देशों के रूप में घोषित ऐसे विनिर्देशों को, ऐसी निर्यात संविदाओं के लिए जिनकी इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पुर्व पुष्टि हो गयी है तथा जिनका उस तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर निर्यात कर दिया गया है, वैक्युम फलास्क के लिए मानक विनिर्देशों के रूप मे मान्यता देती है ।

(4) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में ऐसे वैक्युम फलास्क के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित किसी निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि वैक्युम फलास्क निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1985 के अनुसार निर्यात योग्य है ।

2. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को को समुद्र, भूमि या वायु मार्ग द्वारा वैक्युम फलास्कों के नमुनों के निर्यात को लागू नहीं होगी जिनका पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य केवल 500/– रुपए से अधिक नहीं है ।

3. इस अधिसूचना में वैक्युम फलास्क से निम्नलिखित अभिप्रेत है :—

(1) कोई भी संयुक्त पात्र जिसमें बाहरी सुरक्षात्मक केस है और जिस पर संवरण की व्यवस्था है और उसे ले जाने के लिए उपयुक्त साधन हैं । बाहरी केस में दोहरे कांच की दीवारों वाला डांट सहित पात्र (जिसे रिफिल कहा जाता है) रखा जाएगा, जिसकी दीवारें रजतित होंगी और उनके बीच के स्थान को निर्वात रखा जाएगा जिससे कि उसमें रखे गए पदार्थों से कम से कम गर्मी बाहर जा सके या बाहर से अंदर आ सके ।

(2) उक्त वैक्युम फलास्कों के लिए निर्मित रिफिल ।

4. यह आदेश राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

उपाबंध

वैक्युम फलास्कों के लिए विनिर्देश :—

क. रिफिलों के लिए विनिर्देश :—

1. रिफिलों का आकार, आकृति और क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार होगी ।

2. रिफिल अच्छी प्रकार से अनील किए हुए कांच से बनी होगी।

3. सिल्वर प्लेटिंग एक सार होगी और पत्तकों से मुक्त होगी।

4. स्पेसर, यदि कोई हो, ढीली नहीं होगी।

5. रिफिल का तापीय प्रधान प्रतिरोध तभी पर्याप्त समझा जाएगा जब रिफिल को निम्नलिखित परीक्षण के करने पर कोई हानि न हो :

रिफिल की गर्दन तक 27° सेंटीग्रेड ± 2° सेंटीग्रेड पर पानी डालें और 3 मिनट तक रखें। रिफिल को खाली करें और उबलता हुआ पानी तुरन्त डालें तथा 3 मिनट तक रखें। रिफिल खाली करें और 27° सेंटीग्रेड ± 2° सेंटीग्रेड पर पानी तुरन्त डालें तथा 3 मिनट के लिए रखें। पानी अंदर और बाहर निकालने की क्रिया में प्रत्येक बारी में 15 सेकेंड से अधिक समय नहीं होगा।

6. उष्मा धारण क्षमता का निम्नलिखित रूप से परीक्षण किया जाएगा :—

05 सेंटीग्रेड पर गरम किए गए पानी का तापमान जब वह नीचे विनिर्दिष्ट रीति से रिफिल में रखा जाए तो नीचे उपदर्शित से कम नहीं होगा :—

रिफिल का प्रकार	प्राप्त तापमान कम नहीं होगा		पांच घंटों के परीक्षण के पश्चात स्तम्भ (2) से हर तीसरा
	एक घंटे के परीक्षण के पश्चात	24 घंटे के परीक्षण के पश्चात	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. 750 मि. लीटर से अधिक अंकित धारित का संकीर्ण मुख (आंतरिक मुख का व्यास 45 मि. मी.) तक होगा।	91° सेंटीग्रेड	50° सेंटीग्रेड	78° सेंटीग्रेड
2. 750 मि. मी. से ऊपर किन्तु 250 मि. मी. से कम अंकित धारित का संकीर्ण मुख	88° सेंटीग्रेड	42° सेंटीग्रेड	70° सेंटीग्रेड
3. 1/2 लीटर तथा अधिक अंकित धारिता का चौड़ा मुख (आंतरिक मुख का व्यास 45 मि. मी. से अधिक होगा)	85° सेंटीग्रेड	42° सेंटीग्रेड	70° सेंटीग्रेड
4. 20 मि. मी. अंकित धारिता आंतरिक मुख का व्यास 30 मि. मी. तक होगा	88° सेंटीग्रेड	40° सेंटीग्रेड	70° सेंटीग्रेड
5. 250 मि. मी. अंकित धारिता (आंतरिक मुख का व्यास 30 मि. मी. से ऊपर किन्तु 45 मि. मी. से कम होगा)।	85° सेंटीग्रेड	38° सेंटीग्रेड	68° सेंटीग्रेड
6. अन्य प्रकार के रिफिल जो गिलास, बर्फ के कटोरे आदि के रूप में प्रयोग के लिए आशयित है।	निर्यातकर्ता द्वारा घोषित के अनुसार		

प्रक्रिया :—उबलते हुए जल में रिफिल खंगलें, जहां तक संभव हो अधिक से अधिक जल निकाल लें। शीघ्र ही 95° सेंटीग्रेड पर पानी इसके गले तक भर दें। डाट से मुंह बंद कर दें और समय नोट कर लें।

7. मुख तक धारिता : जब तक क्रेता और प्रदायकर्ता के बीच अन्यथा करार न हो तत्स्थानी अंकित धारिता वाले रिफिलों की मुख तक धारिता निम्नलिखित अनुसार होगी :—

साधारण धारिता	मुख तक धारिता
मि. लीटर	मि. लीटर
250	260 ± 30
500	510 ± 60
750	770 ± 60
1000	1020 ± 60
1350	1380 ± 100
1500	1530 ± 100
1750	1780 ± 125
2750	2780 ± 150

7.1 उपरोक्त वर्णित आवश्यक सहायताओं सहित आकारों की मुख तक धारिता निर्यातकर्ता और विदेशी क्रेता के बीच हुए करार के अनुसार होगी।

. वैक्युम फ्लास्क के अन्य संघटकों के लिए विनिर्देश।

8.1 सामग्री

(क) बाहरी सुरक्षात्मक केस और उप साधन बाहरी सुरक्षात्मक केस और उपसाधन ऐसी सामग्री से बने होंगे जो उपयोग की स्थिति में रिफिल को सुरक्षित रखने के लिये पर्याप्त रूप से पक्की हो और साधारण उठाई-धराई में नुकसान से इसे बचा सकें।

(ख) रिफिल का डाट अविषैला, जंगरोधी और टिकाऊ होगा। जब रिफिल में फिट किया जाए तो यह फिसलेगा नहीं और उसकी रिसाव रोधी फिटिंग होगी।

(ग) पेय कप के रूप में प्रयोग के लिए आशयित सहायक संघटक अविषैले जंगरोधी होंगे और प्रयोग की सामान्य स्थिति में विकृत नहीं होंगे।

(घ) वैक्यूम फ्लास्क का बाहरी सुरक्षात्मक केस, सहायक संवरण और अन्य संघटक क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार होंगे ।

(ङ) टिन प्लेट की मोटाई क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार होगी, तथापि निर्यात संविदा में किसी भी अनुबंध की अनुपस्थिति मे 1/2 लीटर वैक्यूम फ्लास्क के मामले मे टिन प्लेट की मोटाई 0.27 मि. मी. से कम नही होगी ।

8.2 कारीगरी और फिनिश

(क) बाहरी सुरक्षात्मक केस आधार और गले पर उपयुक्त सहायक संघटकों द्वारा रिफिल को सुरक्षित रखेगा ।

(ख) रिफिल की गर्दन को धारण करने वाले संघटक इस प्रकार से डिजाइन किये जाएगें कि वे सुरक्षात्मक केस और रिफिल के बीच के खाली स्थान में तरल पदार्थ को जाने से रोक सकें ।

(ग) सुरक्षात्मक केस का रिंग और तली यदि टिन की बनी है तो दोनों ओर से लैकर किया जाएगा और बांडी को अंदर की ओर से लैकर केवल जंग से बचाने के लिये किया जाएगा । बाहरी सजावट को बचाने के लिए डिब्बे को भली प्रकार से पेन्ट और वार्निश किया जाएगा ।

टिप्पण :— सुरक्षात्मक केस टिन प्लेट से भिन्न सामग्री से भी बनाया जा सकता है परन्तु यह तब जब कि वह ऊपर वर्णित अपेक्षाओं को पूरा करता हो ।

(घ) निलम्बन के लिए उचित हैंडिल या व्यवस्था वैक्यूम फ्लास्क पर की जा सकती है ।

(छ) सजावट पर आपत्तिजनक कोई भी दरारें नहीं होगी ।

(च) वैक्यूम फ्लास्क का आधार स्थायी होगा ताकि उसे लुढ़कने से बचाया जा सके ।

8.3 रिसाव रोध :

"दबाने" और "घुमाने" दोनों प्रकार के डाट पात्र की गर्दन पर कसकर-फिट किये गए होने चाहिए जिससे कि वह रिसाव रोधी हो जाए ।

ठंडे पानी से आधे भरे हुए रिफिल और डाट लगे हुए तैयार वैक्यूम प्लास्कों से जब उन्हें एक मिनट के लिए भली प्रकार से उलटाया और हिलाया जाए तो उससे पानी का रिसाव नहीं होगा ।

[फाइल नं. 6(29)/79— ई आई एंड ईपी]

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 14th September, 1985

ORDER

S.O. 4258.—Whereas for the development of the export trade of India certain proposals for subjecting Vacuum Flasks to quality control and inspection prior to export in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 1616, dated the 7th May 1968, except as respects things done or omitted to be done, were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, in the Gazette of India, Part II-Section 3, Sub-section (ii), dated the 9th March, 1985, under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 963, dated the 9th March, 1985;

And whereas the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby within 45 days of the publication of the said Order in Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 31st March, 1985.

And whereas objections or suggestions have been received from the public on the said draft proposals and have been considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the export Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consultation with the Export Inspection Council, being of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby:—

(i) notifies that Vacuum Flasks shall be subject to quality control and inspection prior to export.

(ii) specifies the type of quality control and inspection in accordance with the draft Export of Vacuum Flasks (Quality Control and Inspection) Rules, 1985, as the type of quality control and inspection which shall be applied to such vacuum flasks prior to export;

(iii) recognises:—

(a) relevant Indian Standard or any other national standard;

(b) contractual specifications subject to the product specifying the minimum of the characteristics specified in Annexure to this order;

(c) the specifications declared by the exporter to be the agreed specifications of the export contract between theforeign buyer and the exporter, for such export contracts as are confirmed prior to the date of publication of this order in the Official Gazette and exported within a period of sixty days from this date; as the standard specifications for vacuum flasks.

(iv) prohibits the exports in the course of international trade of vacuum flasks unless the same is either accompanied by a certificate of inspection issued by any of the Export Inspection Agencies established under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), to the effect that the Vacuum Flasks are exportworthy in accordance with the Export of Vacum Flasks (Qualify Control and Inspection) Rules, 1985.

2. Nothing in this order shall apply to the export by sea, land or air of samples of vacuum flasks not exceeding Rs. 500.00 only in Free on Board value to the prospective buyers.

3. In this notification, 'Vacuum Flasks' means:—

(i) Any composite container consisting of an outer protective case provided with a closure and suitable means for its carrying. The outer case shall house a stoppered double walls silvered and the space in between maintained under vacuum to reduce to a minimum the transfer of heat to and from the contents placed in it.

(ii) Refills meant for the said vacuum flasks.

4. This order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

ANNEXURE

'SPECIFICATIONS FOR VACUUM FLASKS'

A. Specifications for refills

1. The size, shape and the capacity of the refills shall be as agreed to between the buyer and the seller.

2. The refills shall be made of well annealedglass.

3. The silvering shall be uniform and free from flakes.

4. The spacers, if any, shall not be loose.

5. The thermal shock resistance of the refill shall be considered adequate if the refill suffers no damage when subjected to the following test :

Pour water at 27°C ± 2°C upto the neck of the refills and allow to stand for 3 minutes. Empty the refil and pour boiling water immediately and allow to stand for 3 minutes. Empty the refill and pour water at 27°C ± 2°C immediately and allow to stand for 3 minutes. The time for pouring water in and out shall not exceed 15 seconds in each case.

6. The heat retention capacity shall be tested as follows:—

The temperature of water heated to 95°C and when kept in refill in the manner specified below shall not be less than those indicated below:—

Type of Refills	Temperature attained not less than		After five Hours Test Alternative to Column (2)
	After one Hour Test	After 24 Hours Test	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Narrow mouth of nominal capacity higher than 750 ml (internal mouth diametre upto 45 mm)	91°C	50°C	78°C
2. Narrow mouth of nominal capacity higher than 250 ml but less than 750 ml	88°C	42°C	70°C
3. Wide mouth of nominal capacity 1/2 litre and above (internal mouth diameter above 45 mm)	85°C	42°C	70°C
4. 250 ml. nominal capacity (internal mouth diameter upto 30 mm)	88°C	40°C	70°C
5. 250 ml. nominal capacity (internal mouth diameter above 30 mm but below 45 mm)	85°C	38°C	68°C
6. Other types of refills meant for use as tumblers, ice bowls etc.	As declared by the exporters		

PROCEDURE : Rinse the refills with boiling water, draining out as much of water as possible. Quickly fill it up to the neck with water at 95°C, close the mouth with stopper and note the time.

7. Brimful capacities — Unless otherwise agreed to between the purchaser and the supplier, brimful capacities of refills of corresponding nominal capacities shall be as follows :—

Nominal Capacity	Brimful Capacity
ml	ml
250	260±30
500	510±60
750	770±60
1000	1020±60
1350	1380±100
1500	1530±100
1750	1780±125
2750	2780±150

7.1 The brimful capacity of sizes along with necessary tolerances other than mentioned above shall be as agreed to between the exporter and foreign buyer.

8. Specification for the other components of Vacuum Flasks.

8.1 Materials

(a) Outer Protective case and Accessories — Outer protective cases and accessories shall be of materials which shall be rigid enough to hold the refil security under conditions of use and protect it from damage in normal handling.

(b) The stopper of the refill shall be non-toxic, corrosion resistant and durable. When fitted to the refill it shall not slip off and shall provide a leak-resistant fitting.

(c) The auxilliary closure(s), also intended or use as drinking cup(s) shall be non-toxic, corrosion-resistant and shall not deform under normal conditions of use.

(d) The outer protective case, auxillary closures and other components of vacuum flasks shall be as agreed to between the buyer and seller.

(e) The thickness of the tin plate shall be as agreed between the foreign buyer and the exporter. However, in the absence of any stipulation in the export contract, the thickness of tin plate shall not be less than 0.27 mm in case of 1|2 litre vacuum flasks.

8.2 Workmanship and Finish

(a) The outer protection case shall hold the refill securely by suitable supporting components at the base and the neck.

(b) The component holding the back of the refill shall be so designed as to prevent entry of any liquid into the space in between the protective case and the refill.

(c) The ring and bottom of the protective case if made out of tin shall be lacquered on both sides and the body lacquered on the inside only for protection against corrosion. The body shall be suitably painted and varnished to protect the outside decoration.

NOTE : The protective case may also be made of matreials other than tin plate provided they satisfy the requirements mentioned above.

(d) Suitable handle or arrangement for suspension may be provided on a vacuum flask.

(e) There shall be no objectionable scratches on the decoration.

(f) The base of vacuum flasks shall be stable so as to prevent tipping.

8.3 Leak Resistance:—

The stopper both 'push in' type and the 'screw on' type should fit snugly in the neck of the container so that it shall be leak resistant.

Assembled vacuum flask with refill half-filled with cold water and stoppered, when shaken well for one minute, shall not show any leakage of water.

[F. No. 6(29)|79-EI&EP]

का. आ. 4259:—केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :— 1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम वैक्यूम फलास्क का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण) और निरीक्षण) नियम, 1985 है ।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) 'अधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है ;

(ख) 'अभिकरण' से अधिनियम की धारा 7 के अधीन स्थापित कोई निर्यात निरीक्षण अधिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) 'परिषद' से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है ;

(घ) वैक्यूम फलास्क से निम्नलिखित अभिप्रेत है :—

(i) कोई भी संयक्त पात्र जिसमें बहारी सुरक्षात्मक कैस है और जिस पर संवरण की व्यवस्था है और उसे ले जाने के लिए उपयुक्त साधन है। बाहरी कैस में दोहरी कांच की दीवार वाला डॉट सहित पात्र (जिसे रिफिल कहा जाता है) रखा जाएगा, जिसकी दीवारें रजतित होंगी और उनके बीच के स्थान को निर्वात रखा जाएगा जिससे की उसमें रखे गए पदार्थों से कम से कम गर्मी बाहर जा सके या बाहर से अंदर आ सके ।

(ii) उक्त वैक्यूम फलासकों के लिए रिफिल ।

3. निरीक्षण का आधार :— वैक्यूम फलास्क का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जाएगा कि उसकी क्वालिटी केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है, अर्थात :—

(क) सुसंगत भारतीय मानक या अन्य राष्ट्रीय मानक,

(ख) इस बात के अधीन रहते हुए कि उत्पाद इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन जारी किए गए इस आदेश के उपाबंध में विनिर्दिष्ट न्यूनतम विशेषताओं की पूर्ति करता है, संविदात्मक विनिर्देशों को ;

(ग) निर्यातकर्ता द्वारा निर्यातकर्ता और विदेशी क्रेता के बीच निर्यात संविदा के स्वीकृत विनिर्देशों के रूप में घोषित ऐसे विनिर्देशों को ऐसी निर्यात संविदाओं के लिए जिनकी इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पूर्व पुष्टि हो गई है तथा जिन का इस तारीख से आठ दिन की अवधि के भीतर निर्यात कर दिया गया है वैक्यूम फ्लास्क के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देता है ।

या

(क) यह सुनिश्चित करके किया जाएगा कि उत्पादों का विनिर्माण उपबंध (क) में यथा विनिर्दिष्ट उत्पादन के दौरान आवश्यक क्वलिटी नियंत्रण का प्रयोग करके किया गया है ।

या

(ख) उपाबंध (ख) में विनिर्दिष्ट ढंग से किए गए निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर किया गया है ।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :— (1) वैक्यूम फलास्क रिफिलों के परेषण का निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता निर्यात संविदा या आदेश या प्रत्यय-पत्र की एक प्रति के साथ संविदात्मक विनिर्देशों का ब्यौरा देते हुए अभिकरण को लिखित सूचना देगा जिससे अभिकरण नियम 3 के अनुसार निरीक्षण कर सके।

(2) ऐसे वैक्यूम फलास्कों/रिफिलों के निर्यात के लिए जिनका उपाबंध "क" में अधिकथित उत्पादन के दौरान पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करके विनिर्माण किया गया है और अभिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञों के पैनल द्वारा विनिर्माण यूनिट के बारे में जो यह न्याय निर्णित किया गया कि उसमें उत्पादन के दौरान पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण ब्रिलें है, तो निर्यातकर्ता उपनियम (1) में वर्णित सूचना के साथ यह घोषणा भी प्रस्तुत करेगा कि निर्यात के आशयित व्यवस्थिति वैक्यूम फलास्कों/रिफ़िलों के परेषण का विनिर्माण उपाबंध "क" में अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग करके किया गया है और परेषण इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है ।

(3) निर्यातकर्ता अभिकरण के निर्यात किए जाने वाले परेषण पर लगाये जाने वाला पहचान चिन्ह भी होगा ।

(4) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना विनिर्माण के परिसर से परेषण के भेजे जाने से कम से कम सात दिन पूर्व दी जाती है । उपनियम (2) के अधीन घोषण सहित सूचना विनिर्माता के परिसर से परेषण के भेजे जाने के कम से कम तीन दिन पूर्व दी जाएगी ।

(5) उपनियम (1) के अधीन सूचना और उपनियम (2) के अधीन घोषणा यदि कोई हो प्राप्त होने पर अभिकरण:-

क(i) अपना यह समाधान करने लेने पर कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान विनिर्माता के उपबंध "क" में

अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग किया है और इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप उत्पाद का विनिर्माण करने के संबंध में अभिकरण या परिषद द्वारा जारी किए गए अनुदेशों, यदि कोई हो, का पालन किया है, तीन दिन की अवधि के भीतर यह घोषणा करने वाला प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि वैक्यूम फ्लास्कों/रिफ़िलों का परेषण निर्यात योग्य है ;

(ii) उन दशाओं में जहां विनिर्माता निर्यातकर्ता नहीं है, वहां परेषण का भौतिक रूप से सत्यापन किया जाएगा और ऐसा सत्यापन तथा निरीक्षण जो आवश्यक हो, अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि उपरोक्त शर्तों का पालन किया गया है ;

(iii) अभिकरण निर्यात के लिए आशयित कुछ परेषणों की स्थल पर जांच करेगा और यूनिट द्वारा अपनाई गई उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण ड्रिलों की पर्याप्तता के अनुरक्षण का सत्यापन करने के लिए नियमित अंतरालों पर यूनिटों में भी जाएगा ;

(iv) यदि यह पाया जाता है कि विनिर्माण यूनिट विनिर्माण के किसी भी प्रक्रम पर अपेक्षित क्वालिटी नियंत्रण उपायों का प्रयोग नहीं करता है या परिषद और अभिकरण की सिफ़ारिशों का पालन नहीं करता है तो यह घोषित किया जाएगा कि यूनिट के पास उत्पादन के दौरान पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण ड्रिले नहीं है। ऐसी दशाओं में यदि यूनिट चाहे तो वह उत्पादन के दौरान पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण ड्रिलों की पर्याप्तता के अनुरक्षण के न्याय निर्णयन के लिए नए सिरे से आवेदन करेगा ।

(ख) उस दशा में जहां निर्यातकर्ता ने उपनियम (2) के अधीन यह घोषित नहीं किया है कि उपबंध "क" में अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग किया गया है वहां उपबंध "ख" में अधिकथित निरीक्षण/परीक्षण के आधार पर या दोनों के आधार अपना यह समाधान कर लेने पर कि वैक्यूम फ्लास्कों/रिफ़िलों का परेषण इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है, ऐसा निरीक्षण करने के सात दिन के भीतर यह घोषणा करने वाला प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि फ्लास्कों/रिफ़िलों का परेषण निर्यात योग्य है :

परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार का समाधान नहीं होता है, वहां वह निर्यातकर्ता को, यह घोषणा करने वाला प्रमाण-पत्र कि वैक्यूम फ्लास्कों/रिफिलों का परेषण निर्यात योग्य है, जारी करने से इंकार कर देगा और ऐसे इंकार की सूचना सात दिन के भीतर उसके कारणों सहित निर्यातकर्ता को देगा ।

(ग) (i) उस दशा में जहां विनिर्माता उपनियम (5) (क) के अधीन निर्यातकर्ता नहीं है या परेषण का निरीक्षण उपनियम (5) (ख) के अधीन किया जाता है, वहां अभिकरण निरीक्षण की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् परेषण में पैकेजों को यह सुनिश्चित करने के लिए इस रीति से मुहरबंद करेगा कि मुहरबंद पैकेजों के साथ छेड़-छाड़ नहीं की जा सकती ;

(ii) परेषण के नामंजूर किए जाने की दशा में यदि निर्यातकर्ता ऐसा चाहे तो परेषण अभिकरण द्वारा मुहरबंद नहीं किया जाएगा, किन्तु ऐसे मामलों में निर्यातकर्ता नामंजुरी के विरुद्ध अपील करने का हकदार नहीं होगा ।

5. निरीक्षण का स्थान :—इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षण या तो—(क) ऐसे उत्पादों के विनिर्माता के परिसर पर, या (ख) उस परिसर पर जहां निर्यातकर्ता द्वारा माल प्रस्तुत किया जाता है, किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि वहां निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हों ।

6. निरीक्षण फीस :—निर्यातकर्ता अभिकरण को निरीक्षण फीस निम्नलिखित के अनुसार देगा :—

(i) (क) उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण स्कीम के अधीन निर्यात करने के लिए प्रति परेषण कम से कम 20/– रु० के अधीन रहते हुए, पोत-पर्यन्त-निःशुल्क मूल्य के 0.2 प्रतिशत की दर से ।

(ख) परेषणानुसार निरीक्षण के अधीन निर्यात के लिए प्रति परेषण कम से कम 20/– रु० के अधीन रहते हुए पोत-पर्यन्त-निःशुल्क मूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर से ।

(ii) उन विनिर्माताओं/निर्यातकर्ताओं के लिए जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संबंधित सरकारों के पास लघु उद्योग एककों के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, प्रति परेषण कम से कम 20/– रु० के अधीन रहते हुए दर क्रमशः (क) और (ख) के लिए 0.18 प्रतिशत और 0.36 प्रतिशत होगी।

7. अपील :— (1) नियम 4 के उपनियम (5) के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र देने से इंकार किए जाने से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने से दस दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात व्यक्तियों को अपील कर सकता है।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्य संख्या में कम से कम दो–तिहाई सदस्य गैर-सरकारी होंगे ।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी ।

(4) अपील प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी ।

परिशिष्ट (क)

[नियम 3 (क) देखिए]

क्वालिटी नियंत्रण :—

वैक्यूम फ्लास्कों/रिफिलों का क्वालिटी नियंत्रण विनिर्माता द्वारा इससे संलग्न अनुसूची में दिए गए नियंत्रणों के स्तरों सहित नीचे अधिकथित उत्पादों के विनिर्माण, परिरक्षण

और पैकिंग के विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित नियंत्रणों का प्रयोग करके सुनिश्चित किया जाएगा :—

(i) क्रय विनिर्देश और कच्ची सामग्री नियंत्रण :—

(क) प्रयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री के गुण समाविष्ट करते हुए, क्रय विनिर्देश विनिर्माता द्वारा अधिकथित किए जाएंगे।

(ख) स्वीकृत परेषण के साथ क्रय विनिर्देशों की अपेक्षाओं की संपुष्टि करते हुए या तो प्रदायकर्ता का परीक्षण या निरीक्षण प्रमाण-पत्र होगा जिस दशा में क्रेता द्वारा किसी विशेष प्रदायकर्ता के 10 परेषणों में से कम से कम एक की एक बार कालिक जांच पूर्वोक्त परीक्षण या निरीक्षण प्रमाण-पत्रों की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए की जाएगी या क्रय की गई सामग्री का या तो कारखानों की प्रयोगशाला में किसी बाहरी प्रयोगशाला या परीक्षण गृहों में परीक्षण या निरीक्षण किया जाएगा।

(ग) निरीक्षण या परीक्षण के लिए नमूनों का लिया जाना लेखबद्ध अन्वेषण पर आधारित होगा।

(घ) निरीक्षण या परीक्षण किए जाने के पश्चात् स्वीकृत और अस्वीकृत माल के पृथक करण के लिए अस्वीकृत सामग्री का निपटान करने के लिए व्यवस्थित पद्धतियां अपनाई जाएगी।

(ङ) उपरोक्त नियंत्रणों के संबंध में विनिर्माता द्वारा अभिलेख नियमित और व्यवस्थित ढंग से रखे जाएंगे।

(ii) प्रक्रिया नियंत्रण :—(क) विनिर्माता द्वारा विनिर्माण के विभिन्न प्रक्रमों के लिए ब्यौरेवार प्रक्रिया विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे।

(ख) प्रक्रिया विनिर्देशों में अधिकथित प्रक्रियाओं के नियंत्रण के लिए उपकरण और उपस्कर सुविधाएं होंगी।

(ग) विनिर्माता द्वारा विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त नियंत्रणों का सत्यापन करने की संभावना को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे।

(iii) उत्पाद नियंत्रण :—

(क) विनिर्माता के पास यह जांच करने के लिए कि उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है या तो अपनी परीक्षण सुविधाएं होंगी या उसकी पहुंच वहां तक होगी जहां ऐसी परीक्षण सुविधाएं विद्यमान हों।

(ख) परीक्षण या निरीक्षण करने के लिए नमूनों का लिया जाना लेखबद्ध अन्वेषणों पर आधारित होगा।

(ग) परीक्षण के लिए नमूने लेने और किए गए निरीक्षण के बारे में पर्याप्त अभिलेख नियमित और व्यवस्थित रूप से रखे जाएंगे।

(घ) उत्पादों की जांच करने के लिए नियंत्रण के न्यूनतम स्तर इससे उपाबंध अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

(iv) परिरक्षण नियंत्रण :—उत्पाद का भंडारकरण और अभिवहन दोनों के दौरान अच्छी तरह से परिरक्षित किया जाएगा।

(v) पैकिंग नियंत्रण :—पैकेज देखने में सुन्दर होंगे और अभिवहन के दौरान उठाई-धराई सहन करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत होंगे।

अनुसूची

नियंत्रण के स्तर

क्रम सं. अपेक्षाएं	संदर्भ	नमूनों की सं.	आवृत्ति	टिप्पणी
(क) रिफिलों के लिए विनिर्देश :—				
1. चाक्षुष विशेषताएं	इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार	सभी	—	—
2. अर्न लन	इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार	30 मिनट के उत्पादन 5 टुकड़े	—	—
3. परिमाप अपेक्षाएं आवृत्ति और आकार आदि	—यथोक्त—	सारणी II में दिए गए उपाबंध के अनुसार	प्रत्येक पारी का उत्पादन	—
4. क्षमता	—यथोक्त—	1%	—यथोक्त—	—
5. तापीय प्रघात	—यथोक्त—	1%	—यथोक्त—	—
6. उष्मा प्रतिधारण परीक्षण	—यथोक्त—	सभी	—यथोक्त—	—
7. क्षारीयता परीक्षण	—यथोक्त—	1	प्रत्येक पारी का उत्पादन	—

क्रम सं.	अपेक्षाएं	संदर्भ	नमूनों के सं.	आवृत्ति	टिप्पण
(ख)	वैक्यूम फ्लास्कों के अन्य संघटकों के लिए विनिर्देश :—				
1.	चाक्षुष विशेषताएं जिनके अंतर्गत संघटकों और डाटों के फिटिंग हैं ।	इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक सभ विनिर्देशों के अनुसार		प्रत्येक पारे का उत्पादन	--
2.	संघटकों के विमाएं	यथोक्त	10%	यथोक्त	—
3.	पालिश करना, वार्निश करना, लेकर करना	यथोक्त	10%	यथोक्त	--
4.	आपत्तिजनक खरोचों का अवरोध	यथोक्त	10%	यथोक्त	--
5.	खाद्य उत्पादों के विषाक्तता का अवरोध	यथोक्त	—	तीन मास में एक बार प्रदायकर्ता का प्रमाण-पत्र	—
6.	रिसाव परीक्षण	यथोक्त	1%	--	—

परिशिष्ट ख

(नियम—3 (ख) देखें)

1. परीक्षणानुसार निरीक्षण :—

1.1 वैक्यूम फ्लास्कों या रिफिलों के परीक्षण का निरीक्षण और परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप हैं ।

1.2 संविदात्मक विनिर्देशों में नमूना मानदंड की बाबत विनिर्दिष्ट अनुबंध के अभाव में नीचे दी गई सारणी-I में यथा अधिकथित लागू होंगे ।

सारणी-I

नमूना मानदंड

लॉट में डिब्बों की संख्या	चुने गए डिब्बों की संख्या
10 तक	2
11 से 50	5
51 से 200	10
201 से 500	15
501 से 1000	20
1001 और अधिक	25

लॉट:—एक परेषण में एक ही प्रकार और धारिता तथा समान परिस्थितियों के अधीन विनिर्दिष्ट एकत्रित सभी वैक्यूम फ्लास्क या रिफिल एक लॉट होंगे।

1.3 उपरोक्त सारणी-I के अनुसार सहसा चुने गए प्रत्येक डिब्बे में से सारणी-II के अनुसार प्रत्येक डिब्बे में से सहसा चुने गए वैक्यूम फ्लास्कों/रिफिलों की लगभग समान संख्या चुनी होगी ।

सारणी-II

लॉट आकार	चाक्षुष अपेक्षाएं			रिसावरोध उष्माप्रतिधारण और तापीय प्रघात परीक्षण	
	नमूना आकार	स्वीकृत सं०	अस्वीकृत सं०	नमूना आकार	स्वीकृति सं०
1	2	3	4	5	6
500 तक	20	1	4	5	0
501 से 1000	32	2	5	8	0
2001 से 3000	50	3	7	13	0
3001 से 10000	80	5	9	20	1
10001 से 35000	125	7	11	32	2
35001 और अधिक	200	11	16	50	3

2. परीक्षणों की संख्या और अनुरूपता के लिए मानदंड

2.1 सारणी-II के स्तम्भ-2 के अनुसार नमूने के लिए फ्लास्कों/रिफिलों की संख्या का चाक्षुष अपेक्षाओं के लिए परीक्षण किया जाएगा । ऐसी किसी भी अपेक्षा को पूरा न करने वाली प्रत्येक फ्लास्क/रिफिलों को दोषपूर्ण माना जाएगा ।

2.2 यह माना जाएगा कि लॉट इन अपेक्षाओं को संतोषजनक रूप से पूरा करता है यदि नमूनों में त्रुटि की संख्या सारणी-II के स्तम्भ 3 में दी गई तत्स्थानी स्वीकृति संख्या से कम या बराबर है ।

2.3 लॉट को संतोषजनक पाए जाने पर उसकी रिसाव रोधन, उष्मारोधन, तापीय प्रघात और क्षमता के लिए जांच की जाएगी । इस प्रयोजन के लिए फ्लास्कों/रिफिलों की आवश्यक संख्या उनमें से ली जाएगी जो पहले जांच करने संतोषजनक पाए गए हैं ।

2.4 रिसाव रोधन की जांच के लिए जाने वाले वैक्यूम फ्लास्कों की संख्या सारणी-II के स्तम्भ 5 के अनुसार होगी । यह माना जाएगा कि लॉट रिसाव रोधन की अपेक्षा को संतोषजनक रूप से पूरा करता है यदि नमूने में त्रुटियों की संख्या सारणी-II की स्तम्भ 6 में दी गई तत्स्थानी स्वीकृत संख्या से कम या बराबर है ।

2.5 ऊष्मा प्रतिधारण की जांच के लिए जाने वाले रिफिलों की संख्या सारणी-II के स्तम्भ 5 के अनुसार होगी। यह माना जाएगा कि लाट तापीय प्रघात अपेक्षा को संतोषजनक रूप से पूरा करता है यदि नमूने में त्रुटियों की संख्या सारणी-II के स्तम्भ में दी गई है तत्स्थानी स्वीकृत संख्या से कम या बराबर है ।

2.6 तापीय प्रघात की जांच के लिए जाने वाले रिफिलों की संख्या सारणी-II के स्तम्भ 5 के अनुसार होगी । यह माना जाएगा कि लॉट तापीय प्रघात की अपेक्षाओं को संतोषजनक रूप से पूरा करता है यदि नमूने में त्रुटियों की संख्या सारणी-II के स्तम्भ 6 में दी गई तत्स्थानी स्वीकृत संख्या से कम या बराबर है ।

2.7 यह घोषित किया जाएगा कि लॉट इस विनिर्देश की अपेक्षाओं को पूरा करता है ।

[फाईल सं० 6(29)/79-ई आई एंड ई पी]

एन० एस० हरिहरन, निदेशक

S.O. 4259.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, hereby makes the following rules, namely :—

1. (1) Short title and commencement.—These rules may be called the Export of Vaccum Flasks (Quality Control and Inspection) Rules, 1985.

(2) The notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

(b) "Agency" means any one of the Export Inspection Agencies established under section 7 of the Act;

(c) "Council" means Export Inspection Council established under section 3 of the Act:

(d) Vacuum Flask means :—

(i) Any composite container consisting of an outer protective case provided with a closure and suitable means for its carrying. The other case shall house a stoppered double walled glass container (called the refill) with the walls silvered and the space in between maintained under vacuum to reduce to a minimum the transfer of heat to and from the contents placed in it.

(ii) refills meant for the said Vacuum Flasks;

3. Basis of Inspection.—Inspection of Vacuum Flasks shall be carried out with a view to ensure that the quality of the same conforms to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act, namely :—

(a) relevant Indian Standard or any other national standard;

(b) Contractual specifications subject to the product satisfying the minimum of the characteristics specified in Annexure to the order issued under section 6 of the Act;

(c) The specifications declared by the exporter to be the agreed specification of the export contract between the foreign buyer and the exporter, for such export contracts as are confirmed prior to the date of publication of the order in the Official Gazette and exported within a period of sixty days from that date; as the standard specifications for vacuum flasks.

either

(a) by ensuring that the products have been manufactured by exercising necessary inprocess quality control as specified in Appendix-A.

or

(b) on the basis of the inspection and testing carried out in the manner specified in Appendix-B.

4. Procedure of Inspection.—(1) An exporter intending to export a consignment of vacuum flasks/refills shall give an intimation in writing to the Agency furnishing therein details of the contractual specifications alongwith a copy of the export contract or order or letter of credit to enable the agency to carry out inspection in accordance with rule 3.

(2) For export of vacuum flasks/refills manufactured by exercising adequate inprocess quality control as laid down in Appendix 'A' and the manufacturing unit adjudged as having adequate inprocess quality control drills by the panel of Experts constituted by the Agency for this purpose, the exporter shall also submit alongwith the intimation mentioned in sub-rule (1) a declaration that the consignment of vacuum flasks or refills, as the case may be, intended for export has been manufactured by exercising adequate quality control as laid down in Appendix 'A' and that the consignment conforms to the standard specifications recognised for the purpose.

(3) The exporter shall furnish to the agency the indentification mark applied on the consignment to be exported.

(4) Every intimation under sub-rule (1) shall be given not less than seven days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises and the intimation alongwith the declaration under sub-rule (2) shall be given not less than three days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises.

(5) On receipt of the intimation under sub-rule (1) and the declaration, if any, under sub-rule (2), the agency :—

(a)(i) On satisfying itself that during the process of manufacture, the manufacturer had exercised adequate quality control as laid down in Appendix 'A' and followed the instractions, if any, issued by the Agency or Council in this regard to manufacture the product to conform to the standard specifications recognised for the purpose shall, within three days, issue a certificate declaring the consignment of vacuum flasks/refills as exportworthy;

(ii) In case where the manufacturer is not the exporter, however, the consignment shall be physically verified and such verification and inspection as is necessary shall be carried out by the Agency to ensure that the above conditions are complied with;

(iii) The Agency shall, however, conduct spot checks of some of the consignments meant for export and also visit the units at regular intervals to verify the maintenance of the adequacy of inprocess quality control drills adopted by the unit.

(iv) If the manufacturing unit is found not adopting the required quality control measures at any stage of manufacture or does not comply with the recommendation of the Council or Agency, the unit shall be declared as not having adequate inprocess quality control drills, and in such cases the unit if it so desires shall apply afresh for adjudgement of the maintenance of adequacy of inprocess quality control drills.

(b) In case where the exporter has not declared under sub-rule (2) that adequate quality control as laid down in Appendix 'A' had been exercised, on satisfying itself that the consignment of vacuum flasks|refills conform to the standard specifications recognised for the purpose, on the basis of inspection|testing carried out as laid down in Appendix 'B' or on the basis of both, shall within seven days of carrying out such inspection issue a certificate declaring the consignment of vacuum flasks/refills as exportworthy;

Provided that where the agency is not so satisfied, it shall refuse to issue a certificate to the exporter declaring the consignment of vacuum flasks/refills as exportworthy and shall communicate such refusal within seven days to the exporter alongwith the reasons therefor.

(c) (i) In case where the manufacturer is not the exporter under sub-rule (5) (a) or consignment is inspected under sub-rule (5)(b), the Agency shall immediately after completion of the inspection, seal the packages in the consignment in the manner so as to ensure that the sealed package cannot be tampered with.

(ii) In case of rejection of the consignment, if the exporter so desires the consignment may not be sealed by the Agency but in such cases, however, the exporter shall not be entitled to prefer any appeal against the rejection.

5. Place of Inspection.—Every inspection under these rules shall be carried out either (a) at the premises of the manufacturer of such product, or (b) at the premises at which the goods are offered by the exporter, provided adequate facilities for inspection exists therein.

6. Inspection Fee.—Inspection Fee shall be paid by the exporter to the Agency as under :—

(i) (a) For exports under inprocess quality control scheme at the rate of 0.2 per cent of the F.O.B. value subject to minimum of Rs. 20|- per consignment.

(b) For exports under consignmentwise inspection at the rate of 0.4 per cent of the F.O.B. value subject to a minimum of Rs. 20 per consignments.

(ii) Subject to minimum of Rs. 20 per consignment the rate shall be 0.18 per cent and 0.36 per cent for (a) and (b) respectively, for manufacturers/ exporters who are registered as Small Scale Manufacturing units with the concerned Government of State/ Union Territories.

7. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the Agency to issue a certificate under sub-rule (5) of rule 4, may within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a Panel of Exports consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by the Central Government.

(2) The Panel shall consist of atleast two thirds of non-officials of the total membership of the Panel of Exports.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within fifteen days of its receipt.

APPENDIX 'A'

[See Rule 3(a)]

Quality Control:

The Quality Control of the Vacuum Flasks|refills shall be ensured by the manufacturer by effecting the following controls of different stages of manufacture, preservation and packing of the products as laid down below together with levels of controls as set out in the schedule appended thereto;

(i) Purchase specifications and raw materials control.—

(a) Purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of raw materials to be used.

(b) Either the accepted consignments shall be accompanied by a supplier's test and inspection certificate corroborating the requirements of the purchase specifications, in which case occasional checks shall be conducted at least once in 10 consignments by the purchaser for a particular supplier to verify the correctness of the aforesaid test or inspection certificates of the purchased material shall be regularly tested and inspected either in the laboratory within the factory or in an outside laboratory or test houses.

(c) The sampling for inspection or test to be carried out shall be based on the recorded investigation.

(d) After the inspection or test is carried out, systematic methods shall be adopted in segreating the accepted and rejected materials and for disposal of the rejected materials.

(e) Adequate records in respect of the aforesaid controls shall be regularly and systematically maintained by the manufacturer.

(ii) Process Control.—(a) Detailed process specifications shall be laid down by the manufacturer for different stages of manufacture.

(b) Equipment and instrumentation facilities shall be adequate to control the process as laid down in the process specifications.

(c) Adequate records shall be maintained by the manufacturer to ensure the possibility of verifying the controls exercised during the process of the manufacture.

(iii) Product Control:—

(a) The manufacturer shall have either his own testing facilities or shall have access to such testing facilities existing elsewhere to check up whether the product conforms to specifications recognised under section 6 of the Act.

(b) Sampling for the test and inspection to be carried out shall be based on the recorded investigation.

(c) Adequate records in respect of sampling and test carried out shall be regularly and systematically maintained.

(d) The minimum levels of control to check the products shall be as specified in the schedule appended thereto.

(iv) Preservation Control.—The products shall be well preserved both during the storage and the transit.

(v) Packing Control.—The packages shall have a good presentability and sufficient strength to stand handling during transit.

THE SCHEDULE

LEVELS OF CONTROL

Sl. No.	Requirements	Reference	No. of samples	Frequency	Remarks
(a)	Specification for refills				
	(1) Visual characteristics	As per standard specifications recognised for purpose.	All	—	—
	(2) Annealing	As per standard specifications recognised for purpose	5 pcs. every 30 minutes production	—	—
	(3) Dimensional requirements shape and size etc.	-do-	As per Table II given in Annexure	Per shift production	—
	(4) Capacity	-do-	1%	-do-	—
	(5) Thermal shock	-do-	1%	-do-	—
	(6) Heat Retention Test	-do-	All	-do-	—
	(7) Alkalinity Test	-do-	1	Per day production	—
(B)	Specifications for the other components of Vacuum Flasks :—				
	(1) Visual Characteristics including fittings of components & stoppers.	-do-	All	Per shift's production	—
	(2) Dimensions of Components	-do-	10%	-do-	—
	(3) Polishing/Varnishing lacquoring	-do-	10%	-do-	—
	(4) Resistance to objectionable scretches	-do-	10%	-do-	—
	(5) Resistance to Toxicity on food products	-do-	—	Supplier's certificate once in 3 months	—
	(6) Leakage Test	-do-	1%	—	—

APPENDIX-B

[See Rule-(b)]

1. Consignmentwise inspection

1.1 The consignment of vacuum flasks or refills as the case may be shall be subjected to inspection and testing to ensure conformity of the consignment to the standard specification recognised under section 6 of the Act.

1.2 In the absence of specific stipulation in the contractual specifications as regards sampling criteria the same laid down in Table-I given below shall become applicable.

TABLE—I

SCALE OF SAMPLING

No. of cartons in the lot	No. of cartons to be selected
Upto 10	2
11 to 50	5
51 to 200	10
201 to 500	15
501 to 1000	20
1001 and above	25

LOT.—In a single consignment all the vacuum flasks or refills of the same type and capacity and manufactured under similar conditions shall be grouped together to constitute a lot.

1.3 From each of the cartons selected at random as per Table-I above, selected at random approximately equal number of pieces of vacuum flasks/refills from each of the cartons, in accordance with Table-II.

TABLE —II

Lot Size	Visual Requirements			Leak Proofness, Heat Retention and Thermal shock tests	
	Sample size	Acceptance No.	Rejection No.	Sample size	Acceptance No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Upto 500	20	1	4	5	0
501 to 1000	32	2	5	8	0
1001 to 3000	50	3	7	13	0
3001 to 10000	80	5	9	20	1
10001 to 35000	125	7	11	32	2
350001 and above	260	11	16	50	3

2. Number of tests and criteria for conformity.—

2.1 The number of flasks/refills given for the sample in column 2 of Table II shall be examined for visual requirements. A flask/refill failing in any of these requirements shall be considered as defective.

2.2 The lot shall be considered to have satisfied these requirements if the number of defectives found in the sample is less than or equal to the corresponding acceptance number given in column 3 of Table II.

2.3 The lot having been found satisfactory shall be simultaneously tested for leak-proofness, heat retention and thermal shock. For this purpose required number of flasks/refills shall be taken from those already examined and found satisfactory.

2.4 The number of vacuum flasks to be tested for leak-proofness shall be as given in Column 5 of Table II. The lot shall be considered to have satisfied the requirement of leak-proofness if the number of defectives found in the sample is less than or equal to be corresponding acceptance number given in Column 6 of Table II.

2.5 The number of refills to be tested for heat retention shall be as given in Column 5 of Table II. The lot shall be considered to have satisfied the requirement of heat retention if the number of defectives found in the sample is less than or equal to the corresspponding acceptable number given in column 6 of Table II.

2.6 The number or refills to be tested for thermal shock shall be as given in Column 5 of Table II. The lot shall be considered to have satisfied the requirement of thermal check if the number of defectives found in the sample is less than or equal to the corresponding acceptance number given in Column 6 of the Table II.

2.7 The lot shall be declared as conforming to the requirements of this specification.

[F. No. 6(29)/79-EI&FP]

N. S. HARIHARAN, Director

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1985

आदेश

का.आ. 4260:—डा. (श्रीमती) कंवल अग्रवाल, बी-1/28, अशोक विहार, फेज—2, नई दिल्ली—110052, को 54550 रु. मूल्य की वातानुकूलित ए एफ एफ एम रेडियो कैसेट स्टीरियो सहित 4 डुवर सीडन सिलिंडर, 1500 सी सी डीजेल आर एच डी स्टैण्डर्ड मॉडल वाली एक इसुजु जेमिनी आर-कार के आयात के लिए एक सीमाशुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/3051913, दिनांक 6-6-85 जारी किया गया था । आवेदक ने उपर्युक्त सीमशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट अस्थानस्त हो गया है । आगे यह भी बताया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकरण के पास पंजीकृत नहीं था जिससे कि सीमाशुल्क निकासी परमिट के मूल्य को बिल्कुल भी उपयोग में नही लाया गया है ।

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने उपयुक्त न्याय प्राधिकारी के सम्मुख विधिवत शपथ लेकर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । तदनुसार, मैं संतुष्ट हूं कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/3051913, दिनांक 6-6-85 आवेदक से खो गया है । समय-समय पर यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 के उप-खंड 9 (सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके हुए डा. (श्रीमती) कंवल अग्रवाल को जारी किया गया मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/3051913, दिनांक 6-6-85 एतद्द्वारा रद्द किया जाता है ।

3. सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है ।

[फा. सं. ए/ए-8/85-86/बी एल एस/1589]

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

New Delhi, the 23rd August, 1985

ORDER

S.O. 4260.—Dr. (Mrs.) Kanwal Agarwal, D-1/28, Ashok Vihar, Phase II, Delhi-110052 was granted a Customs Clearance Permit No. P/J/3051913 dt. 6-6-85 for the import of one No. Isuzu Gamini R-car 4-door Sedan cylinder 1500 cc diesel RHD standard model with air conditioner AFFM Radio Cassette Sterep valued at Rs. 54,550/-. The applicant has applied for issue of Duplicate copy of the above-mentioned Customs Clearance Permit on the ground that the original CCP has been misplaced. It has further been stated that the original CCP was not registered with any Customs Authority and as such the value of the CCP has not been utilised at all.

2. In support of his contention, the licensee has filed an affidavit duly sworn before appropriate judicial authority. I am accordingly satisfied that the original CCP No. P/J/3051913 dt. 6-6-85 has been lost by the applicant. In exercise of the powers conferred under Sub-Clause 9 (cc) of the Import (Control) Order, 1955 dt. 7-12-1955 as amended from time to time. The said original CCP No. P/J/3051913 dt. 6-6-85 issued to Dr. (Mrs.) Kanwal Agarwal is hereby cancelled.

3. A duplicate copy of the Cusoms Clearance Permit is being issued Separately.

[F. No. A/A-8/85-86/BLS/1589]

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1985

आदेश

का.आ. 4261:—श्रीमती प्रतिमा कैसवा, 28 रोहू इस क्रिसेन्ट, अप्पा लेजिज, नाइजीरिया को टोयटा कोरोला 1600 सी सी पेट्रोल कार का आयात करने के लिए 69,600/— रुपए मात्र का एक सीमाशुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/3052019 दिनांक 28-6-85 दिया गया था । आवेदक ने उपर्युक्त उल्लिखित सीमाशुल्क सीमा निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क परमिट अस्थानस्थ हो गया/खो गया है । आगे यह भी बताया गया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं किया गया था और इस प्रकार सीमाशुल्क निकासी परमिट के मूल्य का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है ।

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने उपयुक्त न्यायिक प्राधिकारी के सामने विधिवत शपथ लेकर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । मैं, तदनुसार, सन्तुष्ट हूं कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/3052019, दिनांक 28-6-85 आवेदक द्वारा खो गया है । समय-समय पर यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955, दिनांक 7-12-1955 की उपधारा 9 (सी सी) के अधीन

प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्रीमती प्रतिमा कैसवा को जारी किए गए मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट सं.पी/जे/3052019 दिनांक 28-6-85 को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है ।

3. सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति पार्टी को अलग से जारी की जा रही है ।

[फा. सं. ए/के–40/85–86/बी एल एस/1599]

एन. एस. कृष्णामूर्ति, उप-मुख्य नियंत्रक,
आयात-निर्यात,
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

New Delhi, the 26th August, 1985

ORDER

S.O. 4261.—Mrs. Pratima Kasewa, 28 Rhodes Cresent, Apapa Lagos, Nigeria, was granted a Customs Clearance Permit No. P/J/3052019 dt. 28-6-85 for Rs. 69,600/- only for import of Toyota Corolla 1600 cc Petrol car. The applicant has applied for issue of Duplicate copy of the above-mentioned Customs Clearance Permit on the ground that the original CCP has been misplaced/lost. It has further been stated that the original CCP was not registered with any Customs authority and as such the value of the CCP has not been utilised at all.

2. In support of his contention, the licensee has filed an affidavit duly sworn before appropriate judicial authority. I am accordingly satisfied that the original CCP No. P/J/3052019 dt. 28-6-85 has been lost by the applicant. In exercise of the powers conferred under Sub-Clause 9 (cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended from time to time, the said original CCP No. P/J/3052019 dt. 28-6-85 issued to Mrs. Pratima Kasewa is hereby cancelled.

3. A duplicate copy of the Customs Clearance Permit is being issued to the party separately.

[F. No. A/K-40/85-86/BLS/1599]
N. S. KRISHNAMURTHY, Dy. Chief Controller
of Imports & Exports.
for Chief Controller of Imports & Exports.

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1985

आदेश

का. आ. 4262.—मैसर्ज इलैक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग कं. लि. 136, जैसोर रोड़, कलकत्ता-700055 को मुक्त विदेशी मुद्रा के अधीन पूंजीगत माल का आयात करने के लिए 19,47,200/- रुपए (उन्नीस लाख सैंतालीस हजार और दो सौ रुपए मात्र) के लिए एक आयात लाइसेंस सं. पी/सी जी/ 2087187/सी/एक्स एक्स/ 87/एच/ 81/सी जी-1 दिनांक 16-6-83 दिया गया था ।

फर्म ने ऊपर उल्लिखित लाइसेंस की सीमाशुल्क/मुद्रा विनिमय प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति/मुद्रा विनिमय प्रयोजन प्रति खो गई या अस्थानस्थ हो गई है । आगे यह भी बताया गया है कि लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति/मुद्रा विनिमय प्रयोजन प्रति किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं थी और इस प्रकार सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के मूल्य का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है ।

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक, कलकत्ता के सम्मुख विधिवत शपथ लेकर स्टाम्प कागज पर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । मैं, तद्नुसार, सन्तुष्ट हूं कि आयात लाइसेंस सं. पी/जे/2087187 दिनांक 16-6-1983 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति/मुद्रा विनिमय प्रयोजन प्रति फर्म द्वारा खो गई है । यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7/12/1985 की उपधारा 9 (सी सी) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्ज इलैक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग कं. लि., कलकत्ता को जारी किए गए आयात लाइसेंस सं. पी/सी जी/ 2087187, दिनांक 16/6/1983 की उपर्युक्त मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति/मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है ।

3. उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति/मुद्रा विनिमय प्रयोजन प्रति की अनुलिपि 19,47,200/- रुपए (192,475 यू एस डालर) मूल्य के लिए पार्टी को अलग से जारी की जा रही है ।

[फाइल सं. सी जी-1/626/4/81-82/सी. जी./397]
पाल बैक, उपमुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

New Delhi, the 2nd September, 1985

S.O. 4262.—M/s. Electrical Manufacturing Co. Ltd., 136, Jessore Rd., Calcutta-700055 were granted an Import Licence No. P/CG/2081187/C/XX/87/II/81/CG. I, dated 16-6-83 for Rs. 19,47,200 (Rupees Nineteen Lakhs Forty Seven Thousand and Two Hundred only for import of Capital Goods under Free Foreign Exchange.

The firm has applied for issue of Duplicate copy of Customs purposes Ex. Control copy of the above mentioned licence on the ground that the original Customs Exchange Control purposes copy of the licence has been lost or misplaced. It has further been stated that the Customs purposes Ex. Control copy of the licence was not registered with any Customs Authority and as such the value of Customs Purpose Ex. Control copy has not been utilised at all.

2. In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary Public Calcutta, I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes Ex. Control copy of Import Licence No. P/CG/2087-187 dated 16-6-1983 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Customs purposes Exchange Control copy No. P/CG/2087-187 dated 16-6-1983 issued to M/s. Electrical Manufacturing Co. Ltd., Calcutta is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs purposes Exchange Control copy of the said licence is being issued to the party separately valued Rs. 19,47,200/- (US $ 192,475).

[File No. CG I/1626/4/81-82/397]
PAUL BECK, Dy. Chief Controller of Imports & Exports
for Chief Controller of Imports & Exports.

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1985

का.आ. 4263:—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के अनुलग्नक में उल्लिखित उपक्रमों के पर्जीकरण के, उक्त उपक्रमों के वह उपक्रम होने पर, जिन पर उक्त अधिनियम के अध्याय-III के भाग-क के उपबन्ध अब लागू नहीं होते हैं, के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है ।

[सं. 16/12/85-एम.3]

अधिसूचना संख्या 16/12/85-एम.-3 का अनुलग्नक

क्र.सं.	उपक्रमों के नाम	पंजीकृत कार्यालय का पता	पंजीकरण संख्या
1.	मै. एलानासन्स प्राइवेट लिमिटेड ।	4-जे, एलाना रोड, कोलाबा, बम्बई-400039	2010/84
2.	एलाना कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि. ।	-यथोपरि-	2004/84
3.	एलाना फ्रोजन फूडस प्रा.लि. ।	एलान हाउस 4, एलाना रोड कोलाबा, बम्बई-400039	2021/84
4.	फ़ोनिसिया सीपिंग कम्पनी प्रा. लि.	4-जे, एलाना रोड, कोलाबा, बम्बई-400039	2018/84
5.	एलाना इनवेस्टमेन्ट्स एंड ट्रेडिंग कम्पनी प्रा.लि. ।	-यथोपरि-	2002/84
6.	फ़ोनोसिया इनवेस्टमेंटस् एंड ट्रेडिंग कम्पनी प्रा.लि. ।	-यथोपरि-	2017/84
7.	एलाना ब्रदर्स प्रा. लि. ।	-यथोपरि-	2003/84
8.	एलाना होल्डिंग्स प्रा. लि. ।	-यथोपरि-	2015/84
9.	एन्जानिया कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि. ।	प्लाट सं. बी/35, लारेन्स रोड, नई दिल्ली	2007/84
10.	एलाना एक्सपोर्टस प्रा. लि. ।	4-जे, एलाना रोड, कोलाबा, बम्बई-400039	2012/84
11.	मोटको फ़ूड्स प्रा. लि. ।	4-जे, एलाना रोड, कोलाबा, बम्बई-400039	2009/84
12.	एलहीलाल फ्रोजेन फ़ूड्स प्रा. लि. ।	-यथोपरि-	2019/84
13.	डेलमल फ्रोजेन फ़ूडस् प्रा. लि. ।	-यथोपरि-	2001/84
14.	एलाना सर्विसेस प्रा. लि. ।	-यथोपरि-	2025/84
15.	एलाना केमीकल्स एंड आयल्स (इंडिया) प्रा.लि. ।	4-जे, एलाना रोड, कोलाबा, बम्बई-400039	2020/84
16.	फ़ोनिसिया ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट प्रा. लि. ।	4-जे, एलाना रोड, कोलाबा, बम्बई-400039	2011/84
17.	जम जम एक्सपोर्ट प्रा. लि. ।	-यथोपरि-	2023/84
18.	कालवा कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि.	4-जे एलान रोड कोलाबा, बम्बई-400039	2013/84
19.	एलाना इम्पोर्टस् एन्ड एक्सपोर्टस् प्रा. लि.	4-जे एलाना रोड कोलाबा, बम्बई-400039	2008/84
20.	भारत टीन वर्क्स	95-मेमोनवाडा रोड, बम्बई-400003	2015/84
21.	सथानव होल्डिंग्स प्रा. लि. ।	एलाना बिल्डिंग, 424-ए मौलाना आजाद रोड, बम्बई-400004	2016/84
22.	एलाना इम्पेक्स प्रा. लि.	-यथोपरि-	2006/84
23.	जोसाभाई ए एलाना एंड सन्स ।	एलान बिल्डिंग 424-मौलाना आजाद रोड, बम्बई-400004	2022/84
24.	जयसन्स	-यथोपरि-	2014/84
25.	भारत आयल एंड वेजीटेबल प्रोडक्ट्स	-यथोपरि-	2024/84
26.	मोरारजी गोकुलदास स्पीनिंग एंड विभिंग कम्पनी लि.	डा. अम्बेडकर रोड, पार्ले, बम्बई-400012	1511/80
27.	गोपीकिसन पीरामल लि.	एडमीनिस्ट्रेशन बोल्डिंग, मोरारजी मिल्स, डा. अम्बेडकर रोड, पार्ले, बम्बई-400012	1594/82

1	2	3	4
28.	मै. पीरामल एक्सपोर्टस् लि.।	-यथोपरि-	1595/82
29.	एलपीन इन्वेस्टमेंट्स लि.	-यथोपरि-	2044/84
30.	उर्वी केमीकल्स एंड एलाइड इन्डस्ट्रीज लि.।	एडमीनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, मोरारजी मिल्स, डा. अम्बेडकर रोड, पार्ले, बम्बई-400012	1654/83
31.	पीरामल पोलिमर्स लि.।	एडमीनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, मोरारजी मिल्स, डा. अम्बेडकर रोड, पार्ले बम्बई-400012	2064/84
32.	निर्वाना इन्वेस्टमेंटस प्रा. लि.।	-यथोपरि-	2088/84
33.	नेवुला इन्वेस्टमेंट्स् प्रा. लि.।	-यथोपरि-	2065/84
34.	करी आन इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा. लि.।	-यथोपरि-	2045/84
35.	लुकरे इन्वेस्टमन्ट्स प्रा.लि.।	-यथोपरि-	2087/84
36.	गुजरात स्टील ट्यूब्स लि.।	बैंक आफ इंडिया बिल्डिंग, भाद्रा, अहमदाबाद--380001	1579/82
37.	नीका ट्यूब्स लि.।	बैंक आफ इंडिया बिल्डिंग, भाद्रा, अहमदाबाद-380001	1580/82

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 29th August, 1985

S.O. 4263.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of the undertakings mentioned in the Annexure to this notification, the said undertakings being undertakings to which the provisions of Part A of Chapter-III of the said Act no longer apply.

[No. 16|12|85.M-III]

ANNEXURE TO NOTIFICATION No. 16/12/85. M-III

S. No.	Names of the Undertakings	Registered Address	Registration No.
1	2	3	4
1.	M/s. Allanasons Pvt. Ltd.	4-J, Allana Road, Colaba, Bombay-400 039.	2010/84
2.	Allana Cold Storage Pvt. Ltd.	-do-	2004/84
3.	Allana Frozen Foods Pvt. Ltd.	Allana House 4, Allana Road, Colaba, Bombay-400 039.	2021/84
4.	Phoenicia Shipping Co. Pvt. Ltd.	4-J, Allana Road, Colaba, Bombay-400 039.	2018/84
5.	Allana Investments and Trading Co. Pvt. Ltd.	-do-	2002/84
6.	Phoenicia Investments & Trading Co. Pvt. Ltd.	-do-	2017/84
7.	Allana Bros. Pvt. Ltd.	-do-	2003/84
8.	Allana Holdings Pvt. Ltd.	-do-	2015/84
9.	Anjaneya Cold Storage Pvt. Ltd.	Plot No. B/35, Lawrence Road, New Delhi.	2007/84
10.	Allana Exports Pvt. Ltd.	4-J, Allana Road, Colaba, Bombay-400 039.	2012/84
11.	Meatco Foods Pvt. Ltd.	4-J, Allana Road, Colaba, Bombay-400 039.	2009/84
12.	Alhilal Frozen Foods Pvt. Ltd.	-do-	2019/84
13.	Delmon Frozen Foods Pvt. Ltd.	-do-	2001/84
14.	Allana Services Pvt. Ltd.	-do-	2025/84
15.	Allana Chemicals and Oils (India) Pvt. Ltd.	4-J, Allana Road, Colaba, Bombay-400 039.	2020/84
16.	Phoenicia Traval and Transpot Pvt. Ltd.	4-J, Allana Road, Colaba, Bombay-400 039.	2011/84
17.	Zam Zam Export Pvt. Ltd.	-do-	2023/84
18.	Kalwa Cold Storage Pvt. Ltd.	4-J, Allana Road, Colaba, Bombay-400 039.	2013/84
19.	Allana Imports & Exports Pvt. Ltd.	4-J, Allana Road, Colaba, Bombay-400 039.	2008/84

1	2	3	4
20.	Bharat Tin Works	95-Memonwada Road, Bombay-400 003.	2005/84
21.	Sathanav Holdings Pvt. Ltd.	Allana Building, 424-Maulana Azad Road, Bombay-400 004.	2016/84
22.	Allana Impex Pvt. Ltd.	-do-	2006/84
23.	Joosabbhoy A. Allana & Sons	Allana Buildings, 424-Maulana Azad Road, Bombay-400 004.	2022/84
24.	Jaysons	-do-	2014/84
25.	Bharat Oil and Vegetable Products	-do-	2024/84
26.	M/s. Morarji Gokuldas Spinning & Wvg. Co. Ltd.	Dr. Ambedkar Road, Parel, Bombay-400 012	1511/80
27.	Gopikisan Piramal Ltd.	Administration Building, Morarjee Mills, Dr. Ambedkar Road, Parel, Bombay-400 012	1594/82
28.	Piramal Exports Ltd.	-do-	1595/82
29.	Elphin Investments Ltd.	-do-	2044/84
30.	Urvi Chemicals & Allied Industries Limited.	Administration Building Morarjee Mills, Dr. Ambedkar Road, Parel, Bombay-400 012.	1654/83
31.	Piramal Polymers Ltd.	-do-	2064/84
32.	Nirvana Investments Pvt. Ltd.	-do-	2088/84
33.	Nebula Investments Pvt. Ltd.	-do-	2065/84
34.	Carry-On Investments Pvt. Ltd.	-do-	2045/84
35.	Lucre Investments Pvt. Ltd.	-do-	2087/84
36.	Gujarat Steel Tubes Ltd.	Bank of India Building, Bhadra, Ahmedabad-380 001.	1597/82
37.	Neoka Tubes Ltd.	Bank of India Building, Bhadra, Ahmedabad-380 001.	1580/82

का.आ. 4264.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के अनुलग्नक में उल्लिखित उपक्रमों के पंजीकरण को, उक्त उपक्रमों के वह उपक्रम होने पर, जिन पर उक्त अधिनियम के अध्याय-III के भाग-क के उपबंध अब लागू नहीं होते हैं, के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है ।

[सं. 16/12/85-एम.-3]
एल. सी. गोयल, अवर सचिव

अधिसूचना संख्या 16/12/85-एम-3 का अनुलग्नक

क्र.सं.	उपक्रमों के नाम	पंजीकृत कार्यालय, पता	पंजीकरण सं.
1.	बेस्ट एण्ड क्राम्पटन इंजी. लि.	29, राजाजी सलाई, पो. ब. नं. 63, मद्रास-600001	1535/81
2.	बीक्लन रोटर कन्ट्रोल्स लि.	यथोपरि	1534/81
3.	करेस्ट डवलपमेंट एण्ड लीजिंग लि.	यथोपरि	1745/84
4.	जर्मन रेमेडीज लिमिटेड	शिवसागर एस्टेट, ए-ब्लाक डा. एनीबसंत रोड, वार्ली, बम्बई-400018	1800/84
5.	एल्यूमीनियम इण्डस्ट्रीज लि.	नं. 1, सेरेमिक फैक्टरी, रोड, कुन्दरा-69150 केरल	1615/83
6.	सैन्डोज (इंडिया) लिमिटेड	सेन्डोज हाउस, डा. एनीबसंत रोड, वार्ली, बम्बई-400018	1503/80
7.	ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन आफ इंडिया लि.,	1-7-293, एम. जी. रोड, सिकन्द्राबाद-500003 (आंध्र प्रदेश)	1586/82

1	2	3	4
8.	भोरुका स्टील लिमिटेड	महादेवापुरा पोस्ट, व्हाइटफील्ड रोड, बंगलौर-560048	1587/82
9.	महिन्द्रा उगाइन स्टील कम्पनी लि.,	बख्तावर, नारीमन पाइन्ट, बम्बई-21	1289/76
10.	के. जी. खोसला कम्प्रेसर्स लिमिटेड	1, देशबन्धु गुप्ता रोड, नई दिल्ली-110055	1625/83
11.	प्रशान्त खोसला न्यूमेटिक्स लि.	यथोपरि	1627/83
12.	खोसला फाउंडरी लिमिटेड	यथोपरि	1628/83
13.	खोसला इन्डाइर लिमिटेड	यथोपरि	1626/83

S.O. 4264.—In pursuance of Sub-Section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of the undertakings mentioned in the Annexure to this notification, the said undertakings being undertakings to which the provisions of Part A of Chapter-III of the said Act no longer apply.

[No. 16|12|85-M.III]

L. C. GOYAL, Under Secy.

ANNEXURE TO THE NOTIFICATION No. 16/12/85- M. III

S. No.	Names of the Undertakings	Registered Address	Regn. No.
1	2	3	4
1.	Best & Crompton Engg. Limited	29, Rajaji Salai, P.B. No. 63, Madras-600 001.	1535/81
2.	Beacon Rotor Controls Ltd.	-do-	1534/81
3.	Krest Development & Leasing Ltd.	-do-	1745/81
4.	German Remedies Limited	Shivnagar Estate, A-Block, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400 018	1800/84
5.	Aluminium Industries Ltd.	No. 1, Ceramic Factory Road, Kundara-691 501, Kerala	1615/83
6.	Sandoz (India) Limited	Sandoz House, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-400 018	1503/80
7.	Transport Corporation of India Limited	1-7-293, M.G. Road, Secunderabad-500 003 (A.P.)	1586/82
8.	Bhoruka Steel Limited	Mahadevapura Post, Whitefield Road, Bangalore-560 048	1587/82
9.	Mahindra Ugine Steel Co. Ltd.	Bakhtawar, Nariman Point, Bombay-400 021	1289/76
10.	K.G. Khosla Compressors Ltd.	1, Deshbandhu Gupta Road, N. Delhi-110 055	1625/83
11.	Prashant Khosla Pneumatics Limited	-do-	1627/83
12.	Khosla Foundary Limited	-do-	1628/83
13.	Khosla Indair Limited	-do-	1626/83

इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय
(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1985

का.आ. 4265.— केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 2473, तारीख 12 जुलाई, 1977 को अधिक्रांत करते हुए, नीचे के सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकारी को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो अपनी अधिकारिता की

सीमाओं के भीतर उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के सरकारी स्थानों की बाबत, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा ।

सारणी

अधिकारी का पदनाम	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
खान अधीक्षक, कोल इंडिया लि. (उत्तर-पूर्वी कोयला खदान क्षेत्र) जिला डिब्रूगढ़, असम	असम के डिब्रूगढ़ और शिवसागर जिलों में और अरुणाचल प्रदेश के तिरप में कोल इंडिया लि. (उत्तर-पूर्वी कोयला खदान क्षेत्र) के कोयला खदान और अन्य सभी स्थान ।

[सं. 43018/8/85-सी.ए.]

MINISTRY OF STEEL MINES AND COAL
(Department of Coal)
New Delhi, the 21st August, 1985

S.O.4265.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (10 of 1971) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal), No. S.O. 2473, dated the 12th July, 1977, the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below being an officer equiv alent to the rank of gazetted officer of the Central Government to be estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on estate officer by or under the said Act, within the limits of his jurisdiction in respect of the categories of public premises specified in column (2) of the said Table:

TABLE

Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
Superintendent of Mines, Coal India Limited (North Eastern Coalfields Area), District Dibrugarh, Assam	Coalfield area and all other premises belonging to the Coal India Limited (North Eastern Coalfields) in the Districts of Dibrugarh and Shibsagar, Assam, and Tirap, Arunachal Pradesh.

[No. 43018/8/85-CA]

आदेश

का.आ. 4266:—केन्द्रीय सरकार कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट सरकारी कंपनियां, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिरोपित निबंधनों और शर्तों का पालन करने के लिए तत्पर है, निदेश देती है कि कोयला बोर्ड के उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अपनी सम्पत्तियों के संबंध में अधिकार, हक और हित केन्द्रीय सरकार में निहित रहने के बजाय पूर्वोक्त सारणी के कालम (4) में विनिर्दिष्ट तारीख से उक्त सरकारी कंपनियों में निहित होंगे ।

सम्पत्ति का क्रम संख्यांक	सम्पत्ति का विवरण	सरकारी कंपनी का नाम	निहित होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दामोदर नदी के किनारे सैंडविनिंग और अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिए भूतपूर्व कोयला बोर्ड की भूमि, भवन	बी.सी.सी. लिमिटेड	1-4-1975
2.	बिहार के धनबाद जिसके टटंगाबाद ग्राम में 3474.97 एकड़ क्षेत्र पर का पट्टा	बी.सी.सी.लिमिटेड	1-4-1975

[सं. 20/39/80-सी.एल/सी.ए.]

ORDER

S.O. 4266.—In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974 (28 of 1974), the Central Government being satisfied that the Government companies specified in column (3) of the Table below are willing to comply with the terms and conditions imposed by the Central Government, hereby directs that the right, title and interest of the Coal Board in relation to its properties specified in column (2) of the said Table shall, instead of continuing to vest in the Central Government, vest in the said Government

Companies with effect from the date specified in column (4) of the aforesaid Table:

S. No. of the property	Description of the property	Name of the Government companies	Date from which it is vested
1	2	3	4
1.	The lands, buildings of ex-Coal Board along river Damodar for sand winning and such other purposes	B.C.C. Limited	1-4-1975
2.	Sand Mining Lease over an area 3474.97 acres in village Tatangabad and others in Dhanbad District of Bihar	B.C.C. Limited	1-4-1975

[No. 20/39/80-CL/CA]

का.आ. 4267.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयला का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. सी-1(ई)-III/ डीडीआर/294-285 तारीख 16 फरवरी, 1985 का निरीक्षण वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (राजस्व अनुभाग), कोयला एस्टेट सिविल लाइंस, नागपुर-440001 के कार्यालय में या कलक्टर, सम्बलपुर (उड़ीसा) के कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक, 1-काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में किया जा सकता है ;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, राजस्व अधिकारी, वेस्टर्न कोलफील्डस लि., कोयला एस्टेट, सिविल लाइंस, नागपुर-440001 को भेजेगा ।

अनुसूची

आई बी घाटी कोयला क्षेत्र में ओरोऐंट खान संख्यांक 1, 2 और 3 का वेस्टर्न ब्लाक जिला सम्बलपुर (उड़ीसा राज्य)

क्र. सं.	ग्राम का नाम	तहसील	जिला	क्षेत्र एकड़ में	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	गन्डघोरा	झारसुगुडा	सम्बलपुर	200.00	भाग
2.	चिंगरीगुडा	झारसुगुडा	सम्बलपुर	300.00	भाग
3.	जामकानि	लखनपुर	यथोक्त	400.00	भाग
4.	छुआलिबेरना	झारसुगुडा	यथोक्त	1100.00	भाग
5.	आमदरहा	यथोक्त	यथोक्त	169.24	भाग
6.	लाजकूरा	यथोक्त	यथोक्त	40.00	भाग

कुल क्षेत्र : 2209.24 एकड़ (लगभग)
या
894.05 हैक्टर (लगभग)

सीमा वर्णन :

क—ख रेखा, बिन्दु "क" से आरंभ होती है और आमदरहा ग्राम से होकर जाती है और आमदरहा और छुआलिबेरना ग्रामों की सम्मिलित सीमा के बिन्दु "ख" पर मिलती है ।

ख—ग रेखा, जमींदारी वन और छुआलिबेरना ग्राम की सम्मिलित सीमा के साथ जाती है और जमींदारी वन, समडा और छुआलिबेरना ग्राम के त्रिसंगम बिन्दु "ग" पर मिलती है ।

ग—घ रेखा, छुआलिबेरना और समडा ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है, फिर जामकानि और समडा ग्रामों से होकर जाती है और समडा और जामकानि ग्रामों की सम्मिलित सीमा पर, बिन्दु "घ" पर मिलती है ।

घ—ङ रेखा, जामकानि, चिंगरीगुडा और लाजकूरा ग्रामों से होकर जाती है और लाजकूरा ग्राम में बिन्दु "ङ" पर मिलती है ।

ङ—क रेखा, लाजकूरा, छुआलिबेरना, गन्डघोकूरा ग्रामों से होकर जाती है, फिर आमदरहा ग्राम की दक्षिण-पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है और आरंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है ।

[फा. सं. 43015/16/85-सी.ए.]

S.O.4267.—whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan bearing No. C-1(E)III/DDR/294-285 dated the 16th February. 1985 of the area covered by this notification can be inspected at the Office of the Western Coalfields Limited (Revenue Section), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440001 or at the office of the Collector, Sambalpur (Orissa) or at the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street Calcutta.

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Western Coalfields Limited, Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440001 within ninety days from the date of publication of this notification.

SCHEDULE

Western Block of Orient Mine Nos. 1, 2 and 3
IB Valley Coalfield
District Sambalpur (Orissa State)

Sr. No.	Name of the village	Tehsil	District	Area in acres	Remarks
1.	Gandghora	Jharsuguda	Sambalpur	200.00	Part
2.	Chingriguda	Jharsuguda	Sambalpur	300.00	Part
3.	Jamakani	Lakhanpur	Sambalpur	400.00	Part
4.	Chhualiberna	Jharsuguda	Sambalpur	1100.00	Part
5.	Amadarha	Jharsuguda	Sambalpur	169.24	Part
6.	Lajkura	Jharsuguda	Sambalpur	40.00	Part
	Grand total area :			2209.24 acres (approximately)	
			or	894.05 hectares (approximately)	

Boundary description:

A-B : Line starts from point 'A' and passes through village Amadarha and meets on the common boundary of villages Amadarha and Chhualiberna at point 'B'.

B-C : Line passes along the common boundary of zamindari forest and village Chhualiberna and meets on trijunction point of zamindari forest, villages Samda and Chhualiberna at point 'C'.

C-D Line passes along the common boundary of villages Chhualiberna and Samda, then Jamkani and Samda and meets on the common boundary of villages Samda and Jamkani at point 'D'.

D-E : Line passes through villages Jamkani, Chingringuda and Lajkura and meets in the Village Lajkura at point 'E'.

E-A : Line passes through villages Lajkura, Chhualiberna, Gaandghora, then proceeds along the south-eastern boundary of village Amadarha and meets at starting point 'A'

[F. No. 43015/16/85-CA]

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1985

का.आ. 4268:—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला (धारक क्षेत्र अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1233 तारीख 14 अप्रैल, 1984 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने और बिहार सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 521.50 एकड़ (लगभग) या 211.04 हेक्टर (लगभग) माप की भूमि का अर्जन किया जाना चाहिए ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में वर्णित 521.50 एकड़ (लगभग) या 211.04 हेक्टर (लगभग) माप की भूमि का अर्जन किया जाता है ।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. राजस्व/147/84 तारीख 22-10-84 का निरीक्षण उपायुक्त गिरिडीह (बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक 1—काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में या सेन्ट्रल कोलफील्डस् लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) दरभंगा हाउस, रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

अनुसूची

चपरी विस्तारण

पूर्वी बोकारो कोयला क्षेत्र

जिला गिरीडीह (बिहार)

सभी अधिकार

क्र.सं.	ग्राम	थाना	थाना सं.	जिला	क्षेत्र	टिप्पणी
1.	एमलो	नवाडीह	64	गिरीडीह	4.30	भाग
2.	धोरही	(बेरमो)	68	गिरीडीह	365.00	भाग
3.	चपरी	(बेरमो)	73	गिरीडीह	152.20	भाग

कुल क्षेत्र—521.50 एकड़ (लगभग)
211.04 हेक्टर (लगभग)

एमलो ग्राम में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक : 137 (भाग)

धोरही ग्राम में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक :—3020 (भाग), 3021 (भाग), 3022 3058 (भाग) और 3228 (भाग) नदी ।

चपरी ग्राम में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक :

943 (भाग) 944 से 949 (भाग), 950 (भाग), 951 (भाग) 1437 (भाग) 1438 (भाग) और 1439 (भाग) ।

सीमा वर्णन

क—ख रेखा चपरी ग्राम में प्लाट संख्यांक 1437 से होकर ग्राम एमलो में प्लाट संख्यांक 137 से होकर और तब धोरही ग्राम में प्लाट सं. 3020 से होकर जाती है (जो धोरही विस्तारण ब्लॉक के साथ भागतः सम्मिलित सीमा बनाती है) ।

ख—ग—घ रेखाएं धोरी ग्राम में प्लाट संख्यांक 3020 और 3021 से होकर जाती है [जो कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अधीन अर्जित धोरी (के) विस्तार—ब्लॉक के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है] ।

घ—ङ—च रेखा, धोरी ग्राम में प्लाट संख्यांक 3021, 3058 और 3228 (दामोदर नदी) से होकर जाती है (जो धोरी कोयला क्षेत्र की भागतः सम्मिलित सीमा बनाती है) ।

च—छ रेखा, दामोदर नदी की मध्य रेखा के भाग साथ-साथ जाती है ।

छ—ज रेखा, दामोदर नदी से होकर और धोरी तथा माकोली ग्रामों की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ मथथ जाती है (जो नवचयनित धोरी कोयला क्षेत्र की सम्मिलित सीमा बनाती है) ।

ज—छ रेखा, धोरी और माकोली ग्राम की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ-साथ और चपरी ग्राम में प्लाट सं. 1439 से होकर जाती है (जो कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अधीन अर्जित गुंजरडीह ब्लाक की भागतः सम्मिलित सीमा बनाती है ।

झ—क रेखा, चपरी ग्राम में प्लाट सं. 1439, 943, 949, 950, 949, 951, 1439, 1438, और 1437 से होकर जाती है और आरंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है ।

[सं: 43015/4/85-सी.ए.]

New Delhi, the 29th August, 1985

S.O. 4268.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 1233 dated the 14th April, 1984 under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development Act 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas the Competent Authority, in pursuance of section 8 of the said Act, has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the report aforesaid and after consulting the Government of Bihar; is satisfied that the lands measuring 521.50 acres (approximately) or 211.04 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto, should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the said Act, the Central Government here by declares that the lands measuring 521.50 acres (approximately) or 211.04 hectares (approximately), described in the said Schedule, are hereby acquired.

The plans, Drg. No. Rev/147/84, dated 22-10-1984 of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, Giridih (Bihar) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the Office of the Central Coalfields Limited (Revenue Section) Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

SCHEDULE

Chapri Extension
EAST BOKARO COALFIELDS
District Giridih (Bihar)

ALL RIGHTS

Serial number	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Emlo	Nawadih (Bermo)	64	Giridih	4.30	part
2.	Dhorhi	,,	68	,,	365.00	,,
3.	Chapri	,,	73	,,	152.20	,,
		Total area :			521.50 acres (approximatly) 211.04 hectares (approximately)	

Plot number acquired in village Emlo : 137 (part).
Plot numbers acquired in vill ge Dhorhi : 3020 (part), 3021 (part), 3022, 3058 (part) and 3228 (part) River.
Plot numbers acquired in village Chapri : 943 (part), 944 to 948, 949 (part), 950 (part), 951 (part), 1437 (part), 1438 (part), and 1439 (part).
Boundary description :—

A–B	line passes through plot number 1437 in village Chapri, through plot number 137 in village Emlo, than through plot number 3020 in village Dhorhi (which forms part common boundary with Dhorhi Extn. block).
B–C–D	lines pass through Plot numbers 3020 and 3021 in village Dhorhi [which forms common boundary with Dhor (K)Extension block acquired under section 9(1) of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957]
D–E–F	lines pass through plot numbers 3021, 3058 and 3228 (River Damodar) in village Dhorhi (which forms part common boundary of Dhorhi Colliery).
F–G	lines passes along the part central line of Damodar River.
G–H	line passes through Damodar River and also along the part common boundary of villages Dhori and Makoli which forms common boundary with new Selected Dhorhi Colliery).
H–I	line passes along the part common boundary of villages Dhorhi and Makoli and tharough plot number 1439 in village Chapri (which forms part common boundary of Gunjardih block acquired under section 9(1) of the Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957].
I–A	line passes through plot numbers 1439, 943, 949, 950, 949, 951, 1439, 1438 and 1437 in village Chapri and meets at starting point 'A'.

[No. 43015/4/85-CA]

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1985

का. आ. 4269 :—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 18 सितम्बर 1982 में प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 3295 तारीख 27 अगस्त, 1982 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में, भूमि का अर्जन करने के लिये अपने आशय की सूचना दी थी ।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने तथा बिहार सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि; —

(क) इससे संलग्न अनुसूची "क" में वर्णित 1743.05 एकड़ (लगभग) या 705.37 हैक्टर (लगभग) माप की भूमि का, और;

(ख) इससे संलग्न अनुसूची "ख" में वर्णित 21.95 एकड़ (लगभग) या 8.82 हैक्टर (लगभग) माप की भूमि में खनिज के खनन, खदान, वेधन, खुदाई करने और खोजने, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकारों का; अर्जन किया जाना चाहिए ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची "क" में वर्णित 1743.05 एकड़ (लगभग) या 705.37 हैक्टर (लगभग) माप की भूमि और उक्त अनुसूची "ख" में वर्णित 21.95 एकड़ (लगभग) या 8.88 हैक्टर (लगभग) माप की भूमि में खनिजों के खनन, खदान वेधन, खुदाई करने और खोजने, उन्हें प्राप्त करने उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकारों का अर्जन किया जाता है;

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले रेखांक का निरीक्षण उपायुक्त टिरिडीह (बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1 काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में अथवा सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), दरभंगा हाउस, रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची क

चलकड़ी ब्लाक विस्तार II

उप-ब्लाक III और पूर्वी बोकारो कोयला क्षेत्र

आरेख सं. राजस्व 10/83

तारीख 4-8-83

(जिसमें अर्जित की गई भूमि दर्शित की गई है)

सभी अधिकार

क्रम सं.	ग्राम	थाना	थाना सं.	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	जरीडीह	नवी-डीह	19	गिरि-डीह	590.00 भाग	

कुल क्षेत्र : 590.00 एकड़ (लगभग)
या 238.76 हैक्टर (लगभग)

जरीडीह ग्राम में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक :

6 (भाग), 20 (भाग), 54 (भाग), 55 (भाग), 56 (भाग), 57 (भाग), 58 से 228, 229 (भाग), 230, 231 (भाग), 232 (भाग), 233, 234, 235 (भाग) 237 (भाग), 238, 239, 240, 241, 242 (भाग) 290 (भाग) 375 (भाग), 376 (भाग), 377, 378 (भाग) 379, 380, 381 (भाग) 382 (भाग), 383 (भाग), 404 (भाग), 405 से 419, 420 (भाग), 421 (भाग), 422 से 429, 430 (भाग), 431 (भाग), 432, 433, 434 (भाग), 435 से 441, 442 (भाग), 443 (भाग), 444 (भाग), 445 से 532, 533 (भाग), 534 (भाग), 538 (भाग), 539, 540 (भाग), 541 से 565, 566 (भाग), 567 से 575, 576 (भाग) 577, 578 (भाग), 579 (भाग), 582 (भाग), 583 से 593, 594 (भाग), 596 (भाग), 597 (भाग), 598 (भाग), 599, 600, 601, 602 (भाग), 645 (भाग), 646 (भाग), 647 (भाग), 648 (भाग), 867 (भाग), 872 (भाग), 874 (भाग), 876 (भाग), 877 से 879, 880 (भाग), 881 (भाग), 882 883 (भाग) 884 (भाग), 885 से 892, 893 (भाग), 894, 895, 896, 897 (भाग), 898 से 971, 972 (भाग), 973, 974 (भाग), 980 (भाग), 984 (भाग), 985 (भाग), 986 (भाग), 987 (भाग), 988 (भाग), 1000 (भाग), 1001 से 1005, 1006 (भाग), 1007 (भाग), 1009 (भाग), 1012 (भाग), 1013 (भाग), 1014 (भाग), 1015, 1016 (भाग), 1027 (भाग), 1029 (भाग), 1030 (भाग), 1031 से 1033, 1034 (भाग), 1035 (भाग), 1036 (भाग), 1037 से 2064 2066 से 2325, 2327, 2328, 2329 और 2332 (भाग)।

सीमा वर्णन :

क-ख रेखा ग्राम जरीडीह में कुनार नदी के भागतः बाएं किनारे के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है।

ख-ग रेखा ग्राम जरीडीह में दामोदर नदी के भागतः बाएं किनारे के साथ-साथ जाती है बिन्दु "ग" पर मिलती है।

ग-घ रेखा कोयला जरिया नदी के भागतः दाएं किनारे के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है।

घ-ङ रेखाएं ग्राम जरीडीह में प्लाट संख्यांक 867, 884, 883, 881, 880, 872, 876, 874, 893, 986, 987, 985, 984, 980, 897, 974, 972, 1000, 1009, 1006, 1007, 1012, 1013, 1014, 1027, 1035, 1036, 1034, 1029, 1030, 1029, 988, 534, 533, 538, 540, 602, 598, 597, 596, 594, 290, 645, 646 और 647 से होकर जाती है (जो बोकारो कोयला क्षेत्र और साथ भागतः सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु "च" पर मिलती है।

च-छ-ज रेखाएं ग्राम जरीडीह में प्लाट संख्यांक 647, 648, 290, 582

ज-ज 576, 578, 579, 566, 434, 404, 382, 381, 383, 378,

क 376, 375, 420, 421, 430, 431, 434, 442, 434, 443, 444, 229, 231, 232, 235, 237, 242, 20, 54, 23, 32, 54, 56, 55, 57 और 6 से होकर जाती है (जो रेल द्वारा अर्जित भूमि के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है) और आरम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

सभी अधिकार उप ब्लाक (4)

क्रम सं.	ग्राम	थाना	थाना सं.	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	चालकड़ी	पेटारबर	46	गिरीडीह	1153.05	भाग

कुल क्षेत्र : 1153.05 एकड़ (लगभग)
या : 466.61 हैक्टर (लगभग)

ग्राम चालकड़ी में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक :

2 से 473, 475 से 705, 713 से 721, 723 (भाग), 725, 743, 744, 745, 746 (भाग), 747 (भाग), 749 (भाग), 750 (भाग), 751 से 756, 757 (भाग), 758, (भाग) 759, 760, 761 (भाग), 763 (भाग), 764 (भाग), 765 (भाग), 767 (भाग), 768 (भाग) 769 से 774, 776, 781 (भाग), 782 से 797, 798 (भाग), 799 से 937, 939 से 1426, 1427 (भाग) 1431 (भाग), 1432, 1433, 1434 (भाग), 1435 (भाग), 1436 से 1443, 1444 (भाग), 1445 से 1539, 1540 (भाग), 1541 (भाग), 1542 (भाग), 1543 से 1546, 1547 (भाग), 1548 से 1558, 1559 (भाग), 1561 (भाग), 1562 से 1564, 1565 (भाग), 1566 (भाग), 1567 (भाग), 1599 (भाग), 1600 (भाग), 1601 से 1605, 1606 (भाग), 1615 (भाग) 1622 (भाग), 1623, 1624 (भाग), 1625 (भाग), 1626, 1627, 1628, 1629, 1630 (भाग), 1631, 1632, 1633, 1634 (भाग), 1635 (भाग), 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, (भाग), 1641 (भाग), 1642 से 2381, 2382 (भाग), 2383 से 2400, 2401 (भाग), 2505 (भाग), 2623 (भाग), 2624 (भाग), 2625 से 2630, 2631 (भाग), 2632 (भाग), 2707 (भाग), 2708 से, 2999, 3000 (भाग), 3001, 3002 (भाग), 3007 (भाग), 3008 से 3081, 3082 (भाग), 3083 (भाग), 3091 (भाग), 3092 (भाग), 3093, (भाग), 3094 (भाग), 3101 (भाग), 3120 (भाग), 3124 (भाग), 3125 (भाग), 3127 (भाग), 3128, 3129, 3130, 3131 (भाग), 3132, 3133, 3134, 3135 (भाग), 3136 (भाग), 3138 (भाग), 3139 (भाग), 3185 (भाग), 3186 (भाग), 3187 से 3189, 3190 (भाग), 3191, 3192, 3193 (भाग), 3201 (भाग), 3202, 3203 (भाग), 3204, 3205 (भाग). 3206 से 3238, 3239 (भाग), 3240 से 3457, 3458 (भाग), 3459 से 3524, 3525 (भाग), 3526 (भाग), 3527, 3528 (भाग), 3529 से 3550, 3551 (भाग), 3552 से 3555, 3556 (भाग), 3575 (भाग), 3576 (भाग), 3577 (भाग), 3581 (भाग), 3582 (भाग), 3583 (भाग), 3584 से 3586, 3587 (भाग), 3589 (भाग), 3598 (भाग), 3600 (भाग), 3601, 3602 (भाग), 3603 (भाग) 3604 (भाग), 4150, 4151, 4153, 4154, 4155, 4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4165, 4167, 4174 और 4175।

सीमा वर्णन

ट-ठ रेखा ग्राम चालकड़ी में प्लाट संख्यांक 3589, 3587, 3583, 3587, 3582 3581, 3525, 2526, 3576, 3577, 3576, 3528, 3576, 3598, 3600 और 3603 से होकर जाती है (जो चालकड़ी ब्लाक विस्तारण के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु "ठ" पर मिलती है।

ठ-ड रेखाएं चालकड़ी में प्लाट संख्यांक 3603, 3602, 3604, 3576,

ढ-ण 3575, 3458, 3556, 3458, 3551, 3458, 3205, 3186, 3185, 3186, 3185, 3190, 3205, 3193, 3205, 3201, 3203, 3135, 3136, 3138, 3139, 3131, 3139, 3131, 3120, 3127, 3125, 3124, 3101,

3239, 3002, 3000, 3002, 3007, 3094, 3092, 3093, 3091, 3083, 3082, 2707, 2632, 2631, 2632, 2624, 2623, 2505, 2401, 2382, 1641, 1640, 1635, 1634, 1630, 1615, 1624, 1625, 1624, 1622, 1606, 1600, 1599, 1427, 1435, 1434, 1431, 1444, 1540, 1541, 1542, 1547, 1566, 1567, 1566, 1565, 1559 और 1561 से होकर जाती है और बिन्दु "ण" पर मिलती है।

ण–त रेखा ग्राम चालकड़ी में नाला के भागतः बाएं किनारे के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "त" पर मिलती है।

त–ट रेखा ग्राम चालकड़ी में दामोदर नदी के पश्चिमी और दक्षिणी किनारे के साथ साथ जाती है और आरम्भिक बिन्दु "ट" पर मिलती है।

अनुसूची ख

उप-ब्लाक 4क, 4ख, 4ग, 4घ, 4ङ, 4च, (जिसमें वह भूमि दर्शित की गई है जहां खनिजों के खनन, खदान वेधन, उनकी खुदाई करने और खोजने, उन्हें प्राप्त करने उस पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकारों का अर्जन किया गया है)

खनन अधिकार

उप ब्लाक	ग्राम	थाना	थाना सं.	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
4क	चालकड़ी	पेटारवर	46	गिरिडीह	0.80	भाग
4ख	चालकड़ी	पेटारवर	46	गिरिडीह	9.50	भाग
4ग	चालकड़ी	पेटारवर	46	गिरिडीह	0.88	भाग
4घ	चालकड़ी	पेटारवर	46	गिरिडीह	0.77	भाग
4ङ	चालकड़ी	पेटारवर	46	गिरिडीह	9.55	भाग
4च	चालकड़ी	पेटारवर	46	गिरिडीह	0.45	भाग
		कुलक्षेत्र	:	21.95 एकड़ (लगभग)		
		या	:	8.88 हेक्टर (लगभग)		

ग्राम चालकड़ी में अंजित किए गए प्लाट संख्यांक

उपब्लाक 4क में 726, 727 और 798 (भाग)

उपब्लाक 4ख में 706 से 812, 722, 723 (भाग) (724, 728 से 737)

उपब्लाक 4ग में 738 से 742

उपब्लाक 4घ में 746 (भाग), 747 (भाग), 748, 749 (भाग) और 750 (भाग)

उपब्लाक 4ङ में 757 (भाग), 758 (भाग), 761 (भाग), 762, 763, (भाग), 764 (भाग), 765 (भाग), 766 (भाग), 767 (भाग), 768 (भाग), 777, 778, 780 और 781 (भाग)।

उपब्लाक 4च में 779

सीमा वर्णन

उपब्लाक 4क

थ–द रेखा प्लाट संख्यांक 798 से होकर जाती है और प्लाट संख्यांक 726 और 638 के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है और बिन्दु "द" पर मिलती है।

द–ध–न रेखाएं प्लाट संख्यांक 726 और 727 की प्लाट संख्यांक 798 के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है और बिन्दु "न" पर मिलती है।

न–थ रेखा प्लाट संख्यांक 798 से होकर जाती है और आरम्भिक बिन्दु "थ" पर मिलती है।

उपब्लाक 4ख

प–फ रेखा ग्राम चालकड़ी के प्लाट संख्यांक 723 से होकर फिर प्लाट संख्यांक 722 की प्लाट संख्यांक 723, 720, 721 के साथ संख्यांक 711 की प्लाट संख्यांक 721, 713 और 714 के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है और बिन्दु फ पर मिलती है।

फ–ब रेखा ग्राम चालकड़ी के प्लाट संख्यांक 711 की प्लाट संख्यांक 714, 701 के साथ प्लाट संख्यांक 708 की प्लाट संख्यांक 702 और 703, 704 और 705 के साथ प्लाट संख्यांक 707 की प्लाट संख्यांक 704 के साथ प्लाट संख्यांक 706 की प्लाट संख्यांक 705 के साथ प्लाट संख्यांक 709 की प्लाट संख्यांक 705 के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है और बिन्दु "ब" पर मिलती है।

ब–भ	रेखा ग्राम चालकड़ी में प्लाट संख्यांक 709 और 736 की प्लाट संख्यांक 507 के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है तथा प्लाट संख्यांक 507 से भी होकर जाती है और बिन्दु "भ" पर मिलती है।
भ–म	रेखा प्लाट संख्यांक 736, 737, 732, 728, 729 की प्लाट संख्यांक 798 के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है और बिन्दु "म" पर मिलती है।
म–प	रेखा प्लाट संख्यांक 732, 730, 722, 724 की प्लाट संख्यांक 798 के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है और आरम्भिक बिन्दु "प" पर मिलती है।

उपखण्ड 4ग

य–क 1	रेखा ग्राम चालकड़ी में प्लाट संख्यांक 742, 741, 740, 739, 738 की प्लाट संख्यांक 798 के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है और बिन्दु क1 पर मिलती है।
क1 ख1–ग1	रेखाएं ग्राम चालकड़ी में प्लाट संख्यांक 738, 739, 740, 741 और 742 की प्लाट संख्यांक 774 के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है और बिन्दु "ग 1" पर मिलती है।
ग 1–ग1 घ	रेखा ग्राम संख्यांक 742 और 798 के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है।

उपखण्ड 4घ

घ 1–ङ. 1	रेखा ग्राम चालकड़ी में प्लाट संख्यांक 746 और 774 के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है और बिन्दु ङ. 1 पर मिलती है।
ङ. 1–च 1	रेखा ग्राम चालकड़ी में प्लाट संख्यांक 746 और 748 की प्लाट संख्यांक 780 के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है तथा प्लाट संख्यांक 749 से होकर जाती है और बिन्दु "च 1" पर मिलती है।
च 1–छ 1	रेखा ग्राम चालकड़ी में प्लाट संख्यांक 750 से होकर जाती है फिर प्लाट संख्यांक 748, 747 की प्लाट संख्यांक 774 के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है और बिन्दु "छ 1" पर मिलती है।
छ 1–घ 1	रेखा ग्राम चालकड़ी में प्लाट संख्यांक 747, 746 से होकर जाती है और आरम्भिक बिन्दु "घ 1" पर मिलती है।

उपखण्ड 4 ङ.

ज 1–झ 1	रेखा ग्राम चालकड़ी में प्लाट संख्यांक 747 और 774 के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है और बिन्दु "झ1" पर मिलती है।
झ 1 ञ–1	रेखा ग्राम चालकड़ी में प्लाट संख्यांक 757 और 756 के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है फिर प्लाट संख्यांक 757, 758, 757, 761, 781 से होकर जाती है और बिन्दु ञ-1 मिलती है।
ञ 1–ट 1–ठ 1	रेखाएं प्लाट संख्यांक 778 और 781 को भागतः सम्मिलित सीमा बनाती है, प्लाट संख्यांक 780 की प्लाट संख्यांक 781 और 814 के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है और बिन्दु ठ 1 पर मिलती है।
ठ 1-ड 1–ढ 1	रेखाएं ग्राम चालकड़ी में प्लाट संख्यांक 780, 778 की प्लाट संख्यांक 814 के साथ, प्लाट संख्यांक 777 की प्लाट संख्यांक 776 के साथ, प्लाट संख्यांक 778 की प्लाट संख्यांक 776 के साथ प्लाट संख्यांक 781 और 762 की प्लाट संख्यांक 776 के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है और बिन्दु ढ 1 पर मिलती है।
ढ 1–ण 1	रेखा ग्राम चालकड़ी में प्लाट संख्यांक 762 की प्लाट संख्यांक 772 के साथ सम्मिलित सीमा और प्लाट संख्यांक 763 की भागतः सीमा बनाती है और बिन्दु "ण 1" पर मिलती है।
ण 1–ज 1	रेखा ग्राम चालकड़ी में प्लाट संख्यांक 763, 764, 765, 766, 767, 768 से होकर जाती है और प्लाट संख्यांक 757 की प्लाट संख्यांक 768, 769, 774 के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है और आरम्भिक बिन्दु "ज1" पर मिलती है।

उप ब्लाक 4 च

त 1–थ 1 रेखा ग्राम चालकड़ी में प्लाट संख्यांक 77 की प्लाट संख्यांक 776 के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है और बिन्दु थ 1 पर मिलती है।

थ 1–द 1-ध 1त 1 रेखाएं ग्राम चालकड़ी में प्लाट संख्यांक 779 की प्लाट संख्यांक 814 के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है और आरम्भिक बिन्दु त 1 पर मिलती है ।

टिप्पण :—ब्लाक 4क से 4च खनन अधिकार संबंधी ब्लाक हैं और ये उपब्लाक 4 क के सभी अधिकार संबंधी ब्लाक के साथ सम्मिलित सीमा बनाते हैं ।

[सं. 19/11/83-सी एल/सी ए]

समय सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd September, 1985

S.O. 4269 - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No.S.O. 3295 dated the 27th August, 1982 published in the Gazette of India, under Part II, section 3, sub-section (ii) dated the 18th September 1982, under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the report aforesaid and after consulting the Government of Bihar, is satisfied that :—

(a) the land measuring 1743.05 acres (approximately) or 705.37 hectares (approximately) described in Schedule 'A' appended hereto, and;

(b) the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in the land measuring 21.95 acres (approximately) or 8.88 hectares (approximately) described in Schedule 'B' appended hereto;

should be acquired.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands measuring 1743.05 acres (approximately) or 705.37 hectares (approximately) described in the said schedule 'A' and the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in the lands measuring 21.95 acres (approximately) or 8.88 hectares (approximately) described in the said schedule 'B'; are hereby acquired.

The plan of the area covered by this notification may be inspected into the Office of the Deputy Commissioner, Giridih (Bihar) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the Office of the Central Coalfields Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

Schedule - A

Chalkari Block Extn.—II

Sub-Block III & IV

East Bokaro Coalfield

Drg. No. Rev/10/83

Dated : 4-2-83

(Showing lands acquired)

All Rights

Serial number	Village	Thana number	Thana	District	Area	Remarks
1.	Jaridih	Nawadih (Bermo)	19	Giridih	590.00	Part

Total area:—590.00 acres (approxmately or 238.76 hectares (approximately)

Plot numbers acquired in village Jaridih :- 6 (Part), 20(Part), 54(Part), 55(Part), 56(Part), 57(Part), 58 to 228, 229(Part), 230 231(Part), 232(Part), 233, 234, 235 (Part), 237(Part), 238, 239, 240, 241, 242(Part), 290(Part), 375(Part), 376(Part), 377, 378 (Part), 379, 380, 381(Part), 382(Part), 383(Part), 404(Part), 405 to 419, 420(Part), 421(Part), 422 to 429, 430(Part), 431(Part), 432, 433, 434(Part), 435 to 441, 442(Part),443(Part), 444(Part), 445 to 497, 498, 499 to 532, 533(Part), 534(Part), 538(Part) 539, 540(Part), 541 to 565, 566(Part), 567 to 575, 576(Part), 577, 578(Part), 579(Part), 582(Part), 583 to 593, 594(Part), 596(Part) 597(Part), 598(Part), 599, 600, 601, 602(Part), 645(Part), 646 (Part), 647(Part), 648(Part), 867(Part), 872(Part), 874(Part), 876(Part), 877 to 879, 880(Part), 881(Part), 882, 883(Part), 884(Part), 885 to 892, 893(Part), 894, 895, 896, 897(Part), 898 to 971, 972(Part), 973, 974(Part), 980(Part), 984(Part), 985(Part), 986(Part), 987(Part), 988(Part), 1000(Part), 1001 to 1005, 1006(Part), 1007(Part), 1009(Part), 1012(Part), 1013(Part), 1014 (Part), 1015, 1016(Part), 1027(Part), 1029(Part), 1030(Part), 1031 to 1033, 1034(Part), 1035(Part), 1036(Part), 1037 to 2064, 2066 to 2325, 2327, 2328, 2329 & 2332(Part).

Boundary description :

A–B line passes along the part left bank of Kunar River in village Jaridih and meets at point "B".

B–C line passes along the part left bank of Damodar River in village Jaridih and meets at point 'C'.

C–D line passes along the part right bank of Koel Jaria Nadi and meets at point 'D'.

D–E–F lines pass through plot numbers : 867, 884 883, 881, 880, 872, 876, 874, 893, 986, 987, 985, 984, 980, 897, 974, 972, 1000, 1009, , 1006, 1007, 1012, 1013, 1014, 1027, 1016, 1027, 1035, 1036, 1024, 1029, 1020, 1029, 988, 534, 533, 538, 540, 602, 598, 597, 596 594, 290, 645, 646 & 647 in village Jaridih (which forms part common boundary with Bokaro Colliery) and meets at point 'F'.

F–G–H–I–J–A lines pass through plot numbers : 647, 648, 290, 582, 576, 578, 579, 566, 434, 404, 382, 381, 383, 378, 376, 375, 420, 421, 430, 431, 434, 442, 434, 443, 444, 229, 231, 232, 235, 237, 242, 20, 54, 2332, 54, 56, 55, 57 and 6 in village Jaridih (forms common boundary with Railway acquired land) and meets at starting point 'A'.

All Rights Sub-Block-IV

Serial number	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1.	Chalkari	Petarbar	46	Giridh	1153.05	Part

Total area : 1153.05 acres (approxmately)
or 466.61 hectares (approximately)

Plot numbers acquired in village Chalkari :—2 to 473, 475 to705, 713 to 721, 723(Part), 725, 743, 744, 745, 746(Part), 747 (Part), 749(Part), 750(Part), 751 to 756, 757(Part), 758(Part), 759, 760, 761(Part), 763(Part), 764(Part), 765(Part), 767(Part), 768(Part), 769 to 774, 776, 781(Part), 782 to 797, 798(Part), 799 to 937, 939 to 1426, 1427(Part),1431(Part), 1432, 1433, 1434(Part), 1435(Part), 1436 to 1443, 1444(Part), 1445 to 1539, 1540(Part), 1541(Part), 1542(Part), 1543 to 1546, 1547(Part), 1548 to 1558, 1559(Part), 1561(Part), 1562 to 1564, 1565(Part), 1566(Part), 1567(Part), 1599(Part), 1600(Part), 1601 to 1605, 1606(Part), 1615(Part), 1622(Part), 1623, 1624(Part),1625(Part), 1626, 1627, 1628, 1629, 1630(Part), 1631, 1632, 1633, 1634(Part), 1635(Part), 1636, 1637, 1638, 1639, 1640(Part), 1641(Part), 1642 1643, 1644, 1645 to 2381, 2382 (Part), 2383 to 2400, 2401(Part), 2505(Part), 2623(Part), 2624(Part), 2625 to 2630, 2631(Part), 2632(Part), 2707(Part), 2708 to 2999, 3000(Part), 3001, 3002 (Part), 3007(Part), 3008 to 3081, 3082(Part), 3083(Part), 3091 (Part), 3092(Part), 3093(Part), 3094(Part), 3101(Part), 3120 (Part), 3124(Part), 3125(Part), 3127 (Part), 3128, 3129, 3130, 3131(Part), 3132, 3133, 3134, 3135(Part), 3136(Part), 3138(Part), 3139(Part), 3185(Part), 3136(Part), 3187 to 3189, 3190(Part), 3191, 3192, 3193(Part), 3201(Part), 3202, 3203(Part), 3204, 3205(Part), 3206 to 3238, 3239(Part), 3240 to 3457, 3458(Part), 3459 to 3524, 3525(Part), 3526(Part), 3527, 3528(Part), 3529 to 3550, 3551(Part), 3552 to 3555, 3556(Part), 3575(Part), 3576(Part), 3577(Part), 3581 (Part), 3582(Part), 3583(Part), 3584 to 3586, 3587(Part), 3589 (Part), 3598(Part), 3600(Part), 3601, 3602(Part), 3603(Part), 3604(Part), 4150, 4151, 4153, 4154, 4155, 4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4165, 4167, 4174, and 4175.

Boundary description :

K–L	line passes through plot nos. 3589, 3587, 3583, 3587, 3582, 3581, 3525, 3526, 3576, 3577, 3526, 3528, 3576, 3598, 3600 and 3603 in village Chalkari (forms common boundary with Chalkari Block Extn.) and meets at point 'L'.
L–M–N–O–	lines, pass through plot nos. 3603, 3602, 3604, 3576, 3575, 3458, 3556, 3458, 3551, 3458, 3205, 3186, 3185, 3186, 3185, 3190, 3205, 3193, 3205, 3201, 3203, 3135, 3136, 3138, 3139, 3131, 3139, 3131, 3120, 3127, 3125, 3124, 3101, 3239, 3002, 3000, 3002, 3007, 3094, 3092, 3093, 3091, 3083, 3082, 2707, 2632, 2631, 2630, 2624, 2623, 2505, 2401, 2382, 1641, 1640, 1635, 1634, 1630, 1615, 1624, 1625, 1624, 1622, 1606, 1600, 1599, 1427, 1435, 1434, 1431, 1444, 1540, 1541, 1547, 1547, 1566, 1567, 1566, 1565, 1559 and 1561 in village Chalkari and meets at point 'O'.
O–P	line passes along part left bank of Nalla in village Chalkari and meets at point 'P'.
P–K	line passes along western and southern bank of Damodar river in village Chalkari and meets at starting point 'K'.

SCHEDULE B

Sub-Block IVA, IVB, IVC
IVD, IVE, IVF

(Showing lands where rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win work and carry away minerals are acquired).

Mining Rights

Sub-Block	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
IVA	Chalkari	Petarbar	46	Giridih	0.80	Part
IVB	-do-	-do-	-do-	-do-	9.50	"
IVC	-do-	-do-	-do-	-do-	0.88	"
IVD	-do-	-do-	-do-	-do-	0.77	"
IVE	-do-	-do-	-do-	-do-	9.55	"
IVF	-do-	-do-	-do-	-do-	0.45	"

Total area :—21.95 acres (approximately)
or 8.88 hectares (approximately)

Plot numbers acquired in village Chalkari :

In sub-block IV-A : 726, 727 and 798 (Part).

In sub-block IV-B : 706 to 712 722, 723(Part), 724, 728 to 737.

In sub-block IV-C : 738 to 742.

In sub-block IV-D : 746(Part), 747(Part), 748, 749(Part) 750(Part).

In sub-block IV-E : 757(Part), 758(Part), 761(Part), 762, 763 (Part), 764(Part), 765(Part), 766(Part), 767(Part), 768(Part), 777, 778, 780 and 781(Part).

In sub-block IV-F : 779.

Boundary description :—

Sub-Block IV-A

Q–R	line passes through plot number 798 and forms common boundary with plot numbers 726 and 638 and meets at point 'R'.
R–S–T	lines forms common boundary of plot numbers 726 and 727 with plot number 798 and meets at point 'T'.
T–Q	line passes through plot number 798 and meets at starting point 'Q'.

Sub-Block IV-B

U–V	line passes through plot number 723, then forms common boundary of plot number 722 with plot numbers 723, 720, 721 plot number 711 with plot numbers 721, 713 and 714 of village Chalkari and meets at point 'V'.
V–W	line forms common boundary of plot number 711 with plot numbers 714, 701, plot number 708 with plot numbers 702, 703, 704, and 705 plot number 707 with plot number 704, plot number 706 with plot number 705, plot number 709, with plot number 705 of village Chalkari and meets at point 'W'.
W–X	line forms common boundary of plot numbers 709 & 736 with plot number 507 and also through plot 507 in village Chalkari and meets at point 'X'.

X–Y	line forms common boundary of plot 736, 737, 732, 728, 729, with plot number 798 and meets at point 'Y'
Y–U	line forms common boundary of plot numbers 732, 730, 722, 724, with plot number 798 and meets at starting point 'U'.

In sub-block-IV-C

Z–A	line forms common boundary of plot numbers 742, 741, 740, 739, 738 with plot number 798 in village Chalkari and meets at point 'A1'
A1–B1–C1	lines forms common boundary of plot numbers 738, 739, 740, 741, and 742 with plot numbers 774 in village Chalkari and meets at point 'C1'
C-1–Z	line forms common boundary with plot number 742 and 798 and meets at starting point 'Z'.

Sub-Block-IV-D

D1–E1	line forms common boundary with plot numbers 746 and 774 in village Chalkari and meets at point 'E1'.
E1–F1	line forms common boundary of plot numbers 746 and 748 with plot numbers 750 and through plot number 749 in village Chalkari and meets at point 'F1'.
F1–G1	line passes through plot number 750, then forms common boundary of plot numbers 748, 747, with plot number 774 in village Chalkari and meets at point 'G1'
G1–D1	line passes through plot numbers 747, 746 in village Chalkari and meets at starting point 'D1'.

Sub-Block-IV-E

H1–I1	line forms common boundary with plot numbers 757 and 774 in village Chalkari and meets at point 'I1'.
I1–J1	line forms common boundary with plot numbers 757 & 756 then passes through plot numbers 757, 758, 757, 761, 781 in village Chalkari and meets at point 'J1'.
J1–K1–L1	lines forms part common boundary of plot numbers 778 and 781, common boundary with plot number 780 with plot numbers 781 and 814 and meets at ponint 'L1'.
L1–M1–N1	lines forms common boundary of plot numbers 780, 778 with plot nos. 814, plot no. 777 with plot no. 776, plot no. 778 with plot no. 776, plot numbers 781 & 762 with plot number 776 in village Chalkari and meets at point 'N1'.
N1–O1	line forms common boundary of plot number 762 with plot number 772 and part boundary of 763 in village Chalkari, and meets at point '01'.
O1–H1	line passes through plot numbers 763, 764, 765, 766, 767, 768 and forms common boundary of plot number 757 with plot nos. 768, 769, 774 in village Chalkari and meets at starting point 'H .

Sub-Block-IV-F

P1–Q1	line forms common boundary of plot number 779 with plot number 776 in village Chalkari and meets at point 'Q1'.
Q1–R1–S1–P1	lines forms common boundary of plot number 779 with plot number 814 in village Chalkar and meets at starting point 'P1'.

Note : Block IV-A to IV-F are mining rights block and forms common boundary with All rights Block of Sub-Block IV

[No. 19/11/83,CL/CA]
SAMAY SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1985

शुद्धिपत्र

का.आ. 4270.—भारत के राजपत्र तारीख 2 फरवरी, 1985 के भाग 2, खंड 3, उप खंड (ii) में पृष्ठ 447 से 450 पर प्रकाशित भारत सरकार के इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना का.आ. सं. 420, तारीख 16 जनवरी, 1985 में—
पृष्ठ 448 पर--अनुसूची में :—

(1) अनुक्रम स. 24, ग्राम स्तंभ में "छूटही" के स्थान पर "छुट्टी" पढ़िये ।
सीमा वर्णन में :--

(2) क–ख रेखा में "जुनापानी बिलावर कलां आरक्षित गोवारी" के स्थान पर "जुनापानी, बिलावर कलां और बिलावर कलां आरक्षित वन, मोवारी" पढ़िये ।

(3) घ–ङ रेखा में "केलावरी" के स्थान पर "केवलारी" पढ़ें ।

(4) ज--झ रेखा में "तलाबादी" के स्थान पर और जहां कहीं यह शब्द प्रयुक्त हुआ हो, उसके स्थान पर "तालाबदी" पढ़िये ।
पृष्ठ 449 पर—

(5) रेखा श–ष में--"चुनापानी" के स्थान पर "जुनापानी" पढ़िए ।

[सं. 43019/17/84-सी.ए.]

New Delhi, the 21st August, 1985

CORRIGENDUM

S.O. 4270.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Steel, Mines and Coal in S.O. No. 420 dated 16th January, 1985, published at pages 447 to 450 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 2nd February, 1985—

at page—449,

In the Schedule—

(1) in Sl. No. 1 in column Area in hectares for "891.771" read "891.717".

(2) in Sl. No. 3 for "Sagonia" read "Sagoniya".

(3) in Sl. No. 7 in column villages for "Bilwar" read "Bilawar".

at page 450

In Boundary Description—

(1) in line A-B for "Janapani" read "Junapani".

(2) in line C-D for "Kotakhadi" read "Kotakhari".

(3) in line E-F for "Dipraj" read "Pipraj" and for "Nazrpur" read "Nazarpur".

(4) in line O-P for "Sangoniya" read "Sagoniya".

(5) in line P-Q for "Ghorwari Kalan" read "Ghorawari Kalan".

(6) in line Q-A for "Ghaikhapa" read "Ghatkhapa".

All persons interested in the lands covered by this notification or shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Western Coalfields Limited, Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440001 within ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 43019/17/84-CA]

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1985

का. आ. 4271:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है,

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक (ड्राइंग सं. एस. डी./1952 तारीख 10-6-85) का निरीक्षण उपायुक्त जिला गोड्डा (बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक 1, काउन्सिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में या निदेशक (नियमित योजना और परियोजनाएं) ईस्टर्न कोलफिल्डस लिमिटेड, सेक्टोरिया डाकघर—दिशेरगढ़, जिला बर्दवान (पश्चिमी बंगाल) के कार्यालय में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, निदेशक (नियमित योजना और परियोजनाएं) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सेक्टोरिया डाकघर—दिशेरगढ़, जिला बर्दवान (पश्चिमी बंगाल) को भेजेंगे।

अनुसूची

ब्लाक—1 से 9 तक

राजमहल कोयला क्षेत्र

ड्राइंग सं. एस. डी./1952

तारीख : 10-6-85

ब्लाक सं.	क्रम सं.	मौजा (ग्राम)	थाना सं. पुलिस स्टेशन थाना	जिला	क्षेत्र एकड़ में	टिप्पणियां
1. (1)		बैलगामा	39 बी डब्ल्यू सिमरा-1	गोड्डा	36.87	भाग
(2)		चितकोठी	38 —यथोक्त—	—यथोक्त—	16.10	—यथोक्त—
(3)		घाट नीमा	37 —यथोक्त—	—यथोक्त—	14.83	—यथोक्त—
(4)		नीमचला	41 —यथोक्त—	—यथोक्त—	30.37	—यथोक्त—
				योग :	98.17	एकड़
2. (1)		नीमचला	41 बी. डब्ल्यू. सिमरा—1	गोड्डा	13.05	भाग
(2)		सुआरमारी	36 —यथोक्त—	—यथोक्त—	1.98	—यथोक्त—
				योग :	15.03	एकड़

3. (1) नीमफला	41	बी. डब्ल्यू. सिमरा–1	गोड्या	2.40	भाग
(2) सुआरमारी	36	–यथोक्त–	–यथोक्त–	26.23	–यथोक्त–
(3) हिजूकीता	42	–यथोक्त–	–यथोक्त–	50.27	–यथोक्त–
			योग :	78.90	एकड़
4. बड़ा सिमरा	33	बी. डब्ल्यू. सिमरा–1	गोड्डा	123.90	भाग
			योग :	123.90	एकड़
5. छोटा सिमरा	34	बी. डब्ल्यू. सिमरा–1	गोड्डा	4.27	भाग
			योग :	4.27	एकड़
6. छोटा सिमरा	34	बी. डब्ल्यू. सिमरा–1	गोड्डा	96.12	भाग
			योग :	96.12	एकड़
7. (1) तेतरिया	709	महागामा	गोड्डा	7.16	भाग
(2) अकासनी	705	–यथोक्त–	–यथोक्त–	19.20	–यथोक्त–
(3) छोटा सिमरा	34	बी. डब्ल्यू. सिमरा–1	–यथोक्त–	16.62	–यथोक्त–
(4) केंदुआ	30	–यथोक्त–	–यथोक्त–	62.74	–यथोक्त–
(5) तेतरिया	31	–यथोक्त–	–यथोक्त–	13.75	–यथोक्त–
(6) कुशमाहा	708	महागामा	–यथोक्त–	15.52	–यथोक्त–
(7) घाट सिमरा-चिठ	35	बी. डब्ल्यू. सिमरा–1	–यथोक्त–	3.77	–पूर्ण–
(8) केंदुआकिता	707	महागामा	–यथोक्त–	1.98	भाग
			योग :	140.74	एकड़
8. महागामा	700	महागामा	गोड्डा	4.18	भाग
			योग :	4.18	एकड़
9. लटरिया	690	महागामा	गोड्डा	42.73	भाग
			योग.	42.73	एकड़

पूर्ण योग :—604.04 एकड़ (लगभग)
या 244.446 हैक्टर (लगभग)

सीमा वर्णन

ब्लाक—1

क1—क2 (उत्तर) रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में, मौजा तेलगामा के प्लाट सं० 641 के उत्तर-पश्चिम कोने से होकर जाती है। तेलगामा से होकर नीमकला के पश्चिमी सीमा पर, बिन्दु क 2 पर मिलती है।

क2—क3 (पूर्व) रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में, मौजा तेलगामा की पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु क 3 पर मिलती है।

क3—क4 (पूर्व) रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में, मौजा नीमकला से होकर जाती है और घाट नीमा की उत्तरी सीमा पर, बिन्दु क 4 पर मिलती है।

क4—क5—क6 (पूर्व) रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में, मौजा घाट नीमा की पूर्वी सीमा से होकर उसके साथ-साथ जाती है और बिन्दु क 6 पर मिलती है।

क6—क7—क8 (दक्षिण) रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में, घाट नीमा और नीमकला के बीच की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ चलते हुए नीमकला से होकर, घाट नीमा और चित्रकोठी के बीच की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ चलकर चित्रकोठी से होकर जाती है और चित्रकोठी के प्लाट सं. 333 के दक्षिण-पश्चिमी कोने पर, बिन्दु क 8 पर मिलती है।

क8—क9—क1 (पश्चिम) रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में, मौजा चित्रकोठी और तेलगामा से होकर जाती है और आरम्भिक बिन्दु क1 पर मिलती है।

ब्लाक—2

ख1—ख2 (उत्तर) रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में, मौजा नीमकला के प्लाट सं. 259 के उत्तर पश्चिमी कोने से नीमकला से होकर जाती है और प्लाट सं. 784 के उत्तर-पूर्व कोने पर बिन्दु ख2 पर मिलती है।

ख2—ख3 (पूर्व) रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में, मौजा नीमकला और सुआरमारी से होकर जाती है और नीमकला और सुआरमारी के बीच की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु ख3 पर मिलती है।

ख3—ख4—ख5 (पूर्व) रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में, नीमकला और सुआरमारी के बीच की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ चलकर सुआरमारी और नीमकला से होकर जाती है और नीमकला के प्लाट सं० 363 के दक्षिण-पूर्वी कोने पर, बिन्दु ख5 पर मिलती है।

ख5—ख6 (दक्षिण) रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में मौजा नीमकला से होकर जाती है और नीमकला के प्लाट सं. 324 के दक्षिण-पश्चिम कोने पर, बिन्दु ख6 मिलती है।

ख6—ख1 (पश्चिम) रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में, मौजा नीमकला से होकर जाती है और आरम्भिक बिन्दु ख 1 पर मिलती है।

ब्लाक—3

ग1—ग2 (उत्तर) रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में नीमकला के प्लाट सं. 497 के दक्षिण-पश्चिम कोने से जाती है, नीमकला से होकर और नीमकला के प्लाट सं. 751 के उत्तर-पूर्वी कोने पर बिन्दु ग 2 पर मिलती है।

ग2—ग3 (पूर्व) रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में गोड्डा पीरपैंती मार्ग की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ, मौजा नीमकला और हिजूकित्ता में से होकर जाती है और हिजूकित्ता के प्लाट सं. 126 के उत्तर-पूर्वी कोने पर बिन्दु ग 3 पर मिलती है।

ग3—ग4 (पूर्व) रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में, हिजूकित्ता में से होकर जाती है और हिजूकित्ता के प्लाट सं. 506 के उत्तर-पूर्वी कोने पर, बिन्दु ग 4 पर मिलती है।

ग4—ग5 (पूर्व) रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में, हिजूकित्ता में से होकर जाती है और हिजूकित्ता के प्लाट सं. 514 के दक्षिण-पूर्वी कोने पर बिन्दु ग 5 पर मिलती है।

ग5—ग6 (दक्षिण) रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में हिजूकित्ता में से होकर जाती है और हिजूकित्ता के प्लाट सं. 144 के दक्षिण-पश्चिमी कोने पर बिन्दु ग 6 पर मिलती है।

ग6—ग7 (दक्षिण) रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में, मौजा हिजूकित्ता और सुआरमारी के बीच की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और सुआरमारी के प्लाट सं. 186 के दक्षिण-पूर्व कोने पर बिन्दु ग 7 पर मिलती है।

ग7—ग8 (दक्षिण) रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में सुआरमारी में से होकर जाती है और सुआरमारी और घाट सिमरा के बीच की सम्मिलित सीमा पर, सुआरमारी के प्लाट सं. 172 के दक्षिण-पश्चिमी कोने पर, बिन्दु ग 8 पर मिलती है।

ग8–ग1 (पश्चिम)	रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में, मौजा सुआरमारी और नीमकला में से होकर जाती है और आरम्भिक बिन्दु ग। पर मिलती है।

ब्लाक—4

घ1–घ2 (उत्तर)	रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में, मौजा बड़ा सिमरा के प्लाट सं. 352 के उत्तर-पश्चिमी कोने से बड़ा सिमरा और हिजूकित्ता के बीच की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बड़ा सिमरा के प्लाट सं. 395 के उत्तर-पूर्वी कोने पर, बिन्दु घ पर मिलती है।
घ2–घ3–घ4 (पूर्व)	रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में, बड़ा सिमरा और रंगमटिया के बीच की सम्मिलित सीमा और बड़ा सिमरा और बड़ा भराई के बीच की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बोअरीजार मार्ग की उत्तरी सीमा पर, बिन्दु घ 4 पर मिलती है।
घ4–घ5 (दक्षिण)	रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में बोअरीजार मार्ग की उत्तरी सीमा के साथ-साथ जाती है और बड़ा सिमरा के प्लाट सं. 686 के दक्षिण-पश्चिमी कोने पर बिन्दु घ 5 पर मिलती है।
घ5–घ6–घ1 (पश्चिम)	रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में, मौजा बड़ा सिमरा में से होकर जाती है और आरम्भिक बिन्दु घ 1 पर मिलती है।

ब्लाक—5

ङ. 1—ङ. 2 (उत्तर)	रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में मौजा छोटा सिमरा के प्लाट सं. 122 के उत्तर-पश्चिम कोने से प्लाट सं. 126 के दक्षिण-पश्चिमी कोने तक जाती है और बिन्दु ङ 2 पर मिलती है।
ङ2–ङ3 (पूर्व)	रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में, छोटा सिमरा में से होकर जाती है और छोटा सिमरा के प्लाट सं. 161 के दक्षिण-पूर्वी कोने पर बिन्दु ङ 3 पर मिलती है।
ङ3–ङ4 तक (दक्षिण)	रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में, छोटा सिमरा में से होकर जाती है और छोटा सिमरा के प्लाट सं. 112 के दक्षिण-पश्चिम कोने पर बिन्दु ङ 4 पर मिलती है।
ङ4–ङ1 (पश्चिम)	रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में छोटा सिमरा में से होकर जाती है और आरम्भिक बिन्दु ङ 1 पर मिलती है।

ब्लाक—6

च1–च2 (उत्तर)	रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में, छोटा सिमरा के प्लाट सं. 321 के उत्तर-पश्चिमी कोने से, छोटा सिमरा में से होकर जाती है और छोटा सिमरा के प्लाट सं. 221 के दक्षिण-पूर्वी कोने पर, बिन्दु च 2 पर मिलती है।
च2–च3 (पूर्व)	रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में मौजा छोटा सिमरा में से होकर जाती है और छोटा सिमरा और बड़ा सिमरा के बीच की सम्मिलित सीमा पर छोटा सिमरा के प्लाट सं. 661 के दक्षिण-पूर्वी कोने पर बिन्दु च 3 पर मिलती ।
च3–च4 (पूर्व)	रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में छोटा सिमरा और बड़ा सिमरा के बीच की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और मौजा छोटा सिमरा के दक्षिण-पूर्वी कोने पर बिन्दु च 4 पर मिलती है।
च4–च5 (दक्षिण)	रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में, छोटा सिमरा और पहाड़पुर के बीच की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु च 5 पर मिलती है।
च5–च6 (पश्चिम)	रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में छोटा सिमरा और तेतरिया के बीच की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ चलकर छोटा सिमरा में से होकर जाती है और छोटा सिमरा के प्लाट सं. 552 के उत्तर-पश्चिमी कोने पर बिन्दु च 6 पर मिलती है।
च6–च1 (पश्चिम)	रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में, मौजा छोटा सिमरा में से होकर जाती है और आरम्भिक बिन्दु च 1 पर मिलती है।

ब्लाक—7

छ1–छ2 (उत्तर)	रेखा रेखांक पर अंकित रूप में मौजा केंटुआ के प्लाट सं. 51 के उत्तर-पश्चिमी कोने से गुजरती है केंटुआ में से होती हुई केंटुआ के प्लाट सं. 82 के उत्तर-पूर्वी कोने पर, बिन्दु छ 2 पर मिलती है।
छ2–छ3–छ4 (पूर्व)	रेखा रेखांक पर अंकित रूप में, केंटुआ में से होकर केंटुआ और छोटा सिमरा के बीच की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और केंटुआ के प्लाट सं. 211 के उत्तर-पूर्वी कोने बिन्दु छ 4 पर मिलती है।
छ4–छ5 (पूर्व)	रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में छोटा सिमरा में से होकर जाती है और छोटा सिमरा के प्लाट सं. 346 के दक्षिण-पूर्वी कोने पर, बिन्दु छ 5 पर मिलती है।

छ5–छ–6–छ–7–छ8 (दक्षिण) — रेखा रेखांक पर अंकित रूप में मौजा छोटा सिमरा तेतरिया और कुशमाहा में से होकर जाती है और कुशमाहा और अकासनी के बीच की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु छ 8 पर मिलती है।

छ8–छ9–छ10–छ11–छ12 (दक्षिण) — रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में कुशमाहा और अकासनी के बीच की सम्मिलित सीमा के भाग के साथ-साथ कुशमाहा में से होकर कुशमाहा और अकासनी की सम्मिलित सीमा के भाग के साथ-साथ चलकर अकासनी में से होते हुए अकासनी और महागामा के बीच की सम्मिलित सीमा के भाग के साथ-साथ जाती है और मौजा अकासनी के प्लाट सं. 109 के दक्षिण-पश्चिमी कोने पर, बिन्दु छ 12 पर मिलती है।

छ12–छ13 (पश्चिम) — रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में अकासनी में से होकर जाती है और केन्टुआकिसा और अकासनी के बीच की सम्मिलित सीमा पर, केंटुआकिसा के प्लाट सं. 10 के दक्षिण-पश्चिमी कोने पर बिन्दु छ 13 पर मिलती है।

छ13–छ1 (पश्चिम) — रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में केंटुआकिसा और अकासनी के बीच की सम्मिलित सीमा के भाग के साथ-साथ चलकर केंटुआ में से होती हुई आरम्भिक बिन्दु छ1 पर मिलती है।

ब्लाक—8

ज1–ज2 (उत्तर) — रेखांक पर अंकित रूप में मौजा महागामा के प्लाट सं. 253 की उत्तरी सीमा द्वारा सीमाबद्ध है।

ज2–ज3 (पूर्व) — रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में प्लाट सं. 253 के उत्तर-पूर्वी कोने से चलकर मौजा महागामा में से होकर जाती है और प्लाट सं. 1083 की दक्षिण सीमा पर बिन्दु ज 3 पर मिलती है।

ज3–ज4 (दक्षिण) — रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में महागामा के प्लाट सं. 1083 और 1019 की दक्षिणी सीमा के भाग के साथ-साथ जाती है और बिन्दु ज 4 पर जा मिलती है।

ज4–ज1 (पश्चिम) — रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में मौजा महागामा में से होकर जाती है और आरम्भिक बिन्दु ज 1 पर जा मिलती है।

ब्लाक—9

ञ1–ञ2 (उत्तर) — रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में मौजा लटरिया के प्लाट सं. 1 के उत्तर-पश्चिमी कोने से चलकर उत्तरी सीमा के भाग के साथ-साथ चलती हुई लटरिया में से होकर जाती है और प्लाट सं. 55 के उत्तर-पूर्वी कोने पर, बिन्दु ञ 2 पर मिलती है।

ञ2–ञ3 (पूर्व) — रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में लटरिया में से होकर जाती है और लटरिया की दक्षिणी सीमा पर प्लाट सं. 48 के दक्षिण-पूर्वी कोने पर, बिन्दु ञ 3 पर मिलती है।

ञ3–ञ4 (दक्षिण) — रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में मौजा लटरिया की दक्षिणी सीमा के भाग के साथ-साथ जाती है और लटरिया के दक्षिण-पश्चिमी कोने पर बिन्दु ञ 4 पर मिलती है।

ञ4–ञ1 (पश्चिम) — रेखा, रेखांक पर अंकित रूप में मौजा लटरिया की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ जाती है और आरम्भिक बिन्दु ञ 1 पर मिलती है।

[सं. 43015/20/85-सी. ए.1]

New Delhi, the 30th August, 1985

S.O. 4271—Where as it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan (Drawing No. SD/1952 dated 10-6-85) of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, District Godda (Bihar) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the office of the Director (Corporate Panning and Projects), Eastern Coalfields Limited, Sanctoria, Post Office-Dishergarh, District—Burdwan (West Bengal).

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Director (Corporate Planning and Projects), Eastern Coalfields Limited, Sanctoria, Post office-Dishergarh, District Burdwan (West Bengal) within ninety days from the date of the publication of this notification in the gazette of India.

SCHEDULE

BLOCKS—1 TO 9

RAJMAHAL COALFIELD

Drawing No. SD/1952
Dated : 10-6-85

Number of Block	Sl. No.	Mouza (village)	Thana No.	Police Station (Thana)	Distt.	Area in acres.	Remarks
1.	(1)	Telgama	39	BW Simra-I	Godda	36.87	Part
	(2)	Chitarkothi	38	-do-	-do-	16.10	-do-
	(3)	Ghat Nima	37	-do-	-do-	14.83	-do-
	(4)	Nimakala	41	-do-	-do-	30.37	-do-
					Total :—	98.17 acres.	
2.	(1)	Nimakala	41	BW Simra-I	Godda	13.05	Part
	(2)	Suarmari	36	-do-	-do-	1.98	-do-
					Total :—	15.03 acres.	
3.	(1)	Nimakala	41	BW Simra-I	Godda	2.40	Part
	(2)	Suarmari	36	-do-	-do-	26.23	-do-
	(3)	Hijnkitta	42	-do-	-do-	50.27	-do-
					Total :—	78.90 acres.	
4.		Bara Simra	33	BW Simra-I	Godda	123.90	Part
					Total :—	123.90 acres.	
5.		Chhota Simra	34	BW Simra-I	Godda	4.27	Part
					Total :—	4.27 acres.	
6.		Chhota Simra	34	BW Simra-I	Godda	96.12	Part
					Total :—	96.12 acres.	
7.	(1)	Tetaria	701	Mahagama	Godda	7.16	Part
	(2)	Akasni	705	-do-	-do-	19.20	-do-
	(3)	Chhota Simra	34	BW Simra-I	-do-	16.62	-do-
	(4)	Kendua	30	-do-	-do-	62.74	-do-
	(5)	Tetaria	31	-do-	-do-	13.75	-do-
	(6)	Kusmaha	708	Mahagama	-do-	15.52	-do-
	(7)	Ghat Simra Chhit.	35	BW Simra-I	-do-	3.77	Full
	(8)	Kenduakitta	707	Mahagama	-do-	1.98	Part
					Total :—	140.74 acres.	
8.		Mahagama	700	Mahagama	Godda	4.18	Part
					Total :—	4.18 acres.	
9.		Latariya	690	Mahagama	Godda	42.73	Part
					Total :—	42.73 acres.	

Grand Total :—604.04 acres (approximately)
or 244.446 hectares (approximately)

BOUNDARY DESCRIPTION :

BLOCK—1

A1—A2 (North)	Line passes from north west corner of plot No. 641 of mouza Telgama. Through Telgama and meets the western boundary of Nimakala at point A2, as delineated on plan.
A2—A3 (West)	Line passes along the eastern boundary of mouza Telgama and meets at point A3, as delineated on plan.
A3—A4 (East)	Line paases through mouza Nimakala and meets the northern boundary of Ghat Nima at point A4, as delineated on plan.
A4—A5—A6 (East)	Lines pass through and along the eastern boundary of mouza Ghat Nima and meet at point A3, as delineated on plan.
A6—A7—A8 (South)	Lines pass along the common boundary between Ghat Nima and Nimakola, through Nimakola, along the common boundary between Ghat-Nima and Chitarkoti, through Chitarkoti and meets at point A8, on the south west corner of plot No. 333 of Chitarkoti, as delineated on plan.
A8—A—9—A1 (West)	Lines pass through mouzas Chitarkoti and Telegama and meet at the starting point A1, as delineated on plant.

BLOCK—2

B1—B2 (North)	Line passes from north west corner of Plot No. 259 of mouza Nimakola, through Nimakola and meets at point B2 at north east corner of Plot No, 784, as delineated on plan.
B2—B3 (East)	Line passes through mouzas Nimakola and Suarmari and meets at point B3 on the common boundary between Nimakal and Suarmari, and delineated on plan.
B3—B4—B5 (East)	Lines passes along the common boundary between Nimakola and Suarmari, through Suarmari and Nimakola and meet at point B5 on the South east corner of plot No.363 of Nomakola, as delineated on plan.
B5—B6 (South)	Line passes through mouza Nimakola and meets at point B5 on the south west corner of Plot No. 1824 of Nimakola as delineated on plan.
B6—B1 (West)	Line passes through mouza Nimakola and meets at the starting point B1, as delineated on plan.

BLOCK—3

C1—C2 (North)	Line passes from south west corner of plot No. 497 of Nimakola, through Nimakola and meets at point C2, on the north east corner of plot No. 751 of Nimakola, as delineated on plan.
C2—C3 (East)	Line passes through mouzas Nimakola and Hijukita, along the western boundary of Godda-pirpaiti road and meets at point C3, on the south east corner of plot No. 126 of Hijukita, as delineated on plan.
C3—C4 (East)	Line passes through Hijukita and meets at point C4, on the north east corner of plot No. 506 of Hijukita, as delineated on plan.
C4—C5 (East)	Line passes through Hijukita and meets at point C5 on the south east corner of plot No.514 of Hijukita, as delineated on plan.
C5—C6 (South)	Line passes through Hijukita and meets at point C6, on the south west corner of plot No.144 of Hijukita, as delineated on plan.
C6—C7 (South)	Line passes along the common boundary between mouzas Hijukita and Saarmari and meets at point C7 on the south east, corner of plot No.186 of Suarmari, as delineated on plan.
C7—C8 (South)	Line passes through Suarmari and meets at point C8 on the common boundary between Suarmari and Ghat Simra at the south west corner of plot No.172 of Suarmari, as delineated on plan.
C8—C1 (West)	Line passes through mouzas Suarmari and Nimakola and meets at the starting point C1, as delineated on plan.

BLOCK—4

D1—D2 (North)	Line passes from north west corner of plot No. 352 of mouza Bara Simra, along common boundary between Bara Simra and Hijukita and meets at point D2 on the north ceast corner of plot No. 395 of Bara Simra, as delineated on plan.
D2—D3—D4 (East)	Lines pass along the commion boundary between Bara Simra and Rangamati and between Bara Simra and Bara Bharai and meet at point D4, on the northern boundary of Bearijer road,as delineated on plan.
D4—D5 (South)	Line passes along the northern boundary of Boarijar road and meets at point D5 on the south west corner of plot No. 686 of Bara Simra, as delineated on plan.
D5—D6—D1 (West)	Lines pass through mouza Bara Simra and meet at starting point D1, as delineated on plan.

BLOCK 5—	
E1—E2 (North)	Line passes from north west corner of plot No.122 to south west corner of plot No.126 of mouza Chota-Simra and meets at point E2, as delineated no plan.
E2—E3 (East)	Line passes through Chota Simra and meets at point E3, on the south east corner of plot No.161 of Chota Simra, as delineated no plan.
E3—to E4 (South)	Line passes through Chota Simra and meets at point E4, on the south west corner of plot No.112 of Chota Simra as delineated on plan.
E4—F1 (West)	Line passes through Chota Simra and meets at the starting point E1, as delineated on plan.
BLOCK—6	
F1—F2 North)	Line passes from north west coener of Plot No. 321 of Chota Simra, through Chota Simra and meets at point F2, on the south east corner of plot No. 221 of Chota-Simra, as delineated on plan.
F2—F3 (East)	Line passes through mouza Chota Simra and meets at F3, on the common boundary between Chota Simra and Bara Simra, at the south eacst corner of plot No.661 of Chota Simra, as delineated on plan.
F3—F4 (East)	Line passes along the common boundary between Chota-Simra and Bara Simra and meets at point F4, on the South east corner of mouza Chota Simra, as delineated on plan.
F4—F5 (South)	Line passes along the common boundary between Chota-Simra and Paharpur and meets at point F5, as delineated on plan.
F5—F6 (West)	Line passes along the common boundary between Chota Simra and Tetaria, through Chota Simra and meets at point F6 on the north west corner of plot No 552 of Chota Simra, as delineated on plan.
F6—F1 West)	Line passes through mouza Chota Simra and meets at the starting point F1, as delineated on plan.
BLOCK—7	
G1—G2 (North)	Line passes from north west corner of plot No. 51 of mouza Kendua, passes through Kendua and meets at point G2, on the north east corner of plot No. 82 of Kemdja, as delineated on plan.
G2—G3—G4 (East)	Lines pass through Kendua, and along the common boundary between Kendua and Chota Simra and meet at point G4, on the north east corner of plot No. 211 of Kendua as delineated on plan.
G4—G5 (East)	Line passes through Chota Simra and meets at point G5, on the south east corner of plot No.346 of Chota Simra as delineated on plan.
G5—G6—G7—G8 (South)	Lines pass through mouzas Chota Simra, Tetaria and Kusmaha and meet at point G8, on the common boundary between Kusmaha and Akasni, as delineated on plan.
G8–G9 G10-G11-G12 (South)	Lines pass along the part common boundary between Kusmaha and Akasni, through Kusmaha, along part common boundary between Kusmaha and Akasni, through Akasni, along part common boundary between Akasni Mahagama and meet at point G12, on the South west corner of plot No. 109 of mouza Akasni, as delineated on Plan.
G12—G13 (West)	Line passes through Akasni and meets at point G13 on the common boundary between Kendua Kita and Akasni on the south west corner of plot No.10 of Kendua Kita as delineated on plan.
G13—G1 (West)	Line passes along part commoa boundary between Kendua Kita and Akasni, through Kendua and meets at the starting point G1, as delineated on plan.
BLOCK—8	
H1—H2 (North)	Bounded by northern boundary of plot No. 253 of mouza Mahagama as delineated on plan.
H2—H3 (East)	Line passes from north east corner of plot No. 253, through mouza Mahagama and meets at H3, on the southern boundary of plot No. 1083, as delineated on plan.
H3—H4 (South)	Line passes along part southern boundary of plot No. 1083 and 1019 of Mahagama and meets at point H4, as delineated on plan.
H4—H1 (West)	Line passes through mouza Mahagama and meets at the starting point H1, as delineated on plan.
BLOCK—9	
J1—J2 (North)	Line passes from north west corner of plot No. 1 of mouza Latariya, along part northern boundary and through Latariya and meets at point J2, on the north eastern corner of plot No. 55, as delineated on plan.
J2—J3 (East)	Line passes through Latariya and meets at point J3, on the south boundary of Lataiya, on the south east corner of plot No. 48, as delineated on plan.
J3—J4 (South)	Line passes along the part southern boundary of mouza Latariya and meets at point J4, on the South Western corner of Latariya, as delineated on Plan.
J4—J1 (West)	Line passes along western boundary of mouza Latariya and meets at the starting point J1, as delineated on plan.

[No. 43015/20/85-CA]

का. आ. 4272 :—केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 11 जून, 1983 में, पृष्ठ 2457-58 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 2523 तारीख 27 मई, 1983 को विखंडित करती है।

[सं. 19/5/83-सी एल./सी. ए.]

टी. सी. ए. श्रीनिवासन, निदेशक

S.O 4272.—In exercise of powers conferred by sub-section (i) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India, in the Ministry of Energy (Department of Coal), No S.O 2523, dated the 27th May, 1983 published in the Gazettee of India, Part-II-Section 3 -Sub-section (ii) dated the 11th June, 1983 at pages 2458-2460.

[No. 19/5/83-CL/CA]

T.C.A. SRINIVASAN, Director

खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1985

का.आ. 4273 :—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सीएम/एल—1043225 जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिये गये हैं 85-02-15 से रद्द कर दिया गया है और वापस ले लिया माना जाये।

अनुसूची

क्र.सं.	लाईसेंस संख्या और दिनांक	लाईसेंसधारी का नाम और पता	रद्द लाईसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	सम्बद्ध भारतीय मानक
1.	सीएम/एल—1043225 82-02-26	मैसर्स स्वास्तिक पेस्टीसाइड्स, एंड केमिकल्स, भोपा रोड, मुज्जफरनगर 251 001	एल्ड्रिन ईसी 30%	IS : 1307—1975 एल्ड्रिन पायसनीय सान्द्र की विशिष्ट (पहला पुनरीक्षण)

[सी एम डी/55:0143225]

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 12th July, 1985

S.O. 4273 :—In pursuance of sub-regulation (4) of regulagion 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that licence No CM/L-1043225 particulars of which are given below has been cancelled with effect from 85-02-15

THE SCHEDULE

Sl No	Licence No. and Date	Name and address of the licensee	Article/Process covered by the licences cancelled	Relevant Indian Standards
1	CM/L-1043225 82-02-26	M/s Swastik Pesticides & Chemicals, Bhopa Road, Muzaffar Nagar-251001	Aldrin EC 30%	IS : 1307-1973 Specification for Aldrin Emulisifiable Concentrates (First Revision)

CMD/55: 0143225]

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1985

का.आ. 4274 भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम, 1955 विनियम 7 के उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विभिन्न उत्पादों के लिये मुहर लगाने की प्रति इकाई फीस अनुसूची में दिये गये ब्यौरों के अनुसार निर्धारित की गई है और ये प्रत्येक के आगे दी गई तारीख से लागु होंगी।

अनुसूची

क्र.सं.	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	सम्बद्ध भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	प्रति इकाई	मुहर लगाने की प्रति इकाई फीस	तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	कटबैक बिटुमेन	IS : 217–1961 कटबैक बिटुमन की विशिष्टि (पुनरीक्षण)	एक टन	(i) पहली 1000 इकाईयों पर 3.00 रु. प्रति इकाई (ii) 1001 से 2000 इकाईयों पर 1.50 रु. प्रति इकाई (iii) 2001 वीं इकाई और इससे अधिक के लिए 75 पैसे प्रति इकाई	1984-03-16
1	2	3	4	5	6
2.	दाब रहित चुल्हे	IS : 2980–1979 दाब रहित चुल्हों की विशिष्ट (पहला पुनरीक्षण)	एक चुल्हा	(i) पहली 5000 इकाईयों के लिए 25 पैसे प्रति इकाई (ii) 5001 तथा इससे अधिक इकाईयों के लिए 15 पैसे प्रति इकाई	1984-09-01

[सं. सी एम डी/13 : 10]

New Delhi, the 12th August, 1985

S.O. 4274—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fee(s) per unit for various products details of which are given in the Schedule hereto annexed, have been determined and the fee(s) shall come into force with effect from the dates shown against each:

SCHEDULE

Sl No	Product/Class of Product	No and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking fee per unit	Date of effect
1	2	3	4	5	6
1	Cutback bitumen	IS:217-1961 Specification for cutback bitumen (revised)	One Tonne	(i) Rs 3 00 per unit for the first 1000 units; (ii) Rs 1 50 per unit for the first 100 1st to 2000 units and (iii) 75 Paise per unit for the 200 1st unit and above	1984-03-16
2	Non-pressure stoves	IS:2980-1979 Specification for non-pressure stoves (first revision)	One Stove	(i) 25 Paise per unit for the first 5000 units and (ii) 15 Paise per unit for the 500 1st unit and above	1984-09-01

[No CMD/13:10]

का. आ. 4275.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 8 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन 454 लाइसेंसों के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, उनका मार्च, 1984 में नवीकरण किया गया है ।

अनुसूची

क्रम	सी एम एल संख्या	वैध : तक
(1)	(2)	(3)
1.	0013110	1985-01-15
2.	0017017	1985-03-31
3.	0017219	—वही—
4.	0024418	1985-03-15
5.	0036526	1985-02-28
6.	0039128	1985-03-31
7.	0051522	—वही—
8.	0065432	1985-02-28
9.	0094843	1984-11-30
10.	0113821	1985-03-15
11.	0121012	1985-02-15
12.	0123420	1985-03-31
13.	0132320	1984-12-31
14.	0147838	1985-01-31
15.	0149438	1985-02-28
16.	0159138	1985-03-31
17.	0160527	1985-03-15
18.	0160830	1985-03-31
19.	0165032	1985-03-15
20.	0166034	1985-03-31
21.	0179144	1985-03-31
22.	0167850	1984-12-31
23.	0189551	1985-01-31
24.	0221925	—वही—
25.	0227331	1985-02-28
26.	0228939	1985-03-15
27.	0230522	1985-03-31
28.	0233528	—वही—
29.	0237132	1985-01-15
30.	0237738	1985-02-15
31.	0257542	1985-03-15
32.	0259142	—वही—
33.	0262131	1985-03-31
34.	0262838	—वही—
35.	0265945	—वही—
36.	0271132	1985-01-31
37.	0271334	1984-11-30
38.	0273944	1985-02-15
39.	0286145	1985-01-15
40.	0287652	1985-03-31
41.	0287854	1985-01-31
42.	0292241	1985-02-15
43.	0294144	1985-02-28
44.	0300315	1985-03-31
45.	0301418	—वही—
46.	0308533	—वही—
47.	0331932	1985-01-31
48.	0334736	1985-03-15
49.	0335031	—वही—
50.	0357344	1985-03-31
51.	0364947	1985-03-15
52.	0365040	1984-12-31
53.	0370538	1985-02-15
54.	0370041	—वही—
55.	0371439	—वही—
56.	0371540	1985-02-15
57.	0373039	1985-02-28
58.	0373342	1985-03-15
59.	0373645	—वही—
60.	0374344	—वही—
61.	0374647	—वही—
62.	0374849	—वही—
63.	0376449	1985-03-31
64.	0376550	—वही—
65.	0376954	—वही—
66.	0377148	—वही—
67.	0377350	—वही—
68.	0377451	—वही—
69.	0377552	—वही—
70.	0378958	1985-01-32
71.	0379051	—वही—
72.	0379152	—वही—
73.	0379253	—वही—
74.	0379354	—वही—
75.	0390140	—वही—
76.	0394552	1985-02-28
77.	0414633	1984-12-15
78.	0416132	1985-02-28
79.	0418641	1985-01-31
80.	0419845	1985-03-31
81.	0424737	1985-02-28
82.	0426539	1985-03-15
83.	0426741	1985-03-31
84.	0428644	—वही—
85.	0429040	—वही—

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
86.	0437140	1985-02-15	134.	0597667	1985-03-31
87.	0430343	1985-03-15	135.	0599267	1985-03-15
88.	0483551	—वही—	136.	0601430	1985-03-31
89.	0486254	1984-11-30	137.	0602028	—वही—
90.	0492249	1985-01-15	138.	0613235	—वही—
91.	0494051	1985-02-28	139.	0627852	1984-07-31
92.	0495558	1985-01-15	140.	0640339	1985-03-15
93.	0495861	1985-03-15	141.	0644953	1984-09-30
94.	0496762	1985-01-31	142.	0646452	1985-02-15
95.	0499667	1985-02-15	143.	0654047	1985-03-31
96.	0501123	1985-03-15	144.	0654633	1984-11-30
97.	0501830	1985-01-31	145.	0666963	1985-01-31
98.	0501931	1985-02-15	146.	0668260	1985-01-15
99.	0502024	—वही—	147.	0669060	1985-01-31
100.	0505836	1985-03-15	148.	0673051	1985-02-15
101.	0506032	—वही—	149.	0673657	—वही—
102.	0532437	1985-03-15	150.	0677261	1985-02-28
103.	0536344	—वही—	151.	0677362	1985-01-31
104.	0536647	1985-03-15	152.	0677665	1985-02-28
105.	0537043	1985-03-31	153.	0677766	—वही—
106.	0537851	1985-01-15	154.	0678364	—वही—
107.	0540537	1985-03-15	155.	0679164	—वही—
108.	0546044	1985-03-31	156.	0679467	—वही—
109.	0559558	—वही—	157.	0679568	—वही—
110.	0563751	1985-03-15	158.	0679669	—वही—
111.	0572146	1985-01-15	159.	0679770	—वही—
112.	0580145	—वही—	160.	0679871	—वही—
113.	0580953	—वही—	161.	0679972	—वही—
114.	0582957	—वही—	162.	0681151	1985-06-15
115.	0583050	1985-01-15	163.	0681252	1985-03-15
116.	0587159	1985-01-31	164.	0682153	—वही—.
117.	0588565	1985-02-15	165.	0682254	1985-03-31
118.	0589062	—वही—	166.	0682658	1985-03-15
119	0589163	—वही—	167.	0683054	—वही—
120.	0589769	—वही—	168.	0683660	—वही—
121.	0598552	—वही—	169.	0685664	—वही—
122.	0591251	1985-02-28	170.	0685765	1985-03-31
123.	0591352	1985-02-15	171.	0686060	—वही—
124.	0591453	1985-02-29	172.	0686969	—वही—
125.	0592556	1985—2-28	173.	0689672	—वही—
126.	0592859	—वही—	174.	0692136	—वही—
127.	0593558	—वही—	175.	0697469	1985-02-28
128.	0593659	—वही—	176.	0738558	1985-02-15
129.	0594257	1985-02-15	177.	0738760	1984-11-30
130.	0594560	1985-02-28	178.	0741850	1985-03-31
131.	0595966	1985-03-15	179.	0743349	1983-12-31
132.	0596463	1985-02-28	180.	0744048	1984-11-15
133.	0597465	1985-03-31	181.	0745858	1985-01-15

(1)	(2)	(3)
182.	0746456	1985-01-15
183.	0748864	1985-01-31
184.	0752956	1985-02-28
185.	0753049	—वही—
186.	0754253	—वही—
187.	0756560	—वही—
188.	0756762	—वही—
189.	0756863	—वही—
190.	0756964	—वही—
191.	0757966	—वही—
192.	0758362	—वही—
193.	0758867	1985-03-15
194.	0760046	—वही—
195.	0762959	1985-03-31
196.	0766361	—वही—
197.	0766462	—वही—
198.	0791259	1984-10-31
199.	0001943	1983-01-01
200.	0812645	1984-11-15
201.	0818354	1984-11-30
202.	0820139	1984-12-15
203.	0829460	1985-01-15
204.	0831952	1984-01-31
205.	0832247	1985-01-31
206.	0832449	1985-03-15
207.	0832550	—वही—
208.	0834958	1985-02-15
209.	0835455	1985-01-31
210.	0836053	1985-02-15
211.	0836154	—वही—
212.	0836356	—वही—
213.	0837257	1985-02-28
214.	0838966	—वही—
215.	0839059	—वही—
216.	0839665	1985-03-15
217.	0840852	1985-01-15
218.	0842048	1985-03-15
219.	0842149	1985-03-15
220.	0842351	1985-03-15
221.	0842452	—वही—
222.	0843050	—वही—
223.	0843151	—वही—
224.	0843555	—वही—
225.	0843656	—वही—
226.	0844153	—वही—
227.	0845155	1985-02-28
228.	0845357	1985-03-15
229.	0845862	1985-10-31
230.	0846561	1985-03-15
231.	0847260	—वही—
232.	0847361	—वही—
233.	0850047	—वही—
234.	0850148	1985-03-31
235.	0850249	1985-03-15
236.	0850855	1985-03-31
237.	0852750	1985-04-15
238	0857263	—वही—
239.	0870255	1985-03-31
240	0882262	1984-07-31
241.	0895473	1985-03-31
242.	0899781	—वही—
243.	0912952	1984-11-15
244.	0918459	1984-12-15
245.	0920143	—वही—
246.	0920244	—वही—
247.	0921357	—वही—
248.	0921448	—वही—
249.	0927157	1984-01-15
250.	0930651	1985-01-15
251.	0930954	1985-01-15
252.	0931754	1985-03-15
253.	0935358	1985-06-15
254.	0935560	1985-02-15
255.	0935964	—वही—
256.	0936057	1985-03-15
257.	0936966	1985-02-15
258.	0937867	—वही—
259.	0938263	1985-02-28
260.	0939164	1985-02-15
261.	0940149	—वही—
262.	0940654	—वही—
263.	0941050	—वही—
264.	0941151	1985-02-28
265.	0942557	—वही—
266.	0942961	—वही—
267.	0943256	—वही—
268.	0943660	—वही—
269.	0944460	—वही—
270.	0944965	—वही—
271.	0945260	1985-02-28
272.	0945967	—वही—
273.	0946060	—वही—
274.	0946464	—वही—
275.	0946565	—वही—
276.	0946767	—वही—

(1)	(2)	(3)
277.	0916868	1985-02-28
278.	0946969	—वही—
279.	0947565	—वही—
280.	0947466	1985-03-15
281.	0948569	1985-02-28
282.	0949066	1085-03-15
283.	0949470	—वही—
284.	0949571	—वही—
285.	0949773	—वही—
286.	0950151	— वही—
287.	0951154	—वही—
288.	0953562	1985-03-31
289.	0954059	—वही—
290.	0955061	1985-03-31
291.	0955263	1985-03-31
292.	0955566	1985-06-30
293.	0958168	1985-05-31
294.	0961258	—वही—
295.	0961359	—वही—
296.	0961763	—वही—
297.	0964264	1984-04-30
298.	0976069	1984-06-15
299.	0990366	1984-09-15
300.	0996176	1984-09-30
301.	1016222	1984-12-15
302.	1019632	1984-12-31
303.	1023724	1985-01-15
304.	1024221	1985-01-31
305.	1024322	1985-01-15
306.	1024524	—वही—
307.	1025728	—वही—
308.	1027126	—वही—
309.	1028128	1985-01-31
310.	1028330	—वही—
311.	1028734	1985-02-15
312.	1029130	—वही—
313.	1029857	—वही—
314.	1030115	—वही—
315.	1030317	—वही—
316.	1031016	—वही—
317.	1031319	—वही—
318.	1032826	—वही—
319.	1034123	—वही—
320.	1034628	1985-01-31
321.	1035731	1985-06-30
322.	1035832	1985-02-15
323.	1035933	—वही—
324.	1036026	1985-02-15
325.	1036329	—वही—
326.	1037129	—वही—
327.	1038131	1985-02-28
328.	1038636	—वही—
329.	1039032	—वही—
330.	1039234	—वही—
331.	1039335	—वही—
332.	1039537	—वही—
333.	1039638	—वही—
334.	1040219	1985-03-15
335.	1041221	—वही—
336.	1041726	—वही—
337.	1042425	—वही—
338.	1042526	—वही—
339.	1042627	1985-02-28
340.	1043225	1984-03-15
341.	1044429	—वही—
342.	1044530	1985-03-31
343.	1044833	1985-03-15
344.	1046635	—वही—
345.	1046837	1985-02-28
346.	1047536	1985-03-15
347.	1047637	—वही—
348.	1047940	—वही—
349.	1048134	—वही—
350.	1048942	—वही—
351.	1049136	1985-03-15
352.	1050424	—वही—
353.	1050929	—वही—
354.	1051123	—वही—
355.	1051325	—वही—
356.	1051628	1985-10-30
357.	1051729	1985-03-15
358.	1051830	—वही—
359.	1053430	—वही—
360.	1053531	—वही—
361.	1053733	—वही—
362.	1054533	1985-03-31
363.	1055535	—वही—
364.	1058440	1985-03-15
365.	1059846	—वही—
366.	1061033	—वही—
367.	1062936	—वही—
368.	1063130	—वही—
369.	1063433	1985-06-30
370.	1071432	1985-03-31

(1)	(2)	(3)
371.	1081738	1984-05-31
372.	1100009	1985-03-15
373.	1114020	1984-08-15
374.	1130624	1984-11-15
375.	1131828	1984-11-30
376.	1135432	—वही—
377.	1136232	1984-12-15
378.	1136838	—वही—
379.	1142934	1984-12-31
380.	1143027	—वही—
381.	1143128	—वही—
382.	1143229	—वही—
383.	1146336	1985-01-15
384.	1146639	1984-12-31
385.	1147944	1985-01-15
386.	1148239	—वही—
387.	1149140	—वही—
388.	1151026	1985-01-31
389.	1153333	1985-02-15
390.	1153838	1985-01-31
391.	1154133	1985-02-15
392.	1154638	—वही—
393.	1155034	1985-04-15
394.	1155842	1985-02-15
395.	1155943	—वही—
396.	1156238	—वही—
397.	1157442	1985-01-31
398.	1157947	1985-02-15
399.	1158040	—वही—
400.	1158141	—वही—
401.	1160330	—वही—
402.	1160431	—वही—
403.	1160633	—वही—
404.	1161433	—वही—
405.	1161534	—वही—
406.	1161938	1985-02-28
407.	1162536	—वही—
408.	1162637	—वही—
409.	1162839	—वही—
410.	1162940	—वही—
411.	1163235	—वही—
412.	1163336	—वही—
413.	1163538	—वही—
414.	1163740	—वही—
415.	1163841	—वही—
416.	1164035	—वही—
417.	1164944	—वही—
418.	1165340	1985-02-28
419.	1165441	—वही—
420.	1165643	—वही—
421.	1165946	—वही—
422.	1166140	—वही—
423.	1166241	—वही—
424.	1166847	—वही—
425.	1167243	1985-03-15
426.	1167344	—वही—
427.	1167445	—वही—
428.	1167546	—वही—
429.	1167647	—वही—
430.	1167748	—वही—
431.	1168447	—वही—
432.	1168649	—वही—
433.	1169146	—वही—
434.	11692	—वही—
435.	1169449	—वही—
436.	1169954	—वही—
437.	1170232	—वही—
438.	1170636	—वही—
439.	1170737	—वही—
440.	1170838	—वही—
441.	1170939	1985-05-31
442.	1173238	1985-03-31
443.	1173945	1985-03-15
444.	1174038	—वही—
445.	1174139	—वही—
446.	1174846	1985-03-31
447.	1174947	1985-05-15
448.	1175343	1985-03-31
449.	1175646	—वही—
450.	1175949	1985-04-15
451.	1176345	1985-03-15
452.	1176446	—वही—
443.	1193749	—वही—
454.	1210319	1984-12-15

[सं० सी एम डी 13 : 12]

S.O.4275—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that 454 licences, particulars of which

are given in the following Schedule, have been renewed during the month of March 1984.

SCHEDULE

Sl. No.	CM/L. No.	Valid upto
1	2	3
1.	0013110	1985-01-15
2.	0017017	1985-03-31
3.	0017219	-do-
4.	0024418	1985-03-15
5.	0036526	1985-02-28
6.	0039128	1985-03-31
7.	0051522	-do-
8.	0065432	1985-02-28
9.	0094843	1984-11-30
10.	0113821	1985-03-15
11.	0121012	1985-02-15
12.	0123420	1985-03-31
13.	0132320	1984-12-31
14.	0147838	1985-01-31
15.	0149438	1985-02-28
16.	0159136	1985-03-31
17.	0160527	1985-03-15
18.	0160830	1985-03-31
19.	0165032	1985-03-15
20.	0166034	1985-03-31
21.	0179144	1985-03-31
22.	0187850	1984-12-31
23.	0189551	1985-01-31
24.	0221925	-do-
25.	0227331	1985-02-28
26.	0228939	1985-03-15
27.	0230522	1985-03-31
28.	0233528	-do-
29.	0237132	1985-01-15
30.	0237738	1985-02-15
31.	0257542	1985-03-15
32.	0259142	-do-
33.	0262131	1985-03-31
34.	0262838	-do-
35.	0265945	-do-
36.	0271132	1985-01-31
37.	0271334	1984-11-30
38.	0273944	1985-02-15
39.	0286145	1985-01-15
40.	0287652	1985-03-31
41.	0287854	1985-01-31
42.	0292241	1985-02-15
43.	0294144	1985-02-28
44.	0300315	1985-03-31
45.	0301418	-do-
46.	0308533	-do-
47.	0331932	1985-01-31
48.	0334736	1985-03-15
49.	0335031	-do-
50.	0357344	1985-03-31
51.	0364947	1985-03-15
52.	0365040	1984-12-31
53.	0370538	1985-02-15
54.	0370841	-do-
55.	0371439	-do-
56.	0371540	1985-02-15
57.	0373039	1985-02-28
58.	0373342	1985-03-15
59.	0373645	-do-
60.	0374344	-do-
61.	0374647	-do-
62.	0374849	-do-
63.	0376449	1985-03-31
64.	0376550	-do-
65.	0376954	-do-
66.	0377148	-do-
67.	0377350	-do-
68.	0377451	-do-
69.	0377552	-do-
70.	0378958	1985-01-31
71.	0379051	-do-
72.	0379152	-do-
73.	0379253	-do-
74.	0379354	-do-
75.	0390140	-do-
76.	0394552	1985-02-28
77.	0414633	1984-12-15
78.	0416132	1985-02-28
79.	0418641	1985-01-31
80.	0419845	1985-03-31
81.	0424737	1985-02-28
82.	0426539.	1985-03-15
83.	0426741	1985-03-31
84.	0428644	-do-
85.	0429040	-do-
86.	0437140	1985-02-15
87.	0480343	1985-03-15
88.	0483551	do--
89.	0486254	1984-11-30
90.	0492249	1985-01-15
91.	0494051	1985-02-28
92.	0495558	1985-01-15
93.	0495861	1985-03-15
94.	0496762	1985-01-31
95.	0499667	1985-02-15
96.	0501123	1985-03-15
97.	0501830	1985-01-31
98.	0501931	1985-02-15
99.	0502024	-do-
100.	0505838	1985-03-15
101.	0506032	-do-
102.	0532437	1985-03-15
103.	0536344	-do-
104.	0536647	1985-03-15
105.	0537043	1985-03-31

1	2	3
106.	0537851	1985-01-15
107.	0540537	1985-03-15
108.	0546044	1985-03-31
109.	0559558	-do-
110.	0563751	1985-03-15
111.	0572146	1985-01-15
112.	0580145	-do-
113.	0580953	-do-
114.	0582957	-do-
115.	0583050	1985-01-15
116.	0587159	1985-01-31
117.	0588565	1985-02-14
118.	0589062	-do-
119.	0589163	-do-
120.	0589769	-do-
121.	0590552	-do-
122.	0591251	1985-02-28
123.	0591352	1985-02-15
124.	0591453	1985-02-29
125.	0592556	1985-02-28
126.	0592859	-do-
127.	0593558	-do-
128.	0593659	-do-
129.	0594257	1985-02-15
130.	0594560	1985-02-28
131.	0595966	1985-03-15
132.	0596463	1985-02-28
133.	0597465	1985-03-31
134.	0597667	d-o-
135.	0599267	1985-03-15
136.	0601430	1985-03-31
137.	0602028	-do-
138.	0613235	-do-
139.	0627852	1984-07-31
140.	0640339	1985-03-15
141.	0644953	1984-09-30
142.	0646452	1985-02-15
143.	0654047	1985-03-31
144.	0654653	1984-11-30
145.	0666963	1985-01-31
146	0668260	1985-01-15
147.	0669060	1985-01-31
148.	0673051	1985-02-15
149.	0673657	-do
150.	0677261	1985-02-28
151.	0677362	1985-01-31
152.	0677665	1985-02-28
153.	0677766	-do-
154.	0678364	-do-
155.	0679164	-do-
156.	0679467	-do-
157.	0679568	-do-
158.	0679669	-do-
159.	0679770	-do-
160.	0679871	-do-
161.	0679972	1985-02-28
162.	0681151	1985-06-15
163.	0681252	1985-03-15
164.	0682153	-do-
165.	0682254	1985-03-31
166.	0682658	1985-03-15
167.	0683054	-do-
168.	0683660	-do-
169.	0685664	-do-
170.	0685765	1985-03-31
171.	0686060	-do-
172.	0686969	-do-
173.	0689672	-do-
174.	0692156	-do-
175.	0697469	1985-02-28
176	0738558	1985-02-15
177.	0738760	1984-11-30
178.	0741856	1985-03-31
179.	0743349	1985-12-31
180.	0744048	1984-10-15
181.	0745858	1985-01-15
182.	0746456	-do-
183.	0748864	1985-01-31
184.	0752956	1985-02-28
185.	0753049	-do-
186.	0754253	-do-
187.	0756560	-do-
188.	0756762	-do-
189.	0756863	-do-
190.	0756964	-do-
191.	0757966	-do-
192.	0758362	-do-
193.	0758867	1985-03-15
194.	0760046	-do-
195.	0762959	1985-03-31
196.	0766361	-do-
197.	0766462	-do-
198.	0791259	1984-10-31
199.	0801943	1983-10-01
200.	0812645	1984-11-15
201.	0818354	1984-11-30
202.	0820139	1984-12-15
203.	0829460	1985-01-15
204.	0831952	1984-01-31
205.	0832247	1985-01-31
206.	0832449	1985-03-15
207.	0832550	-do-
208.	0834958	1985-02-15
209.	0835455	1985-01-31
210.	0836053	1985-02-15
211.	0836154	-do-
212.	0836356	-do-
213.	0837257	1985-02-28
214.	0838966	-do-
215.	0839059	-do-

(1)	(2)	(3)
216.	0839665	1985-03-15
217.	0840852	1985-01-15
218.	0842048	1985-03-15
219.	0842149	1985-03-15
220.	0842351	1985-03-15
221.	0842452	-do-
222.	0843050	-do-
223.	0843151	-do-
224.	0843555	-do-
225.	0843656	-do-
226.	0844453	-do-
227.	0845155	1985-02-28
228.	0845357	1985-03-15
229.	0845862	1985-10-31
230.	0846561	1985-03-15
231.	0847260	-do-
232.	0847361	-do
233.	0850047	-do-
234.	0850148	1985-03-31
235.	0850249	1985-03-15
236.	0850855	1985-03-31
237.	0852758	1985-04-15
238.	0857263	-do-
239.	0870255	1985-03--31
240.	0882262	1984-07-31
241.	0895473	1985-03-31
242.	0899784	-do-
243.	0912952	1984-11-15
244.	0918459	1984-12-15
245.	0920143	-do-
246.	0920244	-do-
247.	0921347	-do-
248.	0921448	-do-
249.	0927157	1984-01-15
250.	0930651	1985-01-15
251.	0930954	1985-01-15
252.	0931754	1985-03-15
253.	0935358	1985-06-15
254.	0935560	1985-02-15
255.	0935964	-do-
256.	0936057	1985-03-15
257.	0936966	1985-02-15
258.	0937867	-do-
259.	0938263	1985-02-28
260.	0939164	1985-02-15
261.	0940149	-do-
262.	0940654	-do-
263.	0941050	-do-
264.	0941151	1985-02-28
265.	0942557	-do-
266.	0942961	-do-
267.	0943256	-do-
268.	0943660	-do-
269.	0944460	-do-
270.	0944965	-do-
271.	0945260	1985-02-82
272.	0945967	1985-02-28
273.	0946060	-do-
274.	0946464	-do-
275.	0946565	-do-
276.	0946767	-do-
277.	0946868	-do-
278.	0946969	-do-
279.	0947365	-do-
280.	0947466	1985-03-15
281.	0948569	1985-02-28
282.	0949066	1985-03-15
283.	0949470	-do-
284.	0949571	-do-
285.	0949773	-do-
286.	0950151	-do-
287.	0951154	-do-
288.	0953562	1985-03-31
289.	0954059	-do-
290.	0955061	1985-03-31
291.	0955263	1985-03-31
292.	0955566	1985-06-30
293.	0958168	1985-03-31
294.	0961258	-do-
295.	0961359	-do-
296.	0961763	-do-
297.	0964264	1984-04-30
298.	0976069	1984-06-15
299.	0990366	1984-09-15
300.	0996176	1984-09-30
301.	1016222	1984-12-15
302.	1019632	1984-12-31
303.	1023724	1985-01-15
304.	1024221	1985-01-31
305.	1024322	1985-01-15
306.	1024524	-do-
307.	1025728	-do-
308.	1027126	-do-
309.	1028128	1985-01-31
310.	1028330	-do-
311.	1028734	1985-02-15
312.	1029130	-do-
313.	1029837	-do-
314.	1030115	-do-
315.	1030317	-do-
316.	1031016	-do-
317.	1031319	-do-
318.	1032826	-do-
319.	1034123	-do-
320.	1034628	1985-01-31
321.	1035731	1985-06-30
322.	1035832	1985-02-15
323.	1035933	-do-
324.	1036026	-do-
325.	1036329	-do-
326.	1037129	-do-
327.	1038131	1985-02-28

(1)	(2)	(3)
328.	1038636	1985-02-28
329.	1039032	-do-
330.	1039234	-do-
331.	1039335	-do-
332.	1039537	-do-
333.	1039638	-do-
334.	1040219	1985-03-15
335.	1041221	-do-
336.	1041726	-do-
337.	1042425	-do-
338.	1042526	-do-
339.	1042627	1985-02-28
340.	1043225	1985-03-15
341.	1044429	-do-
342.	1044530	1985-03-31
343.	1044833	1985-03-15
344.	1046635	-do-
345.	1046837	1985-02-28
346.	1047536	1985-03-15
347.	1047637	-do-
348.	1047940	-do-
349.	1048134	-do-
350.	1048942	-do-
351.	1049136	1985-03-15
352.	1050424	-do-
353.	1050929	-do-
354.	1051123	-do-
355.	1051325	-do-
356.	1051628	1985-10-30
357.	1051729	1985-03-15
358.	1051830	-o-
359.	1053430	-do-
360.	1053531	-do-
361.	1053733	-do-
362.	1054533	1985-03-31
363.	1055535	-do-
364.	1058440	1985-03-15
365.	1059846	-do-
366.	1061833	-do-
367.	1062936	-do-
368.	1063130	-do-
369.	1063433	1985-06-30
370.	1071432	1985-03-31
371.	1081738	1984-05-31
372.	1100009	1985-03-15
373.	1114020	1984-08-15
374.	1130624	1984-11-15
375.	1131828	1984-11-30
376.	1135432	-do-
377.	1136232	1984-12-15
378.	1136838	-do-
379.	1142934	1984-12-31
380.	1143027	-do-
381.	1143128	-do-
382.	1143229	-do-
383.	1146336	1985-01-15
384.	1146639	1984-12-31
385.	1147944	1985-01-15
386.	1148239	-do-
387.	1149140	-do-
388.	1151026	1985-01-31
389.	1153333	1985-02-15
390.	1153838	1985-02-31
391.	1154133	1985-02-15
392.	1154638	-do-
393.	1155034	1985-04-15
394.	1155842	1985-02-15
395.	1155943	-do-
396.	1156238	-do-
397.	1157442	1985-01-31
398.	1157947	1985-02-15
399.	1158040	-do-
400.	1158141	-do-
401.	1160330	-do-
402.	1160431	-do-
403.	1160633	-do-
404.	1161433	-do-
405.	1161534	-do-
406.	1161938	1985-02-28
407.	1162536	-do-
408.	1162637	-do-
409.	1162839	-do-
410.	1162940	-do-
411.	1163235	-do-
412.	1163336	-do-
413.	1163538	-do-
414.	1163740	-do-
415.	1163841	-do-
416.	1164035	-do-
417.	1164944	-do-
418	1165340	-do-
419.	1165441	-do-
420.	1165643	-do-
421.	1165946	-do-
422.	1166140	-do-
423.	1166241	-do-
424.	1166847	-do-
425.	1167243	1985-03-15
426.	1167344	-do-
427.	1167445	-do-
428.	1167546	-do-
429.	1167647	-do-
430.	1167748	-do-
431.	1168447	-do-
432.	1168649	-do-
433.	1169146	-do-
434.	11692	-do-
435.	1169449	-do-
436.	1169954	-do-
437.	1170232	-do-
438.	1170636	-do-

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
439.	1170737	1985-03-15	447.	1174947	1985-03-15
440.	1170838	-do-	448.	1175343	1985-03-31
441.	1170939	1985-05-31	449.	1175646	-do-
442.	1173238	1985-03-31	450.	1175949	1985-04-15
443.	1173945	1985-03-15	451.	1176345	1985-03-15
444.	1174038	-do-	452.	1176446	-do-
445.	1174139	-do-	453.	1193749	-do-
446.	1174846	1985-03-31	454.	1210319	1984-12-15

[No. CMD/13 : 12]

का. आ. 4276.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) नियम, 1955, के नियम 4 के उपनियम (1) के अनुसार, भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे अनुसूची में दी गई जिन मानक मुहरों के डिजाइन और डिजाइनों के शाब्दिक वर्णन तथा तत्संबंधी भारतीय मानक के शीर्षक दिये गये हैं, वे निर्धारित कर दिये गये हैं।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) अधिनियम, 1952 और इसके अधीन बने नियमों और विनियमों के निमित्त यह मानक चिन्ह इनके सामने दी गई तिथियों से लागू होंगे :—

अनुसूची

क्र.सं.	मानक चिन्ह की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की संख्या	मानक चिन्ह की डिजाइन का शाब्दिक विवरण	लागू होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	IS:217 ISI	कटबैक बिटुमेन	IS : 217-1961 कटबैक बिटुमेन की विशिष्टि (पुनरीक्षित)	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद संख्या अंकित की गई है।	1984-03-16
2.	IS:2980 ISI	दाबरहित चूल्हे	IS : 2980-1979 दाब रहित चूल्हों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 'ISI' शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद संख्या अंकित की गई है।	1984-09-01

[सं. सी एम डी/13 : 9]

S.O. 4276 :-In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the Standard Mark(s), design(s) of which together with the fverbal description of the design(s) and the title (s) of the relevant indian Standard(s) is/are given in the Schdedul hereto annexed, has/have been specified.

This/These Standard Mark(s) for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with efforect from the dates shown against each :

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the design of the Standard Mark	Date of effect
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(6)
1	IS : 217	Cutback bitumen	IS : 217—1961 Specification for cutback butumen (revised)	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1984-03-16
2.	IS : 2980	Non-Pressure stoves	IS : 2980—1779 Specification for non-pressure	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters'ISI',drawn in the exact style nand relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design	1984-09-01

[No. CMD/13 : 9]

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1985

का.आ. 4277:—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सीएम/एल-0697570 जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची मे दिये गये है, 1964-11-08 से रद्द कर दिया गया है और वापस ले लिया माना जाए:—

अनुसूची

क्र सं	लाइसेंस संख्या और दिनांक	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द लाइसेंस के अधीन वस्तु प्रक्रिया	सम्बद्ध भारतीय मानक
1	2	3	4	5
1.	सीएम/एल-0697570 1978-04-12	मैसर्स धींगड़ा पेंटस (इंडिया), 14/6, मथुरा रोड, फरीदाबाद (हरियाणा)	सामान्य कार्यों के लिए एलुमीनियम रोगन	IS : 2339-1963 सामान्य कार्यों के लिए एलुमीनियम रोगन की विशिष्टि

[सीएमडी/55 : 0697570]

डा. बी. एन. सिंह, अपर महानिदेशक

New Delhi, the 19th August, 1983

S.O.4277 In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulation 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that licence No. CM/L-0697570 particulars of which are given below has been cancelled with effect from 1984-11-30.

SCHEDULE

Licence No. & Date	Name and Address of the licensee	Article/Process covered by the licence Cancelled	Relevant Indian Standards
CM/L-0697570 1978-04-12	M/s. Dhingra Paints (India), 14 6, Mathura Road, Faridabad (Haryana)	Aluminium paint for general purposes	IS : 2339—1963 Specification for aluminium paints fo general purposes.

[CMD/55 : 0697571]

B. N. Singh, Addl. Director General

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1985

का. आ. **4278** :—होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार होम्योपैथी की केन्द्रीय परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उपयुक्त अनुसूची में "पश्चिम बंगाल" शीर्ष के अधीन क्रम संख्या 29-क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं : अर्थात् :—

विश्व विद्यालय बोर्ड अथवा आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम :	मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता	पंजीकरण के लिए संक्षेपण	टिप्पणी
1	2	3	4
"29-ख" कलकत्ता विश्व विद्यालय, कलकत्ता	बैचलर आफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी	बी. एच एम. एस.	"1984 से 1988

[संख्या वी. 27021/8/84-होम्यो.]

के. वेणुगोपाल, निदेशक

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 30th August, 1985

S.O. 4278 —In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Government, after consulting the Central Council of Homoeopathy hereby makes the following further amendment in the Second Schedule to the said Act, namely :—

In the said Schedule, under the heading "West Bengal", after Serial number 29A and the entries relating thereto, the following Serial number and entries shall be inserted, namely :—

Name of the University, Board or Medical Institution	Recognised medical qualification	Abbreviation for registration	Remarks
1	2	3	4
"29B. University of Calcutta, Calcutta.	Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery	B.H.M.S.	from 1984 to 1988.".

[No. V-27021/8/84-Homoeo]

K. VENUGOPAL, Director

परमाणु ऊर्जा विभाग

बम्बई, 29 जुलाई, 1985

का. आ. **4279** :—राष्ट्रपति इस विभाग की तारीख 2 जनवरी, 1984 और 7 मई, 1984 की अधिसूचना संख्या 25/2/83-ई आर के अनुक्रम में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को वर्ष 1985 के लिए निम्नलिखित प्रकार से पुनःनामित करते हैं :

1. प्रोफेसर ए. के. डे	अध्यक्ष
2. डा. ई. सी. सुब्बा राव, निदेशक, टाटा अनुसंधान विकास और अभिकल्प केंद्र, पुणे।	सदस्य
3. डा. बी. डी. गुप्ता, प्रोफैसर और अध्यक्ष, विकिरण चिकित्सा विभाग, स्नातकोत्तर अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़।	सदस्य
4. डा. पी. आर. दस्तीदार, अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा विभाग, सुरक्षा समीक्षा समिति, परमाणु ऊर्जा विभाग।	सदस्य
5 श्री पी. एन. कृष्णमूर्ति, वैज्ञानिक अधिकारी (एच)	सदस्य-सचिव

सं. 18/1/9/85-ईआर/2039

[कुमारी एच. बी. विजयकर, अवर सचिव]

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Bombay, the 29th July, 1985.

S.O. 4279 —In continuation of this Department's Notifications No. 25/2/83-ER dated January 2, 1984 and May 7, 1984, the President is pleased to re-nominate Chairman and Members of the Atomic Energy Regulatroty Board for the year 1985, as under :

1. Prof. A.K. De.	—Chairman
2. Dr. E.C. Subba Rao, Director, Tata Research Development and Design Centre, Pune.	—Member
3. Prof. B.D. Gupta, Professor & Chairman, Department of Radiotheraphy, Post Graduate Institute of Research, Chandigarh.	—Member
4. Dr. P.R. Dastidar, Chairman, DAE Safety Review Committee, Department of Atomic Energy	—Member
5. Shri P.N. Krishnamoorthy, Scientific Officer(H).	—Member-Secretary

[No. 18/1/9/85-ER/2039]

KUM. H.B. VIJAYAKAR, Under Secy.

अंतरिक्ष विभाग

बंगलौर, 29 जुलाई, 1985

का. आ. 4280:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरिक्ष विभाग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1976 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम अंतरिक्ष विभाग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधित नियम 1985 कहलायेंगे।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. अंतरिक्ष विभाग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1976 के अनुसूची में "भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह–1, अंतरिक्ष खंड परियोजना कार्यालय (इन्सैट–1 एस.एस.पी.ओ) "के शीर्ष के बाद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित शीर्ष और प्रविष्टियों को सम्मिलित किया जाय, अर्थात् :—

1	2	3	4	5
"भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह–1, प्रधान नियंत्रण सुविधा (एम.सी.एफ) हसन				
समूह–ख				
वैज्ञानिक तथा तकनीकी पद / प्रशासनिक/अन्य पद	परियोजना निदेशक, इन्सैट–1 एस.एस.पी.ओ.	परियोजना निदेशक, इन्सैट–1 एस.एस.पी.ओ.	सभी	सचिव अंतरिक्ष विभाग
समूह–ग	प्रबंधक, इन्सैट–1, एम.सी.एफ. हसन	प्रबंधक, इन्सैट–1, एम.सी.एफ. हसन	सभी	परियोजना निदेशक, इन्सैट–1 एस.एस.पी.ओ.
समूह–घ	प्रशासनिक अधिकारी–II	प्रशासन अधिकारी–II	सभी	प्रबंधक, इन्सैट–1, एम.सी.एफ, हसन

[सं. 2/9(1)/83–I(v)]

टी. एस. वेंकटरामन, अवर सचिव ।

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore, the 29th July, 1985

S.O. 4280 :—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Space Employees' (Classification, Control and Appeal) Rules, 1976, namely:—

1. (1) These rules may be called the Department of Space Employmees' (Classification Control and Appeal) Amendment Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Space Employees' (Classification, Control and Appeal) Rules, 1976 after the heading "Indian National Satellite-1 Space Segment Project Office (INSAT-1 SSPO)" and the entries relating thereto, the following heading and entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5
"INDIAN NATIONAL SATELLITE-1, MASTER CONTROL FACILITY (MCF) HASSAN				
Group B				
Scientific and Technical Posts. / Administrative/Other Posts.	Project Director, INSAT-1 SSPO	Project Director INSAT-1 SSPO	All	Secretary, Department of Space.
Group C	Manager, INSAT-1, MCF, Hassan	Manager, INSAT-1, MCF Hassan	All	Project Director INSAT-1 SSPO.
Group D	Administrative Officer-II	Administrative Officer-II	All	Manager, INSAT-1 MCF, Hassan."

[No. 2/9(1)/83-I(V)]

T.S. VENKATARAMAN, Under Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1985

का०आ० 4281:— दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 3 की उपधारा 3 के खंड (छ) के साथ पठित उप धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्माण और आवास मंत्रालय की दिनांक 25-9-1982 की अधिसूचना संख्या के 11011/22/78-डी०डी० 1(ए)/II बी के अधिक्रमण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका के प्रशासक श्री धर्मदत्त को श्री पी०एस० भटनागर के स्थान पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामित करती है और भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय के दिनांक 30 दिसम्बर, 1957 की अधिसूचना संख्या 12-173/57-एल०एस०जी० में निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामत :—

उक्त अधिसूचना की मद संख्या 10 में, 'श्री पी० एस० भटनागर, प्रशासक, नई दिल्ली नगर पालिका के इन्दराज के लिए निम्नलिखित इन्दराज प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"श्री धर्मदत्त प्रशासक, नई दिल्ली नगर पालिका "।

[सं० के०-11011/22/78-डी०डी० 1 (ए) /IIबी]
चन्द्र सैन, उप सचिव

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

(Delhi Division)

New Delhi, the 4th September, 1985

S.O. 4281.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (g) of sub-section (3) of section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) and in supersession of Ministry of Works & Housing Notification No. K-11011/22/78-DDIA/IIB dated the 25th September, 1982, the Central Government hereby nominates Shri Dharam Dutt, Administrator, New Delhi Municipal Committee as a member of the Delhi Development Authority in place of Shri P.S. Bhatnagar and makes the following further amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Health No. 12-173/57-LSG, dated the 30th December, 1957, namely:—

In the said notification, in item No. 10 for the entry "Shri P.S. Bhatnagar, Administrator, New Delhi Municipal Committee" the following entry shall be substituted:—

"Shri Dharam Dutt, Administrator, New Delhi Municipal Comittee".

[No. K-11011/22/78-DDI(A)/IIB]
CHANDAR SAIN, Dy. Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1985

का.आ. 4282 :—चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित फिल्मों (वीडियो फिल्मों को छोड़कर) के संबंध में फिल्म की एक प्रिंट/वीडियो कापी को जमा करने से संबंधित चलचित्र (प्रमाणन) नियम 1983 के नियम 28 के उप-नियम (1) के उपबंधों से 1-10-85 से 31-3-86 तक की अवधि के लिये इस शर्त पर छूट देती है कि आवेदक फिल्म की शूटिंग स्क्रिप्ट को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास जमा करेगा ।

[फ़ा. सं. 806/21/83-एफ़ (सी)]
इकबाल कृष्ण, अवर सचिव,

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 20th August, 1985

S.O. 4282.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Cinematograph Act 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby grants exemption from the provisions of sub-rule (1) of rule 28 of the Cinematograph (Certification) Rules 1983 relating to deposit of a print/video copy of the film in respect of films (excluding video films) certified by the Central Board of Film Certification for the period 1-10-85 to 31-3-86 subject to the condition that the applicant shall deposit a shooting script of the film to the Control Board of Film Certification.

[Fil No. 806/21/83-F(C)]
IQBAL KRISHAN, Under Secy.

पेट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1985

का.आ. 4283.—तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 (1974 का 47) की धारा (ख) के खण्ड 3 के उप-खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पेट्रोलियम मंत्रालय में वित्त सलाहकार श्री एस. बालाचन्द्रन को उनके पद की हैसियत से तत्काल प्रभावी तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड का सदस्य नियुक्त करते है, ताकि वे श्री आर. वासुदेवन के स्थान पर वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर सकें ।

[सं. 7/10/82—वित्त-II]
एम. कुमारस्वामी, निदेशक (वित्त)

MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 12th August, 1985

S.O. 4283.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 3 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (No. 47 of 1974), the Central Government hereby appoints, with immediate effect and for a period not exceeding two years, Shri S. Balachandran, Financial Adviser, Ministry of Petroleum, as a member of the Oil Industry Development Board by virtue of his office to represent the Ministry of Finance, vice Shri R. Vasudevan.

[No. 7|10|82-Fin.II]
M. KUMARASWAMI, Director (Finance)

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1985

का. आ. सं. 4284.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जंकशन पोइन्ट से जी०जी० एस० IV तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

जंकशन पाइन्ट से जी. जी. एस 4 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात गांव	जिला : मेहसाना सर्वे नंबर	हेक्टर	तालुका : कलोल आर	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
कलोल	252/228	0	04	00
	252/225	0	01	40
	252/224	0	18	15
	252/223/16	0	01	45
	252/223/8	0	01	50
	252/223/6	0	04	00
	252/223/3	0	04	65
	252/223/9	0	00	10
	252/223/11	0	00	35
	252/223/12	0	00	60
	214	0	07	50
	215	0	01	80
	कार्ट्रट्रेक	0	01	44
	252/76	0	01	12
	252/68	0	08	40
	252/69	0	08	73
	252/66	0	02	52
	252/65/1	0	01	00
	252/30	0	05	50
	252/61	0	07	00
	252/22	0	02	80
	252/23	0	03	68
	252/25	0	09	36
	252/27	0	00	10
	केन्स	0	01	12
	252/1/2	0	01	00
	251/12	0	05	25
	251/13	0	01	53
	251/11	0	03	87
	251/10	0	00	50
	251/32	0	07	40
	251/33	0	01	75
	251/34	0	06	00
	251/35	0	01	05
	251/36	0	02	34
	251/39	0	00	95
	251/40	0	01	20
	251/41	0	02	72

[सं. O-12016/99/85-ओ. एन. जी.-डी. 4]

पी. के. राजगोपालन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 30th August, 1985

S.O. 4284.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from junction point to GGS-IV in Gujrat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, construction and maintenance Division Makarpura Road, Vadodara, (390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM JUNCTION POINT TO GGS IV

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hectare	Area	Centiare
1	2	3	4	5
KALOL	252/228	0	04	00
	252/225	0	01	40
	252/224	0	18	15
	252/223/16	0	01	45
	252/223/8	0	01	50
	252/223/6	0	04	00
	252/223/3	0	04	65
	252/223/9	0	00	10
	252/223/11	0	00	35

1	2	3	4	5
	252/223/12	0	00	60
	214	0	07	50
	215	0	01	80
	Cart track	0	01	44
	252/76	0	01	12
	252/68	0	08	40
	252/69	0	08	73
	252/66	0	02	52
	252/65/1	0	01	00
	252/30	0	05	50
	252/61	0	07	00
	252/22	0	02	80
	252/23	0	03	68
	252/25	0	09	36
	252/27	0	00	10
	Kans	0	01	12
	252/1/2	0	01	00
	251/12	0	05	25
	251/13	0	01	53
	251/11	0	03	87
	251/10	0	00	50
	251/32	0	07	40
	251/33	0	01	75
	251/34	0	06	00
	251/35	0	01	05
	251/36	0	02	34
	251/39	0	00	95
	251/40	0	01	20
	251/41	0	02	72

[No. O-12016/99/85-ONG-D4]
P. K. RAJAGOPALAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1985

का. आ. 4285 :—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2399 तारीख 12-7-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हर्जरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : बड़ोदरा तालुका : डभोई

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टर	एआरई	सेन्टीयर
मारेया	466	0	03	64
	474	0	30	56
	473	0	10	92
	468	0	10	40
	469	0	11	84
	472	0	28	32
	528	0	19	68
	529	0	21	60
	530	0	38	56
	538	0	23	20
	471	0	01	60
	536/2	2	43	04
	534	0	23	20
	535	0	03	84
	561/1	0	18	46
	561/2	0	20	96
	559	0	26	40
	558	0	10	72
	560	0	08	96

[सं. O-12016/71/84-ओ. एन. जी. डी.-4]

New Delhi, the 9th Sept., 1985

S.O. 4285.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Petroleum) S.O. 2399 dated 12-7-74 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declares its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted reprot to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd., free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Dabhoi

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Nariya	466	0	03	64
	474	0	30	56
	473	0	10	72
	468	0	10	40
	469	0	11	84
	472	0	28	32
	528	0	19	68
	529	0	21	60
	530	0	38	56
	538	0	23	20
	471	0	01	60
	536/2	0	43	04
	534	0	23	20
	535	0	03	84
	561/1	0	18	46
	561/2	0	20	96
	559	0	26	40
	558	0	10	72
	560	0	08	96

[No. O-12016/71/84-ONG—D4]

का. आ. 4286.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 301 तारीख 26-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच० पी० जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : म न तहसील : घट्टिया जिला : उज्जैन, राज्य : (मध्य-प्रदेश)

अनुसूची

अनु क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	267	0.021
2.	262	0.105
3.	266	0.982
4.	265	0.021
5.	285	0.512
6.	268	0 094
7.	282	0.594
8.	279	0.293
9.	305	1.066
10.	277	0.439
11.	276	0.157
12.	275	0 031
13.	294	0.366
14.	295	0.042
15.	314	0.209
16.	316	0.281
17.	317	0.052
18.	315	0.491
19.	319	0.439
20.	188	0.063
योग :—कुल क्षेत्रफल		6.268

[सं. O-14016/535/84-जं. पा.]

S.O. 4286.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 301 dated 26-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village: Meen Tehsil: Ghatiya : Distt. Ujjain

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1.	267	0.031
2.	262	0.105
3.	266	0.982
4.	265	0.021
5.	285	0.512
6.	268	0.094
7.	282	0.594
8.	279	0.293
9.	305	1.066
10.	277	0.439
11.	276	0.157
12.	275	0.031
13.	294	0.366
14.	295	0.042
15.	314	0.209
16.	316	0.281
17.	317	0.052
18.	315	0.491
19.	319	0.439
20.	188	0.063
	Total Area	6.268

[No. O-14016/535/84—GP]

का. आ. 4287.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, पैट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 4494 तारीख 22-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : मालीखेड़ी तहसील : महिदपुर जिला : उज्जैन राज्य : (मध्य-प्रदेश)

अनुसूची

अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	288	0.447
2.	296	0.125
3.	297	0.316
4.	298/2	0.089
5.	303/1	0.008
6.	302/1	0.129
	302/2	—
7.	301	0.210
8.	305/1/2	0.049
9.	305/3	0.227
10.	328/1	0.040
11.	330/1	0.008
12.	331/1	0.129
13.	331/2	0.121
14.	327/3	0.004
15.	331/3	0.113
16.	326/4	0.405
17.	327/4	0.324
18.	331/4	0.065
19.	324/2	0.405
20.	341/1	0.425
21.	341/2	0.219
22	323	0.235
23.	347/1	0.437
24.	343	0.016
25.	346	0.028
	कुल योग क्षेत्रफल :	4.574

[सं. O-14016/333/84-जे. पी.]

S.O. 4287.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum, S.O. 4494 dated 22-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right

of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands, shall instead of vesting in Central Government, vests on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from all encumbrances.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village: Mali Khedi Tehsil: Mahid Pur Distt. Ujjain

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1.	288	0.447
2.	296	0.125
3.	297	0.316
4.	298/2	0.089
5.	303/1	0.008
6.	302/1 302/2	0.129 —
7.	301	0.210
8.	305/1/2	0.049
9.	305/3	0.227
10.	318/1	0.040
11.	330/1	0.008
12.	331/1	0.129
13.	331/2	0.121
14.	327/3	0.004
15.	331/3	0.113
16.	326/4	0.405
17.	327/4	0.324
18.	331/4	0.065
19.	324/2	0.405
20.	341/2	0.425
21.	341/1	0.219
22.	323	0.235
23.	347/1	0.437
24.	343	0.016
25.	346	0.028
Total Area		4.574

[No. O-14016/383/84—GP]

का. आ. 4288.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1251 तारीख 23-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : बहरगखेड़ी तहसील राघोगढ़ : जिला—गुना राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनु क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	63	0.021
2.	129	0.282
3.	149	0.035
4.	151	0.105
5.	155	0.010
6.	156	0.010
7.	157	0.157
8.	158	0.334
9.	159	0.052
10.	163	0.052
11.	164	0.063
12.	165	0.083
13.	166	0.031
14.	167	0.418
15.	189	0.063
16.	199	0.021
17.	200	0.188
18.	201	0.052
19.	202	0.031
20.	203	0.021
21.	205	0.105
22.	206/1	0.063
23.	206/2	0.052
24.	207 में से	0.042
25.	207 में से	0.042
26.	207 में से	0.010

1	2	3
27.	208	0.335
28.	209	0.470
29.	211	0.107
30.	215	0.550
31.	232	0.157
32.	235	0.428
33.	236	0.157
34.	238	0.052
35.	239	0.052
36.	240	0.366
37.	191	0.042
योग :	कुल क्षेत्रफल	5.059

[सं. O-14016/144/85-जी. प.]

S.O. 4288.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1251 dated 23-3-85 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (I) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village: Vahara Khedi Tehsil: Raghogarh Distt.: Guna

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R. O. U. in Hecture
1	2	3
1.	63	0.021
2.	129	0.282
3.	149	0.035
4.	151	0.105
5.	155	0.010
6.	156	0.010
7.	157	0.157
8.	158	0.334
9.	159	0.052
10.	163	0.052
11.	164	0.063
12.	165	0.083
13.	166	0.031
14.	167	0.418
15.	189	0.063
16.	199	0.021
17.	200	0.188
18.	201	0.052
19.	202	0.011
20.	203	0.021
21.	205	0.105
22.	206/1	0.063
23.	206/2	0.052
24.	207M.S.	0.042
25.	207M.S.	0.042
26.	207M.S.	0.010
27.	208	0.335
28.	209	0.470
29.	211	0.107
30.	215	0.550
31.	232	0.157
32.	235	0.428
33.	236	0.157
34.	238	0.052
35.	239	0.052
36.	240	0.366
37.	191	0.042
Total Area :		5.059

[No. O-14016/144/85—GP]

का. आ. 4289.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 2038 तारीख 11-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : तेहरी तह० : पिछोर जिला : शिवपुरी राज्य : मध्य प्रदेश

अनुसूची

अनुक्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्म में)
1.	2.	3.
1.	85	0.408
2.	87	0.010
8.	80	0.240
4.	108	0.052
5.	79	0.073
6.	103	0.209
7.	102	0! 105
8.	105	0.84
9.	104	0.146
10.	106	0.418
11.	123	0.010
12.	142	0.021
13.	91	0.010
14.	141	0.188
15.	138	0.094
16.	139	0.334
17.	140	0.136
18.	126	0.125
19.	129	0.199
20.	497	0.021
21.	496	0.262
22.	127	0.167
23.	125	0.105
24.	128	0.397
25.	124	0.543
26.	111	0.428
27.	213	0.052
28.	430	0.115
29.	446	0.512
30.	447	0.240
31.	431	0.251
32.	444	0.146
33.	450	0.167
34.	451	0.428
35.	452	0.031
36.	503	0.282
37.	499	0.449
38.	498	0.272
39	504	0.178
40.	500	0.387
41.	522	0.010
42.	493	0.011
43.	494	0 053
44.	536	0.031
45	495	0.188
46.	492	0 555
47.	611	0 052
48.	610	0.199
49.	613	0.387
50.	617	0.314
51.	615	0.157
52.	616	0.418
53.	682	0.157
54.	701	0.010
55.	702	0.042
56.	703	0.021
57.	698	0.136
58.	691	0.157
59.	694	0.094
60.	684	0.997
61.	685	0.687
62.	706	0.125
63.	707	0.53
64.	109	0.031
65.	712	0.418
66.	693	0.105
67.	692	0.272
68.	683	0.345
69.	445	0.052
योग :—कुल क्षेत्रफल		14.362

[सं. O-14016/317/85-जें. पी०]

S.O. 4289.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 2038 dated 11-5-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline:

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ Gas Pipe Linc Project

Village Tehari Tehsil Pichhore Distt. Shivpuri

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R. O. U. in Hecture
1	2	3
1.	85	0.408
2.	87	0.010
3.	80	0.240
4.	108	0.052
5.	79	0.073
6.	103	0.209
7.	102	0.105
8.	105	0.084
9.	104	0.146
10.	105	0.410
11.	123	0.010
12.	142	0.021
13.	91	0.010
14.	141	0.188
15.	138	0.094
16.	139	0.334
17.	140	0.136
18.	126	0.125
19.	129	0.199
20.	497	0.021
21.	496	0.262
22.	127	0.167
23.	125	0.105
24.	128	0.397
25.	124	0.543
26.	111	0.428
27.	213	0.052
28.	430	0.115
29.	446	0.512
30.	447	0.240
31.	434	0.251
32.	444	0.146
33.	450	0.167
34.	451	0.428
35.	452	0.031
36.	503	0.282
37.	499	0.449
38.	498	0.272
39.	504	0.178
40.	500	0.387
41.	522	0.010
42.	493	0.011
43.	494	0.053
44.	536	0.031
45.	495	0.188
46.	492	0.555
47.	611	0.052
48.	610	0.199
49.	613	0.387
50.	617	0.314
51.	615	0.157
52.	616	0.418
53.	682	0.157
54.	701	0.010
55.	702	0.042
56.	703	0.021
57.	698	0.136
58.	691	0.157
59.	694	0.094
60.	684	0.997
61.	685	0.687
62.	706	0.125
63.	707	0.053
64.	109	0.021
65.	712	0.418
66.	693	0.105
67.	692	0.272
68.	683	0.345
69.	445	0.052
	Total Area	14.362

[No. O-14016/317/85—GP]

का. आ. 4290 :—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1250 तारीख 23-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : वर्या तहसील : राघोगढ़ जिला : गुना राज्य (म. प्र.)

अनुसूची

अनु. क्र.	खसरा नं.	अपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	12	0.178
2.	2	0.010
3.	16	0.052
4.	17	0.016
5.	18	0.324
6.	20	0.073
7.	29	0.300
8	38	0.031
9.	39	0.073
10.	43	0.088
11.	45	0.273
12.	46	0.409
13.	140	0.157
14.	144	0.209
15.	145	0.167
16.	146	0.343
17.	191	0.031
18.	205	0.438
19.	209	0.031
20.	210	0.531
21.	215	0.179
22.	216	0.082
23.	217	0.361
24.	218	0.606
25.	225	0.031
26.	44	0.011
27.	142	0.011
28.	37	0.021
29.	13	0.011
30.	5	0.011
31.	42	0.031
32.	24	0.031
योग :—कुल क्षेत्रफल		5.121

[सं. O-14016/143/85-जं. पं.]

S.O. 4290.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1250 dated 23-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

H.B.J. Gas Pipe Line Project.

Village : Varya Tehsil : Raghogarh Distt. Guna (M.P.)

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R. O. U. in Hectare
1	2	3
1.	12	0.178
2.	14	0.010
3.	16	0.052
4.	17	0.016
5.	18	0.324
6.	20	0.073
7.	29	0.300
8.	38	0.031
9.	39	0.073
10.	43	0.088
11.	45	0.273
12.	46	0.409
13.	140	0.157
14.	144	0.209
15.	145	0.167
16.	146	0.343
17.	191	0.031
18.	205	0.438
19.	209	0.031
20.	210	0.531
21.	215	0.179
22.	216	0.083
23.	217	0.361
24.	218	0.005
25.	225	0.031
26.	44	0.011
27.	142	0.011
28.	37	0.021
29.	13	0.011
30.	5	0.011
31.	42	0.031
32.	24	0.031
Total Area		5.121

[No. O-14016/143/85—GP]

का०आ० 4291.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की पैट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का०आ० सं० 1538 तारीख 13-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम : डोंगर तहसील : राघोगढ़ जिला : गुना राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु.क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	1	0.941
2.	134	0.031
3.	135	0.188
4.	136/1	0.147
5.	136/2	0.021
6.	140 1/1	0.167
7.	139	0.575
8.	141	0.021
9.	145	0.486
10.	147/2	0.010
11.	2	0.105
12.	147/1	0.010
13.	147 3	0.084
14.	148	0.439
15.	215/1	2.132
16.	245	0.031
17.	223/1	1.296
18.	223/2	1.118
19.	246	0.031
20.	225/1	2.278
21.	243/2	0.147
22.	241/1	0 136
23.	240	0.157
24.	238/2	0.261
25.	239	0.105
26.	237	0.272
27.	234/3	0.157
28.	225/2	0.084
29.	225/3	0.157
	योग :—कुल क्षेत्रफल	9.587

[सं. O-14016/205/85-जी. पी.]

S.O. 4291.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, (Department of Petroleum) S.O. 1538 dated 13-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village: Dongar Tehsil: Raghogarh Distt:Guna MP

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hector
1	2	3
1.	1	0.941
2.	134	0.031
3.	135	0.188
4.	136/1	0.147
5.	136/2	0.021
6.	140/1/1	0.167
7.	139	0.575
8.	141	0.021
9.	145	0.486
10.	147/2	0.010
11.	2	0.105
12.	147/1	0.010
13.	147/3	0.084
14.	148	0.439
15.	215/1	2.132
16.	245	0.031
17.	223/1	1.296
18.	223/2	1.118

1	2	3
19.	246	0.031
20.	225/1	2.278
21.	243/2	0.147
22.	241/1	0.136
23.	240	0.157
24.	238/2	0.261
25.	239	0.105
26.	237	0.272
27.	234/3	0.157
28.	225/2	0.084
29.	225/3	0.157
	TOTAL AREA	9.587

[No. O-14016/205/85-G.P.]

का. आ. 4292—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का. आ. सं. 1301 तारीख 30-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और अगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम आवन तहसील राघोगढ जिला—गुना राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	50	0.104
2.	51	0.209
3.	53	0.230
4.	54	0.073
5.	55	0.042
6.	58	0.155
7.	67	0.063
8.	69	0.157
9.	70	0.366
10.	78	0.021
11.	81	0.021
12.	71 में से	0.157
13.	76	0.052
14.	79	0.052
15.	80 में	0.125
16.	80 मे	0.105
17.	83	0.266
18.	84	0.021
19.	139	0.052
20.	140	0.209
21.	141	0.209
22.	142	0.178
23.	153	0.345
24.	154	0.105
25.	163	0.366
26.	201	0.627
27.	207	0.209
28.	208	0.073
29.	1060	0.230
30.	1061/1	0.230
31.	1063 में	0.063
32.	1099	0.010
33.	1064	0.440
34.	1066	0.052
35.	1067	0.021
36.	1972	0.888
37.	1087	0.021
38.	1095	0.188
39.	1097	0.202
40.	1098	0-063
41.	1106	0-126
42.	1112	0-126
43.	1113	0-336
44.	1117	0.073
45.	152	0-010
46.	82	0-052
47.	52	0-021
48.	59	0-073
योग : कुल क्षेत्रफल		7.824

[सं O-14016/165/85-जीपी]

S.O. 4292.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, (Department of Petroleum) S.O. 1301 dated 30-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Avan Tehsil : Paghogarh Distt. Guna

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be Aequired for R.O.U. in Hecture
1	2	3
1.	50	0.104
2.	51	0.209
3.	53	0.230
4.	54	0.073
5.	55	0.042
6.	58	0.155
7.	67	0.063
8.	69	0.157
9.	70	0.366
10.	78	0.021
11.	81	0.021
12.	71 M.S.	0.157
13.	76	0.052
14.	79	0.052
15.	80 M.S.	0.125
16.	80 M.S.	0.105
17.	83	0.266
18.	84	0.021
19.	139	0.052
20.	140	0.209
21.	141	0.209
22.	142	0.178
23.	153	0.345
24.	154	0.105
25.	163	0.366
26.	210	0.627
27.	207	0.209
28.	208	0.073
29.	1060	0.230
30.	1061/1	0.230
31.	1063 M.	0.063
32.	1099	0.010
33.	1064	0.440
34.	1066	0.052
35.	1067	0.021
36.	1072	0.888
37.	1087	0.021
38.	1095	0.188
39.	1097	0.209
40.	1098	0.063
41.	1106	0.126
42.	1112	0.126
43.	1113	0.336
44.	1117	0.073
45.	152	0.010
46.	82	0.052
47.	52	0.021
48.	59	0.073
	TOTAL AREA	7.824

[No. O-14016/165/85-G.P.]

का. आ. 4293 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का. आ. सं. 1311 तारीख 30-9-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम—बावड़ी खेड़ा तहसील—राघोगढ़ जिला—गुना राज्य (म. प्र.)

अनुसूची

अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर्स में)
1	2	3
1.	83	0.105
2.	118	0.523
3.	117/2	0.314
4.	117/1 में से	0.470
5.	117/1 में से	0.115
6.	117/3	0.460
7.	95/3	0.031
8.	115	0.021
9.	116	0.031
10.	117/8	0.021
11.	122	0.021
12.	130/1	0.021
	योग कुल क्षेत्रफल	2.133

[सं. O-14016/176/85-जी. पी.]

S.O. 4293.—Whereas by notification of the Government of India in the Miinstry of Energy (Deptt. of Petroleum) S.O. 1311 dated 30-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Bawadikhedi Tehsil : Raghogarh Distt.Guna (M.P.)

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectere
1	2	3
1.	83	0.105
2.	118	0.523
3.	117/2	0.314
4.	117/1 M.S.	0.470
5.	117/1 M.S.	0.115
6.	117/3	0.460
7.	95/3	0.031
8.	115	0.021
9.	116	0.031
10.	117/8	0.021
11.	122	0.021
12.	130/1	0.021
	TOTAL AREA	2.133

[No. O-14016/176/85-G.P.]

का॰आ॰ 4294.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का॰आ॰सं॰ 2044 तारीख 11-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप, में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम मोहशा डामरोग तहसील पिछोर जिला—शिवपुरी राज्य (म. प्र.)

अनुसूची

अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	2046	0.031
2.	2053	0.188
3.	2057	0.366
4.	2058	0.261
5	2059	0.167
6.	2292	1.000
7.	2070	0.470
8.	2291	0.031
9.	2294	0.082

1	2	3
10.	2124	0.648
11.	2123	0.209
12.	2121	0.230
13.	2175	0.031
14.	2176	0.292
15.	2147	0.366
16.	2150	0.240
17.	2151	0.324
18.	2269	0.021
19.	2268	0.010
20.	2270	0.042
21.	2271	0.261
22.	2283	0.021
23.	2148	0.355
24.	2224	0.146
25.	2223	0.073
26.	2225	0.063
27.	2227	0.115
28.	2228	0.115
29.	2229	0.073
30.	2264	0.010
31.	2265	0.209
32.	2277	0.314
33.	2278	0.105
34.	2281	0.105
35	2296	0.063
36.	2297	0.031
37.	2295	0.031
38.	2054	0.052
39.	2064	0.021
40.	2226	0.010
	योग:—कुल क्षेत्रफल	7.182

[सं. O-14016/323/85-जी. पी.]

S.O. 4294.—Whereas by notification of the Government of India in the Miinstry of Energy (Deptt. of Petroleum) S.O. 2044 dated 11-5-85 under sub-sccion (1) of Secion 8 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And Further Whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from all encumbrances.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Mohaba Darmone Tehsil : Pichhore
Distt. : Shivpuri

SCHEDULE

S No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hector
1	2	3
1.	2046	0 031
2.	2053	0.188
3.	2057	0.366
4.	2058	0.261
5.	2059	0.167
6.	2292	1.000
7.	2070	0.470
8.	2291	0.031
9.	2294	0.082
10.	2124	0.648
11.	2123	0.209
12.	2121	0.230
13.	2175	0.031
14.	2176	0.292
15.	2147	0.366
16.	2150	0.240
17.	2151	0.234
18.	2269	0.021
19.	2268	0.010
20.	2270	0.042
21.	2271	0.261
22.	2283	0.021
23.	2148	0.355
24.	2224	0.146
25.	2223	0.073
26.	2225	0.063
27.	2227	0.115
28.	2228	0.115
29.	2229	0.073
30.	2264	0.010
31.	2265	0.209
32.	2277	0.314
33.	2278	0.105
34.	2281	0.105
35	2296	0.063
36.	2297	0.031
37.	2295	0.031
38.	2054	0.052
39.	2064	0.021
40.	2226	0.010
	TOTYL AVEA	7.182

[No. O—14016/323/85-G.P.]

का. आ. 4295.—यत : पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन

भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1300 तारीख 30-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम देहरी तहसील राघोगढ़ जिला—गुना राज्य (म. प्र.)

अनुसूची

अनु. क्र.	खसरा नं	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	35	0.063
2.	36	0.052
3.	37	0.345
4	60	0.470
5	66	0.523
6.	38	0.157
7.	39	0.052
8.	42	0.523
9	43	0.094
10.	45	0.021
11.	46	0.105
12.	54	0.063
13	55	0.042
14.	56	0.209
15.	57	0.010
16	61	0.021
17.	62	0.418
18.	67	0.209
19	68	0.261
20	69/1	0.052
21	74	0.136
22	77	0.042
23	80	1.505
	योग कुल क्षेत्रफल	5.373

[सं. O-14016/164/85-जी. पी]

S.O. 4295.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 1300 dated 30-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline:

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Dehari Tehsil : Raghogarh Distt. : Guna

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1.	35	0.063
2.	36	0.052
3.	37	0.345
4.	60	0.470
5.	66	0.523
6.	38	0.157
7.	39	0.052
8.	42	0.523
9.	43	0.094
10.	45	0.021
11.	46	0.105
12.	54	0.063
13.	55	0.042
14.	56	0.209
15.	57	0.010
16.	61	0.021
17.	62	0.418
18.	67	0.209
19.	68	0.261
20.	69/1	0.052
21.	74	0.136
22.	77	0.042
23.	80	1.505
	TOTAL AREA	5.373

[No. O—14016/164/85-G.P.]

का. आ. 4296:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2316 तारीख 1-6-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित किया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त नियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच बी जे गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम छापी तहसील कोलारस जिला-शिवपुरी राज्य (म. प्र.)

अनुसूची

क्रम सं.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर्स में)
1	2	3
1.	92	0.033
2.	237	0.052
3.	93	0.297
4.	263	0.157
5.	54	0.314
6.	264	0.031
7	262	0.502
8	238	0.932
9	133	0.042
10.	125	0.199
11.	134	0.544
12.	261	0.137
13	293	0.031
14.	94	0.042
15.	336	0.136
16	57	0.167
17.	73	0.114
18.	132	0.010
19.	156	0.010
20.	75	0.084
21	78	0.334
22.	79 1	0.158
23.	77	0.111
24	86	0.209
25	131	0.282
26	81	0.337
27	82	0.264
28	137	0.112
	योग--	5.671

[सं. O-11016/232/85-ज. प.]

S.O. 4296.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry Petroleum S.O. 2316 dated 1-6-1985 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Chhapi Teshil : Kolaras Distt. : Shivpuri

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectares
1.	92	0.0333
2.	237	0.052
3.	93	0.297
4.	263	0.157
5.	54	0.314
6.	264	0.031
7.	262	0.052
8.	238	0.932
9.	133	0.042
10.	125	0.199
11.	134	0.544
12.	261	0.137
13.	293	0.031
14.	94	0.042
15.	136	0.136
16.	57	0.167
17.	73	0.114

1	2	3
18.	132	0.010
19.	156	0.010
20.	175	0.084
21.	78	0.334
22.	79/1	0.158
23.	77	0.111
24.	80	0.209
25.	131	0.262
26.	81	0.337
27.	82	.. 0.234
28.	137	0.142
TOTAL AREA :		5.671

[No. O--14016/332/85-G.P.]

का.आ. 4297.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.स. 2324 तारीख 18-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग के अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकबा ब. बि. बि.	विवरण
हरदोई	शाहाबाद	पछोहा	पचरिया	422	0—4—8	
				423	1—0—10	
				424	0—0—9	
				425	0—9—18	
				426	0—11—11	
				436	0—0—4	
				437	0—1—10	
				438	0—4—0	
				439	0—10—0	
				440	0—3—6	
				442	1—0—7	

[सं. O—14016/349/85-जी. पी.]
एम. एस. श्रीनिवासन, उप सचिव

S.O. 4297.—Whereas by notification of the Government of India in the Minisrty of Petroleum S.O. 2324 dated 18-5-1985 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahasil	Pargana	Village	Plot No.	Area in B.B.B.
Hardoi,	Shahabad	Pachhoha	Pachriya	422	0-4-8
				423	0-0-10
				42	40-0-9
				425	0-9-18
				426	0-11-11
				436	0-0-4
				437	0-1-10
				438	0-4-0
				439	0-10-0
				440	0-3-6
				442	1-0-7

[No. O..14016/349/85-G.P.]
M. S. SRINIVASAN, Dy. Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1985

आदेश

का. आ. 4298:—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच विद्यमान है;

2. और यह विवाद ऐसे स्वरूप का है कि एक से अधिक राज्य में स्थित खाद्य निगम के प्रतिष्ठानों के इस विवाद में दिलचस्पी रखने या उससे प्रभावित होने की संभावना है ;

3. और केन्द्रीय सरकार की राय है कि राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा उक्त विवाद मे न्याय निर्णयन करना चाहिए ;

4. अतः अब केन्द्रीय सरकार:—

(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसका मुख्यालय बम्बई में होगा और श्री आर. डी. तुलपुले को इसका पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है ; और

(2) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त औद्योगिक विवाद को उक्त राष्ट्रीय अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

उक्त अधिकरण औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (2-क) के अनुसार उक्त विवाद में अपना पंचाट छह महीनों की अवधि के अंदर देगा ।

अनुसूची

"क्या भारतीय खाद्य निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली के प्रबंधतंत्र की निम्नलिखित डिपो में लेबर मेट पद्धति कर्मचारियों को :—

उड़ीसा	(1) रूपशा और (2) जालेश्वर,
पश्चिम बंगाल	(1) अशोक नगर (2) चिनसुरा (3) खारदा (4) आसनसोल (गोपालपुर) (5) ओरियंट जूट मिल,
उत्तर प्रदेश	(1) गाजियाबाद (2) साहिबाबाद, (3) बस्ती और (4) पंकी,
दिल्ली	(1) शक्ति नगर/शाहदरा
हरियाणा	(1) फरीदाबाद — ——

अपना कर्मचारी न मानने और लेखा वर्ष 1982 तथा 1983 और 1983-84 के लिए बोनस के स्थान पर अनुग्रहपूर्वक लाभों की अदायगी न करने की कार्यवाही उचित और वैध है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ?"

[सं. एल-42011/3/85-डी-5]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 13th August, 1985

ORDER

S.O. 4298.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers' in relation to the management of Food Corporation of India and the workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

2. And whereas, the dispute is of such a nature that establishments of Food Corporation situated in more than one State are likely to be interested in or affected by such dispute;

3. And whereas the Central Government of the opinion that the said dispute should be adjudicated by a National Tribunal.

4. Now, therefore, the Central Government :—

(i) in exercise of the powers conferred by section 7B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), hereby constitutes a National Industrial Tribunal with head quarters at Bombay and appoints Shri R. D. Tulpule as its Presiding Officer; and

(ii) in exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of Section 10 of the said Act, hereby refers the said industrial dispute to the said National Tribunal for adjudication.

The said Tribunal shall give its award in the said dispute within a period of six months in accordance with sub-section (2A) of section 10 of the I.D. Act, 1947.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Food Corporation of India, Head Office, New Delhi in not treating the Labour mate system employees at the following depots;

ORISSA :

(1) Rupsha and
(2) Jaleswar.

WEST BENGAL :

(1) Ashok Nagar,
(2) Chinsura,
(3) Kharda,
(4) Asansol (Gopalpur) and
(5) Orient Jute Mill.

U.P. :

(1) Ghaziabad,
(2) Sahibabad,
(3) Basty and
(4) Panki.

DELHI :

(1) Shaktinagar/Shadra.

HARYANA :

(1) Faridabad.

as their employees and depriving them from the payment of benefits of ex-gratia in lieu of bonus for the accounting year, 1982 and 1983 and 1983-84 is fair just and legal, If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?"

[No. 42011/3/85-D. V.]

नई दिल्ली, 22 अगस्त 1985

का. आ. 4299:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम, पंजाब क्षेत्र चन्डीगढ़ के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण चन्डीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19-8-1983 को प्राप्त हुआ था।

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 22nd August, 1985

S.O. 4299.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India, Punjab Region, Chandigarh, and their workmen, which was received by the Central Government on the 19th August, 1985.

BEFORE SH. J. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH.

Case No. I. D. 11|84

PARTIES :

Employers in relation to the management of Food Corporation of India.

AND

Their Workman—Sh. Pawan Kumar Singla.

APPEARANCES :

For the Employers : Sh. Mangoo Ram and V. K. Bansal. for the workman : Petitioner in Person.

INDUSTRY : Food Corporation of India STATE-Punjab.

AWARD

Dated, the 14th of August, 1985.

The Central Govt. Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under section 10 (1)(d) of the Industrial Dispute Act 1947, vide their Order No.L-42012 (24)|83. D. II (B)|D. IV (B) date the 16th March, 1984 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adudication :—

> "Whether the action of the management of Food Corporation of India in relation to Punjab Region, Chandigarh, in denying full wages for suspension period from 9-8-74 to 19-7-76 and stoppage of an increment with cumulative effect of Sh. Pawan Kumar Singla Watchman at Sangrur is justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. Brief facts of the case, according to the petitioner workman; are that he has posted as a Watchman under the Respdt. Corporation in district Ferozepur in the year 1974 and was a "protected workman"? It was alleged that the management did not take kindly to his Trade Union activities and, thus, with a view to harras him, placed him under supension w.e.f. 9-8-74 on some vague, false and fabricated charges. Even though the supension was revoked on 15-7-76 yet he was subjected to a departmental inquiry; that on the conclusion of such proceeding the Punishing Authority passed the impunged order stopping his one increment with cumulative effect 1-1-82. eeling aggrieved, the petitioner approached his Union who raised a demand on the Management for withdrawing the order of punishment and also for the release of his full wages for the suspention period. However the Management was found unresponsive despite the intervention of the A.L.C. (C) at the Conciliation stage and hence the Reference.

3. The petitioner assailed the inquiry proceedings on the ground that he was not given a fair opportunity to project his defence, that some of the important witnesses were with held by the management, that the Enquiry Officer failed to properity appreciate the evidence because of certain inexplicable bias and that the Disciplinary Authority did not even care to apply its mind to the findings of the Enquiry Officer at the time of passing the impunged order of punishment. It was further avered that the petitioner was a victim of double copardy in the same that he was transferred from district Ferozepur to Dist. Sangrur, denied full wages for the suspension relied and deprived of the Annual increment with cumulative effect. He, thus prayed for quashing the charge sheet itself and claimed release of his full scale wages alongwith the forfieted increment.

4. Resisting the proceedings, the management denied the insinuation of frowning upon the petitioner's Trade Union activities and refuted his claim of being a "protected workman'. The burden of their pleadings was that he often indulged in subversive activities of the type which could be detrimental to the efficient management and congenial atmosphere in an industrial activity, that he was a habitual trouble shooter who black mailed his senior officers with false and frivolous complaints and that he not only lacked devotion to duty but was also making a mockery of discipline which had the natural effect of spreading contemination amongst his co-workers. For the obvious reasons they denied the allegation of any flaw in the conduct of the departmental proceedings and contended that the same were gone through in accordance to the principles of enquiry, i.e., pay, and natural justice as also within the framework of the FCI Staff Regulation. Similarly the validity of the impunged Order was also asserted.

5. In support of his case the petitioner examined himself and filed a number of documents whereas the management felt satisfied with the deposition of their Asstt. Manager Sh. Mangoo Ram. I have carefully gone throuh the records and heard the parties.

6. The petitioner submitted that he was not supplied with all the documents forming basis of the charge sheet and that his prayer for examining sarvshri S. P. Didi and Jagir Singh during the course of nquiry was rejected by the Enquiry Officer and thus he was deprived of a fair opportunity to project his defence.

7. Despite its seeming attraction the submission failed to carry conviction with me because a bare perusal of the memorandum Ex. W4 filed by the petitioner himself alongwith its annexures, would leave no manner of doubt that all the relevant documents were supplied to him alongwith a precis of the allegations before the start of domestic enquiry. And so far as the non production of sarv-Sh. S. P. Didi and Jagir Singh is concerned the same requires appraisement against the backdrop that the disputed complaint, which formed the subect matter of the Enquiry, was alleged to have been manoeuvred by the petitioner against these very officers. There is no gain saying that they were the immediate boss and senior officers of the petitioner. Therefore it was rightly explained on behalf of the management that the petitioner's effort to drag them in the witness box during the departmental proceeding was designed just to embarrass, if not to humliate, them with irresponsible and motivated suggestions.

8. Be that as it may, the Management examined no less than seven persons from amongst the signatories of the Complaint and their depositions were quite consistent to show that he had procured their signatures on it without apprising them of the contents. On the other hand the petitioner could not impeach their credibility despite grilling cross-examination. In short, there was nothing to show that any of them had any bias or prejudice against him to disown the contents of the complaint. It is besides the point that I am not supposed to sit as a Court of Appeal over the manner of appreciation of evidence or findings of fact concluded in the domestic forum unless the same are shown to be based on "no evidence" or otherwise perverse.

9. Petitioner's next submission was that the Enquiry Officer had exonerated him of the general charge relating to encouraging indiscipline and insubordination amogst the staff, but even then he was punished solely on this very ground; meaning thereby that the Disciplinary Authority did not apply its mind while passing the impunged Order. The petitioner appears to have a valid propose on this count because from the relevant document Ex. W35 it transpires that the Enquiry Officer had exonerated him of the afore said charge though he held him guilty of manoeuvring a complaint against his senior officers sarvshri S. P. Didi and Jagir Singh, whereas in the impunged order Ex. W34 the Disciplinary Authority did not make any reference whatso ever to the established charge and proceeded to punish him on the charge which was not sustained by the Enquiry Officer.

10. It may not, perhaps, be disputed that a Disciplinary Authority has a ligitimate right and privilage to differ with the Enquiry Officer but in that case he is obliged to say so

either expressely or by necessary implication. It is besides the point that in such like situations even the delinquent employee should also be heard at the time of reversal of the findings of the Enquiry Officer. And since no such exercise was undertaken by the Disciplinary Authourity in the instant case, therefore, I feel that it will not be fair to the petitioner if I were to sustain the impunged Order as such.

11. At the risk of repetition it may again be mentioned that the only charge which could be proved against the petitioner related to a complaint manoeuvered against some of his senior officers by misusing his position in the workers Union. Of course there is no evidence on record to accept him as a "protected workman" within the meaning of Section 33 (3) and (4) of the I. D. Act yet one can not loose sight of the fact that he was probably trying to ventilate a grievance which could be common to all the workers more over it was a solitary and isolated instance without any follow up action, albeit his anxiety and over enthusiasm he went out of the way while raising some imaginary and irresponsible issues and procured the signatures of some of his colleagues without even appraising them of the contents. Be that as it may keeping in view the totality of the situation I feel that it was more of an immature and misguided adventure rather than a malicious act. Hence on setting aside the Order in its entirety I substitute the same with a "Censure"

12. The petitioner had also claimed the relief of recovery of his back wages for the period of suspension with the submission that since the management had restrained his movements by fixing his headquarters for the purpose of holding departmental inquiry, therefore, they had no ustification in making any deduction from his full scale wages. For the legal proposition he relied on the case of B.B.&C. IVs. B. C. Patil and others (1951) II L.L.J. 584 (Bombay).

13. I am afraid the petitioner has tried to read too much in between the lines of the Bombay case which had an entirely different setting of facts On the other hand in the matter of Kesho Ram Cotton Mills Vs. Ganga Dhar AIR 1964 S.C. 703 it was authoriatively laid down that the management has a legitimate right to restrict the grant of full salary of the reliquent employee who is not fully exonerated of the charges during the departmental inquiry; and that, prehaps, sanctifies the Rule 66(6) and (7) of the FCI taff Regulation 1971 conferring such powers on the Management.

14. No other point was raised before me, and thus to sum up my aforesaid discussion on the various aspects of the issue, while sustaining the Management's action in its pith and substance, I modify the order of punishment to the extent indicated in para No. 11 of this Award.

15. Award returned accordingly.

Chandigarh,

14-8-1985.

I. P. VASISHTH, Presiding Officer

[No. L-42012/24/83-D.II(B)/D.IV(B)/D.V]

का. आ. 4300.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम, पंजाब क्षेत्र संगरूर के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण चन्डीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19-8-1985 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 4300.—In pursuance of section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India, Punjab Region and their workmen, which was received by the Central Government on the 19th August, 1985.

BEFORE SH. I.P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVT., INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH.

Case No. I.D. 32 of 1984. Chandigarh

PARTIES:

Employers in relation to the management of Food Corporation of India.

AND

Their Workman: Sh. Mohinder Singh

APPEAREANCES:

For the Employers: S/Sh. Mangoo Ram and V.K. Bansal

For the Workman: Sh. P.K. Singla

INDUSTRY: Food Corporation of India

STATE:Punjab

AWARD

Dated, the 13th of August, 1985

The Central Govt., Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10 (1) (d) of the Industrial Disputes Act 1947, hereinafter referred to as the Act, vide their Order No. L-42012 (14)/83-D. IV (B)/D.V. dated the 21st August, 1984 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication.—

"Whether the termination of employment of Shri Mohinder Singh, Watchman Food Storage Depot, Sangrur by the management of Food Corporation of India is justified and legal? If not, to what relief the workman Shri Mohinder Singh is entitled to and from what date?"

2. Brief facts of the case according to the petitioner workman are that he was employed as a Casual watchman under the respdt. Corporation in district Sangrur w.e.f. 5-2-1982 and continuously worked for them till his services were abruptly terminated on 23-5-1983 without any notice and paymnt of terminal benefits etc. He therefore, raised an issue through his Union and tried to impress upon the Management the properiety of withdrawing the "Termination" which was in flagrant violation of the mandatory provisions of Section 25F, 25-G, 25-H and 25-N of the Act. However the management was found unresponsive despite the intervention of the A.L.C. (C) at the Conciliation stage and hence the reference.

3. Resisting the proceedings, the Management contended that the petitioner was a volunteer of the Punjab Home Guard and engaged by them as a Casual watchman on loan basis for guarding foodgram stock kept temporarily in the open; that he was paid wages at the D.C. rates fixed for such like workers and had served them intermittently from 5-2-82 till his disengagement in May 1983 without completing 240 days' service in an year .It was alleged that he was no maintaining absolute devotion to duty and lacked integrity in as much as on 22-5-1983 and 23-5-83 he marked his "attendance" in register even though he was absent on both these days.

4. Elaborating their version, the Management explained that since the petitioner was governed by Home Gurds Act and was working with them on loan basis, therefore, they were not competent to take any action against him for his misconduct and thus repatriated him to his parent department on 23-5-1983, when the aforesaid fabrication in the Attendance Register was detected. For the obvious reason they avared that it was not a case where they could be required to comply with the provisions of Section 25-F etc. of the Act.

5. In support of his case, the petitioner examined himself and filed a number of documents whereas the management felt contended with the deposition of their District Manager Shri T.R.K. Murti. I have carefully persued the entire available data and heard the parties.

6. As would be evident from the history of the case, the first and foremost point, which calls for adjudication, is as

to whether the petitioner was an employee of the Respt. Corporation and as to whether he had put in one year's continuous service within the meaning of Section 25-B of the Act by the time of his unilateral disengagement. There is no gainsaying that no terminal benefits were accorder to him and that there was any element of assumed misconduct in the incident albeit no formal Inquiry was ever held.

7. The Management's contention that the petitioner was working with them on loan basis (being a volunteer of the Punjab Home Guard) and that there was no privity of contract to infer a Master-Servant relationship between the parties is devoid of force of course the petitioner was a volunteer in the Punjab Home Guard but all the same the pertinent point is as to whether he was regularly employed there and was drawn on loan by the Respdt. Corporation? In my considered opinion had it been so there should have been some correspondance between the Respdt. Corporation and the Punjab Home Guard; but no such information was revealed for judicial scrutiny: similarly there is no material on record to show that it was an oral arrangement made either on an "across the table discussion" between the Punjab Home Guard and the Respdt. Corporation or by sendng an oral requisition through some identifiable channel. To crown it all, no evidence was collected from the Punjab Home Guard either to corborate the proposition or to show that he was their employee. As a matter of fact, barring a vague and wild assertion in the Written Statement and the affidavit of the District Manager Shri Murti, there is no evidence on record throw any light on such a curcil aspect of issue. On the other hand, on its own showing, the Respdt. Corporation was utilising his services continuously from 5-2-82 to 26-2-1982 and again from 3-8-82 up to 23-5-1983 as per disclosures in para No. 5 of the affidavit Ex. M1 of Shri Murti.

8. And so far as the petitioner's enrolement as a volunteer of the Punjab Home Guard is concerned that hardly deteriorates his position as an employee of the Respdt. Corporation because under the scheme of the Home Guard Act his type of Class IV employees of Public Sector Undertakings can legitmately be enrolled and kept on the live-rolls of the Punjab Home Guard even during their whole-time employment with the F.C.I. who rather have a statutory obligation to relieve them for call out duty and routine parade etc. whenever so required by the Home Guards.

9. Be that as it may, there is very significant piece of evidence exposing the hollowness of the Respdt's version. During the cross-examination of their District Manager Shri Murti, it was suggested to him that at an earlier stage also the petitioner's services were illegally terminated and then there arose a dispute which was amicably settled through the intervention of the A.L.C. (C) Chandigarh, and that Memorandum of Settlement was also drawn and signed by the parties under Section 12 of the Act as a result of which the petitioner was re-engaged on 3-8-1982. Shri Murti could not controvert the proposition and rather feigned ignorance; on being confronted with the original Settlement, he evaded the issue on the pretext of uncertainty. All the same he could not disown the Settlement whose printed copy Ex. W8 was filed by the Petitioner. On latter's behalf it was rightly urged had Sh. Murti's ignorance been ignoenous, it remains to be explained as to then, how and why the petitioner was re-engaged on 3-8-82 after his disengagement on 26-6-82; as admitted in para No. 5 of his own affidavit Exb. M1 [Sh Murti's Affidavit.]

10. On behalf of the Management it was argued that if the petitioner were to be in their employment he would have been paid wages in accordance to the calander months rather than on daily basis at the D.C. rates; and would have also been assigned a particular seniority, but according to his own case no such facility was given to him; meaning thereby, that his services were of a purely temporary and casual nature.

11. I am afraid a misguided effort has been made to equate a casual and Temporary daily wager with an employee drawn on "loan" from some other department. The theory of "Loan basis engagement" has already been discussed and discarded by me whereas the casual nature of his tenure does not take their cause anywhere because the definition of a "Workman" as propounded in Section 2 (s) of the Act is wide enough to include in its ambit even Casual work-force. For my views I draw support from the observations in the cases of Pilot Pen Company (Ind.) Pvt. Ltd. Vs. Presiding Officer Additional Labour Court *1979 (1) L.L.J.* 241 and Crompton Engineering Co. (Madras) Public Ltd Vs Additional Labour Court Madras 1975 (1) L.L.J. 207.

12. Hence, in view of what has been stated above, on accepting the petitioner as an employee of the Respdt. Corporation I proceed further to examine as to whether he had put in more than one year's continuous service within the meaning of Section 25-B of the Act by the time of his unilateral disengagement.

13. On behalf of the management it was argued that in the year 1981 the petitioner had put in only 54 days service from 16-3-81 up to 1-6-81; then he was re-employed on 5-2-82 and worked for them up to 26-6-1982; and his last engagement from 3-8-1982 continued up to 23-5-83, meaning thereby that he had not completed 240 days service in any of the three calendar years. In short requirement of 240 days service in one particular calendar year was sought to be impressed upon the Tribunal which, in my considered opinion, is highly misconceived for reasons more than one.

14. The first and foremost point is that there is no sanction for such a proposition in the phraseology of section 25-B of the Act; the second aspect is that it being a beneficient legislation its interpratative benefits would go to the workman rather than to the Employer. The third angle is that if the argument were accepted on its face value and taken to the logical end it would frustrate the very purpose of the statue. To be illustrative, suppose a person were to join service with an Organisation w.e.f. 1st July, 1984 and disengaged on 30th June 1985, he would not be heard saying that he had put in one year's continuous service because in neither of the two calender years he had done 240 days. Perhaps it was with a view to over come such practical difficulties that the Hon'Judges of the Supreme Court, if I am permitted to say, were pleased to adoopt a down the earth approach in the case of State Bank of India Vs. Sundra Mony (1976) 1 SCC 822 and Santosh Gupta of State Bank of Patiala AIR 1980 SC 1219 to hold that for the purpose of section 25-B an year means 12 calender months. And it goes without saying that on such parameter, by the time of his disengagement on 23-5-83, the petitioner had certainly put in more than an year's continuous service.

15. I, accordingly, repell the contentions raised on behalf of the management and hold that since the petitioner was entitled for all the terminal benefits which were denied to him; therefore his unilateral disengagement was void-ab-initio.

16. On the other hand if he were to accept the proposition that he had misconducted himself by marking his presence for 22nd and 23rd May 1983 despite absence from duty, the termination would be bad because, shorn of holding a regular enquiry, even a show cause notice was not issued to him. In short it was an ex-party, summary and spot dismissal.

17. No other point was raised before me, and thus to conclude with my aforesaid discussion on the various aspects of the matter, as emerging from the records, on quashing the petitioner's termination I return my Award in his favour with a direction to the Management to re-instate him forth with and treat the intervening period as spent on duty with all the attendant benefits.

18. Award returned accordingly.

[No. L-42012|14|83-D. IV(B) D. V]
I. P. VASISHTH, Presiding Officer
R.K. GUPTA, Desk Officer

नई दिल्ली 19 अगस्त, 1985

का. आ 4301—हौमस मंदाय अधिनियम, 1965 (1965 का 21) की धारा 32 के खंड (9) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय

सरकार भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1985 (1985 का 62) की धारा 3 के अधीन स्थापित एक वित्तीय संस्थान भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को उक्त धारा के खंड (छ) के अधीन वित्तीय संस्था के रूप में निर्दिष्ट करता है ।

[एस- 33012/2/84-डब्ल्यू बी.]
पी. राघवन, उप सचिव,

New Delhi, the 19th August, 1985

S.O. 4301.—In exercise of powers conferred by sub-clause (g) of clause (ix) of section 32 of the Payment of Bonus Act, 1965 (21 of 1965), the Central Government hereby specify the Industrial Re-construction Bank of India, a financial institution established under section 3 of the Industrial Reconstruction Bank of India Act, 1985 (62 of 1985), as a financial institution under clause (g) of the said section.

[S. 33012/2/84-WB]
P. RAGHAVAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1985

का. आ. 4302:—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार सिंगरैनी कोलरीज कम्पनी लि. कोठागुडम डिविजन डाकघर वेंकटेश खानी, जिला खम्मम के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करता जो केन्द्रीय सरकार को 27 जुलाई 1985 को प्राप्त हुआ था :

New Delhi, the 20th August, 1985

S.O. 4302.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudum Division, Post Office Venkatesh Khani Distt. Khammam, and their workmen which was received by the Central Government on the 27th July, 1985.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

PRESENT :

Sri J. Venugopala Rao, Industrial Tribunal.

Industrial Dispute No. 60 of 1984

BETWEEN

The Workman of *Singarani Collieries* Company Limited, Kothagudam Division P. O. Venkateshkhani, District Khammam.

AND

The Management of Messrs Singarani Collieries Company Limited, Kothagudem Division, P.O. Venkatesh Khani, District Khammam. (A.P.).

APPEARANCES :

Sri D.S.R. Varma, Counsel—for the Workmen.

Sarvasri K. Srinivasa Murthy, H. K. Saigal and Kum. G. Sudha, Advocates—for the Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-22012/112/83-D. III(B) dated 2-3-1984 referred the following dispute under Sections 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employers in relation to Messrs. Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem Division, P.O. Venkatesh Khani District Khammam and their workmen to this Tribunal for adjudication.

"Whether the management of Messrs. Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem Division, P.O. Venkatesh Khani, are justified in refusing category V wages to Shri Tanguturi Posham, Fitter No. 5A Incline, with effect from 24-9-1980? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

This reference was registered as Industrial Dispute No. 60 of 1984 and notices were issued to the parties.

2. The workmen filed their claims statement and Sri D.S.R. Varma filed his vakalat for the workmen. Sarvasri K. Srinivasa Murthy, H. K. Saigal and Miss Sudha filed their vakalat and counter for the Management . The matter was adjourned from time to time for reporting settlement. On 17-7-1985 both the counsels present and filed a compromise petition praying to treat this I.D. No 60 of 1984 as closed since the Management have agreed to place Sri Tanguturi Posham, Fitter, No. 5A Incline, Kothagudam Division in Category V with effect from 1-3-1981 and the Union has agreed to withdraw the case.

3. Having gone through the compromise petition I find that the settlement is fair, proper and just and award is passed accordingly, treating this industrial dispute as closed.

Award is passed and a copy of the compromise petition is enclosed herewith.

Given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 17th day of July, 1985.

Sd/-

INDUSTRIAL TRIBUNAL.

Appendix of Evidence.

Nil

Dated : 17-7-85.

J. VENUGOPALA RAO, Industrial Tribunal

[No. L-22012(112)/83-D. III(B)]
HARI SINGH, Desk Officer

Compromise Petition to be filed the respect of I.D. No. 60/84 with regard to Shri Tanguturi Posham, fittier, Cat. IV, No. 5 Incline claiming for Cat. V wages, Between management of Singareni Collieries Company Limited and workers represented by S. C. Workers' Union.

The workman filed a claim vide letter No. GS/ID/SA/6084 dated 12-11-1984. The Management in turn filed their Counter statement on 21-12-1984.

The Management and the Union have discussed the Issue mutually and decided to compromise on this issue. The Management have agreed to place Sri Tanguturi Posham, Fitter, No. 5A Incline, Kothagudem Division in Cat. V with effect from 1-3-1981 and the Union has agreed to withdraw the case. Hence in view of the above a compromise petition is herewith filed.

In view of the foregoing, we pray the Hon'ble Industrial Tribunal (Central)/Hyderabad, to treat this I.D. No. 60/84 as closed.

Union's Representatives :
S. K. IMAM

Management Representatives:
G. AILAIAH, Personnel Officer

Jt. Secretary,
S.C.W. Union.

H. K. SAIGAL, Counsel for the management.

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1985

का. आ. 4303.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एम. एल. पाल को मध्य प्रदेश, इन्दौर के लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के रूप में श्री एस. आर. दास गुप्ता के स्थान पर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए नियुक्त करती है।

[सं. ए-12017/1/85-एस. एस-3]
चित्रा चोपड़ा, निदेशक

New Delhi, the 23rd August, 1985

S.O. 4303.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5D of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri M. L. Pal as Regional Provident Fund Commissioner for the Madhya Pradesh Region, Indore, to assist the Central Provident Fund Commissioner in the discharge of his duties vice Shri S. R Das Gupta.

[No. A-12017(1)/85-SS. III]
SMT. CHITRA, CHOPRA, Director

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1985

का. आ. 4304.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इण्डिया के प्रबंधतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16 अगस्त, 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 23rd August, 1985

S.O. 4304.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the United Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th August, 1985.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I.D. No. 76/81

In the matter of dispute between :
Shri P. C. Jain, workman represented by United Bank of India Sramik Karamchari Samity.

Versus

United Bank of India, New Delhi.

APPEARANCES :

Shri R. C. Danwar—for the workman.

Miss Geeta Sharma—for the Management.

AWARD

Central Government, Ministry of Labour on 23-6-81 vide Order No. L-12012/158/80-D. II. A made reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of United Bank of India, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi in not posting Shri P. C. Jain, Cash-cum-General Clerk to their small Business Development Office, Asaf Ali Road, New Delhi with effect from 23-5-78 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled to?"

2. Mr. P. C. Jain was the senior-most Cash-cum-General Clerk at Delhi then posted at Timarpur Branch of the Bank. The United Bank of India had to fill the post of Cash-cum-General Clerk with Head Cashier's allowance at S.B.D.O. Asaf Ali Road on 23-5-78. A person junior to Shri P. C. Jain was appointed there and Mr. P. C. Jain was not appointed. Mr. Jain represented immediately against his being ignored and the Union of workmen also took up his case. Subsequently Mr. P. C. Jain was appointed Cash-cum-General Clerk with Head Cashier's allowance at the Regional Office in May, 1979 and latter he was transferred to S.B.D.O. Asaf Ali Road on 7-4-80.

3. In the statement of claim the workmen's Association claims that Mr. P. C. Jain was ignored for the posting at Small Business Development Office Asaf Ali Road, New Delhi from 23-5-78 till 7-4-80 in an illegal and clandestine manner and that the posting of his junior Mr. H. S. Bhatia, at SBDI Asaf Ali Road was irregular and unfair and that the Management of United Bank of India should be ordered to give benefit of Head Cashier's allowance to Mr. P. C. Jain with all other benefits w.e.f. 23-5-78 since when he was to be posted whereas his junior was posted as Cashier-cum-General Clerk with Head Cashier's allowance at SBDO Asaf Ali Road, Delhi.

4. The Management of United Bank of India contested the claim. It was asserted that the reference was not maintainable because the workman had been promoted to Officer Cadre on 19-4-80 even before the conciliation proceedings.

5. On merits, the plea raised was that the workman had in February, 74 requested for and made an option to be transferred to Timar Pur Branch which was done and that option exercised by him disentitled him to a further transfer to S.B.D.O. Asaf Ali Road and that was the reason why the other person was appointed at S.B.D.O. Asaf Ali Road and that P. C. Jain had forefeited his right to be appointed at S.B.D.O. on account of his option earlier made for transfer to Timarpur Branch.

6. The workmen in their rejoinder contested the Management's pleas and asserted that in accordance with the Bank's own policy Management had to issue a circular asking for option from senior-most persons for the allowance carrying position at S.B.D.O. which it failed to do and that subsequently the Management realised this mistake and gave option to P. C. Jain for similar allowance carrying post at Regional Office Delhi in 1979 and finally transferred P. C. Jain in 1980 to S.B.D.O. Asaf Ali Road and that the transfer option earlier made in 1974 had no effect and that in fact two options could be made by the workman under the policy of the Management and that the benefit of Head Cashier Special Allowance to P. C. Jain have been with held by the Management in a foul manner and the unfairness to the workman had to be set at naught.

7. The matter in reference has been tried and Sh. S. C. Dev, Regional Manager filed his affidavit and has been cross-examined by the workman. Shri P. C. Jain filed his own affidavit and he has also been crossexamined by the Management. Written arguments have been filed by the workmen and oral arguments of the Management's Advocate have been heard.

8. It appears that P. C. Jain has been unfairly treated. The workman made an application on 15-12-83 demanding from the Management copy of the circular issued by them in April-May, 1978, if any, inviting option from the staff members for the office of S.B.D.O. Asaf Ali Branch as per

practice of the Bank or other circular to that effect, if any, but the Management did not produce any such circular and the circular attached to the affidavit of Shri S. C. Dev, Regional Manager dated 9th May, 1977 relates to proposed office at Chandni Chowk S.B.D.O. Delhi and does not relate to opening of S.B.DO. Office at Asaf Ali Road. In this situation the Management plea is wrong that they invited options for the Cash-cum-General Clerk post at S.B.D.O. Asaf Ali Road, New Delhi and the workmen appear to be on sound footing when they urged that action was taken secretly without issuing the circular letter as per practice of the Management an da letter was issued in respect of posting of Clerk-cum-Cashier with Head Cashier allowance at the Regional Office on 2|3-5-79 to P. C. Jain in the following terms :

"UNITED BANK OF INDIA

Regional Office,
North India Region,
206-208 Ansal Bhawan,
16, Kasturba Gandhi Marg,
New Delhi-110001.
Ref. No. NIP/DRM/STF|6118|79 2|3-5-79.
Sri P. C. Jain,
C/o United Bank of India,
Timarpur Branch.

Dead Sir,

Please let us know whether you are willing to accept the post of C.C.G., at our office. The said post of C.C.G- is Head Cashier's Allowance bearing. Also let us know your present qualification and date of appointment.

All the above information should us within a period of 4 days from the date hereof.

Yours faithfully,
Sd/- illegible
Dy. Regional Manager."

9. A reference to the Management's circular relating to transfers No. PD/763/73 dated 6th March. 73 Annexure B to the affidavit of Sh. Dev indicates that two prayers for transfer can be entertained and not more than two such prayers can be entertained does not show that P. C. Jain made more than one transfer prayer.

10. In view of the aforesaid circumstances, the complaint of the Union of workman against the Management is sound that the posting of a junior official at S.B.D.O. Asaf Ali Road from 23-5-78 was done in a secret irregular manner thereby violating the rightful claim of posting as Clerk-cum-Cashier with Head Cashier's allowance at S.B.D.O. Asaf Ali Road, New Delhi of P. C. Jain, affected official and Mr. P. C. Jain is entitled to the Head Cashier's allowance since 23-5-78 and the Management of United Bank of India is ordered to pay him that allowance since that date. The Award is made accordingly.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

August 13, 1985.

O. P. SINGLA, Presiding Officer
[No. L-12012/158/80-D. II(A)]

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1985

का. आ. 4305.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार सिटी बैंक. एन. ए., नई दिल्ली के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16 अगस्त 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 29th August, 1985

S.O. 4305.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the City Bank N. A. New Delhi and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th August, 1985.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I. D. No. 4/79

The matter in dispute between :
City Bank Staff Association, Parliament Street, New Delhi.

Versus

City Bank N.A. New Delhi.

APPEARANCES :

Shri S. K. Bisaria Advocate—for the workman.
Shri J. K. Mehra Advocate—for the Management.

AWARD

Central Government, Ministry of Labour on 23-1-1979 vide Order No. L-12012/97/78-D.II (A) made reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the Citi Bank N.A. New Delhi in refusing the personal loan to Miss Neena Saxena, Stenographer is justified ? If not, to what relief she is entitled ?"

2. The City Bank Staff Assoacition in a statement of claim asserted that the Management had the policy of providing the facility of loans to its employees for purpose of housing as well as personal loans in times of need and financial emergency and this loan facility had become a Condition of Service of the employees by practice and custom.

3. Miss Neena Saxena employee applied for a personal loan of Rs. 5000 in October, 76 for purchase of house-hold appliances and the same was recommended by Shri C. R. Sharma, Assistant Manager, but Mr. A. Somasekhar, A. M. with whom she was attached as Stenographer refused to forward the loan application and she could not get the loan sanctioned. It was refused to her on the alleged ground of her irregular attendance. The workmen's case is that she took leave on medical certificate or it was otherwise sanctioned by the Management and she took leave only as and when circumstances were beyond her control and that she was denied loan because she was active in Union activities.

4. The Association requested that the Tribunal may direct the Management to grant personal loan of Rs. 5000 to the workman.

5. The Management contested the claim and raised a few preliminary objections.

6. On facts, it was pleaded that the grant of loan to any member of staff was purely a Management prerogative and purely within the discretion of the Management and any application for grant of loan could be rejected without assigning any reason whatsoever. She was not granted loan because she was irregular in attendance but the rejection had nothing to do with any Union activity of the workmen. The allegations were said to be irrelevant.

7. The following issues were settled :

i. Whether the reference relates to an Industrial Dispute ? If so, to what effect.

ii Whether granting of personal loan is a condition of service and has the force of a legal right as

alleged in the statement of claim ? If so, to what effect.

iii. As in terms of reference.

8. The workman examined only Mr. K. L. Malhotra. Mr. S. K. Maini filed affidavit but was not tendered for cross-examination. Miss Neena Saxena did not appear as a witness.

9. The Management examined Mr. Rajeshwar Kumar, Assistant Manager. The written arguments of the parties are on record and have been perused.

10. During the pendency of this reference Mr. S. K. Maini made a complaint that he was a 'Protected workman' and was General Secretary of the City Bank Staff Association and after making of the reference I. D. 4/79 he had been denied a personal loan of Rs. 4000 which sought at the time of his marriage in February, 1980 and that this was violation of condition of service during the pendency of the reference and fell within the ambit of section 33 (3)A of the I. D. Act which was registered as I. D. 72/81.

11. So far as Mr. Maini's complaint I. D. 72/81 is concerned, no action need be taken on it because today R. N. Tewari, Assistant Secretary stated that S. K. Maini had received personal loans to the extent permissible to him and he withdrew the complaint of Mr. Maini in which no relief can be given.

12. So far as the main reference is concerned, the Management itself has filed my Award in I. D. 7/79 in First National City Bank Staff Association Vs. Manager, City Bank, New Delhi decided on 5-2-85 and in that Award it was ruled that the grant of personal loans and the interest to be charged thereon was definitely a matter concerning the condition of service of the workmen and in that case the rate of interest was directed to be changed by the Management. However, it was observed that the Management had the right to decide on an individual loan application.

13. In view of that decision the preliminary objections of the Management fail and it is a question to be decided on merit whether the discretion of the Management was properly exercised in this case or not. In the case of refusal of loan to Miss Neena Saxena. Mr. Rajeshwar Kumar MW-1 has shown that personal loans were allowed and disallowed at New Delhi and Bombay as under :

"NEW DELHI

LOANS TURNED DOWN :

1. Ram Sawrup (NU) November, 1978, February 10, 1977.
2. J. N. Nigam (U) Thrice February, 1978, October, 1977 and August, 1978.
3. P. Balasubramaniam (U) April, 1979.
4. S. K. Maini (U) Twice November, 1979, February, 1980.
5. K. L. Malhotra (U) September, 1979.
6. A. N. Tiwari (U) Twice February, 1979, March, 1980.
7. R. L. Vohra (NU) March, 1976, April, 1976.

LOANS GRANTED :

1. A. N. Tiwari (U) January, 1980, February, 1972.
2. J. N. Nigam (U) March, 1980.
3. K. L. Malhotra (U) March, 1980, June, 1970.
4. Ram Swarup (NU) June, 1980, August, 1968, May, 1972 April, 1981, May 14, 1969.
5. P. Balasubramaniam (U) May, 1980.
6. A. N. Tiwari (U) August 1981, September, 1982.
7. K. L. Malhotra (U) October, 1981.
8. S. K. Maini (U) February, 1983, February, 1983.

BOMBAY :

1. H. J. W. Coats February, 1979.
(Not a member of union when loan was turned down. Subsequently became member of union)

LOANS TURNED DOWN :

1. K. S. Aiyer (NU)
2. P. Banerjee (NU)
3. T. K. Bose (U)
4. P. C. Debnath (NU)
5. A. K. Dhole (NU)
6. M. K. Kanjilal (U)
7. T. K. Ghosh (U)
8. S. C. Mukherjee (U)
9. B. K. Nandi (U)
10. A. Chakraborty (NU)
11. D. Sengupta (NU)
12. B. C. Saha (U)
13. A. Ghosh (NU)

GRANTED :

1. K. S. Aiyer (NU)
2. P. Banerjee (NU)
3. T. K. Bose (U)
4. M. K. Kanjilal (U)
5. S. C. Mukherjee (U)
6. A. Chakraborty (NU)
7. B. C. Saha (U)
8. Anima Gosh (NU)"

14. In the aforesaid annexure (U) means member of Union at the time of grant or refusal of loan and (NU) means not member of the Union at the time of grant or refusal of the loan.

15. Further, Rajeshwar Kumar explains that in the case of Shri K. L. Malhotra who was Founder President of the Local Branch and President of the Federation of Union of all Branches in India, the Management granted him personal loan in October, 1981 and earlier in September, 1979 and that Mr. S. K. Maini was granted personal loan in February, 1983 twice and that P. Balasubramaniam was also granted loan in March, 80 and so also A. N. Tiwari in August, 81 and September, 82 and that the refusal of loan to Miss Neena Saxena was not whimsical.

16. It cannot be said from the evidence produced that as a policy of penalising the office-bearers of the Association as claimed by the workman the officers of the Union have not been granted personal loans and at present S. K. Maini has been granted loans to the maximum extent permissible and similar is the case with Miss Neena Saxena who on 26-9-83 was granted personal loans amounting to Rs. 24500 and her entitlement was Rs. 24502.16 p.

17. Miss Neena Saxena has not come forward to explain the circumstances which necessitated the grant of loan to her for purchase of house-hold appliances at the relevant time and she has not subjected herself to cross-examination of Management to show her irregularity in attendance. In the circumstances I am of opinion that the Management cannot be faulted for rejecting the loan application of Miss Neena Saxena and it has not been shown to be malafide decision by the Management in the refusal of loan to her at the relevant time.

18. Accordingly I hold that the grant or refusal of personal loan to an individual is a matter of exercise of sound discretion by the Management but the granting of loans and the interest thereon are matters of condition of service of the workmen.

19. The analogy is there in the case of Earned Leave the grant of Earned Leave the quantum of it are rights of the workmen but whether any individual application for grant of Earned Leave is to be allowed or not is a matter in the sound discretion of the Management. Similar is the case with the grant of Personal Loans. Miss Neena Saxena is not entitled to any further relief even though the grant of personal loans has been held to be the condition of service of the workmen.

Award is made accordingly.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

O. P. SINGLA, Presiding Officer

August 7, 1985.

[No. L-12012/97/78-D.II (A)/D.IV (A)]

का. आ. 4306—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार फेडरल बैंक लिमिटेड इरोड के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद, में औद्योगिक अधिकरण मद्रास के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 19 अगस्त 1985 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 4306.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Federal Bank Limited, Erode and their workmen which was received by the Central Government on the 19th August, 1985.

BEFORE THIRU K. E. VARADHAN, B.A., B.L., PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMILNADU, MADRAS

(Constituted by the Central Government)
Thursday, the 8th day of August, 1985
Industrial Dispute No. 44 of 1985

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workman and the Management of the Federal Bank Limited, Erode-638001, Periyar District)

BETWEEN

Shri R. Narasimhan, 33, Pachiamman Koil Street, Karungalpalayam, Erode, Periyar District, Tamil Nadu.

AND

The Manager,

The Federal Bank Limited,

P.B. No. 53, 151-152, Netaji Road, Erode-638001, Periyar District,
Tamil Nadu.

REFERENCE :

Order No. L-12012/26/84-D.IV (A), dated 1st July, 1985, Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on this day for final hearing upon perusing the reference and other connected papers on record and the Petitioner-Workman having filed a letter of withdrawal and recording the same, this Tribunal passed the following :

AWARD

The parties in this industrial dispute are the Management of the Federal Bank Limited, Erode, Periyar District and their workman Thiru R. Narasimhan and the reference under Order No. L-12012/26/84-D.IV (A), dated 1-7-1985 from the Ministry of Labour of the Central Government, seeks the adjudication on the issue as to "Wehther the action of the management of the Federal Bank Limited, Always in relation to their branch at Erode, District Periyar, Tamil Nadu, in terminating the services of Shri R. Narasimhan, ex-workman with effect from 5-3-1982, is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. Summons were issued to the parties for 8-8-1985. A letter was received in this Tribunal from the Petitioner-workman on 16-7-1985 stating that he withdraws this dispute. The same is recorded.

3. In view of the letter of withdrawal by the Petitioner-workman, this industrial dispute is dismissed as settled and withdrawn. Award is passed accordingly. No costs.

Pronounced in open court, this 8th day of August, 1985.

K. E. VARADHAN, Industrial Tribunal

[No. L-12012/26/84-D.IV (A)]

K. J. DYVA, PRASAD, Desk Officer

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1985

का. आ. 4307—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्ज नवजीवन एजेंसीस बंबई के प्रबंधतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं. 1, बंबई के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 20 अगस्त, 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 30th August, 1985

S.O. 4307.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the M/s. Nav Jeevan Agencies, Bombay, and their workmen, which was received by the Central Government on the 20th August, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

PRESENT :

Dr. Justice R. D. Tulpule Esqr., Presiding Officer.

Reference No. CGIT-3 of 1985

Employers in relation to M/s. Nav Jeevan Agencies, Bombay,

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the employer—Mr. Verma, Advocate.
For the workmen—Mr. Wagh, Advocate.

INDUSTRY : Ports and Docks STATE : Maharashtra

Bombay, the 12th day of July, 1985

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by Order No. L-31012/2/84-D.IV (A) dated 2nd February, 1985 in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Nav Jeevan Agencies, Bombay and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule mentioned below :—

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s. Nav Jeevan Agencies, Bombay in terminating the services of Shri P. B. Chavan with effect from 2-11-1982 is justified ? If not, to what relief the workmen is entitled ?"

2. Parties filed their respective statements in support of their contentions. It was then when the matter came up for hearing settlement talks were begun.

3. Today when the matter was called out again the parties informed that they have settled the dispute and filed the terms of settlement. All the parties including the workman were present. He accepts this settlement. I am satisfied that it is genuine. I accept the settlement and pass an award in terms of the settlement.

4. Award accordingly.

R. D. TULPULE, Presiding Officer

[No. L-31012/2/84-D.IV (A)]

का. आ. 4308—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार सिटी बैंक एन. ए., नई दिल्ली के प्रबंधतंत्र से

सबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16 अगस्त, 1985 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 4308.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal New Delhi, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the City Bank N.A. New Delhi and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th August, 1985.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I. D. No. 104/80

In the matter of dispute between :

First National City Bank Staff Association, New Delhi.

Versus

City Bank N.A. 3, Parliament Street, New Delhi.

APPEARANCES :

Shri J. K. Mehra Advocate—for the Management.
Shri S. K. Bisaria Advocate—for the workmen.

AWARD

Central Government, Ministry of Labour on 20-9-1980 vide Order No. L-12012/92/80-D.II (A) made reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Citi Bank, New Delhi in ignoring the claims of S/Shri P. Balasubramaniam and V. P. Mallik and promoting their junior Shri B. K. Malhotra to the post of Authorised Signer, is justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?"

2. The Citi Bank Staff Association, New Delhi is unhappy over the promotion given to Shri B. K. Malhotra by the Management of Citi Bank ignoring the claims of S/Shri P. Balasubramaniam and V. P. Mallik who were senior to B. K. Malhotra in the clerical cadre. The workmen's case is that the legal rights of the senior-most persons working as Special Assistants had been denied and the promotion given to B. K. Malhotra was a favourtism and against settled promotion policy mutually agreed upon between the workmen and the Management, and B. K. Malhotra was made an Officer known as Authorised Signer on 1-3-78 illegally ignoring the legal and fundamental rights of senior-most person P. Balasubramaniam and V. P. Mallik. It was said to be a policy of 'pick and choose' that was operative and the pleasure of the Management had taken place of respect for continuity and seniority in the clerical cadre especially those who were acting as Special Assistants.

3 The Management of Citi Bank contested the claim and asserted that there was no mutually agreed promotion policy of respect for seniority alone and that the only settled policy was suitability for a particular post before promotion.

4. In respect of B. K. Malhotra it was stated that Mr. B. K. Malhotra joined the bank in 1969 as a clerk-cum-typist and became Confidential Secretary-cum-Stenographer on 26-9-72. He was promoted to SSRP (Staff on Special Rates of Pay) in 1975 and as S.S.R.P. he enjoyed a different grade and scale of pay and was a separate category of employee who was not covered by the Bipartite Settlements or Bank Awards and his appointment in 1975 in that category was never challenged. It was in view of his special qualifications that he was made Authorised Signer in 1978. The especial of the dispute by the Association was also challenged.

5. The following issues were settled.

(i) Whether the dispute is properly espoused ?

(ii) As in terms of reference.

6. Management examined Shri Rajeshwar Kumar, Assistant Manager, Citi Bank, New Delhi and the workmen examined Shri P. Balasubramaniam. Written arguments of the parties are on record and have been perused.

7. The only agreed upon Minutes in respect of promotion policy are the Minutes of Meeting with F.N.C.B. Staff Association Executive Committee on March 22, 1973 wherein Mr. L. S. Roncari, G.M., Mr. J. J. Menezes, P.M. and Mr. Viney Sawhney. As were present for the Management. Mr. K. L. Malhotra, Mr. R. L. Seth, Mr. N. K. Khera, Mr. P. Balasubramaniam, Mr. R. C. Gupta, Mr. J. N. Nigam and Mr. C. P. Kapur were present for the workmen.

8. Para 15 of the Minutes requires to be extracted and is as under :

"(15) Officiating Allowance Positions—Clerical and Official.—Mr. Malhotra reiterated that the senior most person in the department should be paid officiating allowance as far as possible so that the employee concerned was able to benefit. He emphasized that the senior most employees in the same department should officiate in case the officer was on leave and he be paid the officiating allowance as per the Bipartite. Mr. Roncari stated that as far as the clerical positions were concerned it was his understanding that the same practice was being followed in New Delhi but in case of official positions the employee should become eligible for officiating allowance only if he strictly performed official functions. According to him no employee could automatically claim allowance for his officer who was on leave.

9. The Management clearly stated that while in case of clerical cadre officiating allowance post was being given on the basis of seniority alone at Delhi, the same could not be accepted in relation to promotion to officer cadre and Seniority alone could not be the base for promotion to officer cadre.

10. In the cross-examination of Mr. P. Balasubramaniam it has been admitted by him that he was junior to S/Shri K. L. Jain, K. L. Malhotra, Surinder Mohan and S. S. Nanda but he got special assistant assignment earlier to them. According to Mr. Subramaniam's own admission even in the clerical cadre he got special assistant assignment earlier to his seniors.

11. Staff on Special Rates of pay (SSRPs) are intermediate cadre between the officers and clerks and that cadre is a short one of four persons at Delhi while there are 25 officers and 50 clerks at New Delhi. That cadre was created only in 1975 but there is no pleading before me that creating of S.S.R.P cadre was only to subvert the promotion policy mutually agreed upon or was an unfair labour practice of the Management. The creation of that small, cadre in 7-4-75 was never challenged and even in this reference it has not been specifically challenged and there is no presumption that the creation of SSRP cadre is a malafide act of the Management intended to harm the clerical cadre. Rajeshwar Kumar has explained that the SSRPs discharge functions including arranging International Conferences in India and they are entitled to take decisions without consulting others as and when occasion arise within certain guidelines given earlier. They can exercise supervision over clerical cadre staff as and when situation or occasion arise these instructions may be oral, telephonic or otherwise.

12. In view of what is stated in the foregoing the promotion to B. K. Malhotra who worked as Confidential Secretary and as S.S.R.P cannot be said to be violation of any settled policy of the Management and cannot be said to be a malafide action of the Management or an unfair Labour Practice by the Management. The promotion to the officer cadre cannot be accepted to be by mere seniority and unless pick and choose and favourtism are clearly established, it is difficult to find fault with the Management's promotion of B. K. Malhotra. Action of the Management appears to be justified and does not call for interference. Award is made against the workmen.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

O. P. SINGLA, Presiding Officer
[No. L-12012/92/80-D.II (A)/D.IV (A)]
Date : 7 August, 1985.

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1985

का. आ. 4309.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार बैंक आफ इण्डिया के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर, का पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22 अगस्त 1985 प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 30th August, 1985

S.O. 4309.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government industrial Tribunal, Kanpur, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the Bank of India, and their workmen, which was received by the Central Government on the 22nd August, 1985.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL KANPUR.

Industrial Dispute No. 99 of 1981

In the matter of dispute

BETWEEN

Shri Hardeo Ji Nagar S|o Shri Nauvind Ji Nagar, C|o Shri O. P. Nigam 293|377 Deen Dayal Marg, Asharfabad Lucknow.—Workman.

AND

The Regional Manager, Bank of India, 1, Naval Kishore Road, Lucknow.—Management.

AWARD

APPEARANCE :

Shri O. P. Nigam, representative—for the workman.

Shri Jagat Arora, representative—for the management.

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification no L-12012|194|80-D.II.A, dated 21st July, 1981, has referred the following dispute for adjudication;

> Whether the action of the management of Bank of India, Lucknow in dismissing from service Shri Hardev Ji Nagar, Special Asstt. Varanasi Branch with effect from 8-10-76 is justified ? If not, to what relief is the worker concerned entitled ?

2. The services of workman Hardeo Ji Nagar terminated on 8-10-76 for misconduct. The charges were framed against him and an enquiry held and it was on the basis of enquiry report that the disciplinary authority terminated his services. The workman contested the enquiry on the ground that the enquiry officer did not inform after 13-9-76 that the enquiry will be held day to day till finished and thus it was a hurried enquiry. Thus on the issue if the enquiry was fair proper or vitiated, the court held that it can not be said that the enquiry was proceeded in hurry and fair opportunity was not allowed to the workman to defend the case. Ultimately, it was held on the issue that the enquiry is not vitiated as alleged and the issue was decided against the workman. That the findings on the issue will form part of this Award.

3. It is common ground that no departmental appeal was filed by workman against the termination order. The counsel for the management has argued that without exhausting remedy provided no reference could be made. In support of his contention he has referred me the ruling;

Atlas Cycle Industries Versus Industrial Tribunal Punjab & Haryana High Court page 183 wherein it was observed;

> "for the reasons given above, therefore, we feel that there is force in the argument of the learned counsel for the management that before exhausting the remedies as provided the settlement, the workman could not approach the conciliation officer and the conciliation officer had no jurisdiction to go to into the matter before the procedure laid down in the settlement had been followed. For the same reason, the matter could not be referred to the Industrial Tribunal either, we consequently, uphold the objection of the management, accept and quashed the decision of the Industrial Tribunal.

The above ruling will not apply in the present case as that related to remedies given in the settlement itself. If a matter is covered by some settlement in which their mode is given in case of any dis-satisfied reasoning out of settlement then during currency of said settlement no reference can be made. It was not incumbent on the workman that after termination of the services to have filed departmental appeal and waited for the orders. He was fully justified in raising Industrial Dispute which the Government in its wisdom considered just and proper to refer the matter for adjudication and not turning the request of the workman on the ground that the remedy available by way of departmental appeal should be exhausted first.

4. The counsel for the management has further argued that in case the Tribunal is inclined to grant relief to the workman, compensation should be allowed and not reinstatement. The management has further referred me the ruling;

McKenzie & Company Vs. Its workman & others, SC Civil Appeal No. 500 of 1957 17th October, 1958, wherein it was held;

In cases of dismissal, or misconduct, the Tribunal does not however act as a Court of appeal and substituted its own judgment for that of the management. It will interfere;

(a) when there is want of good faith;

(b) when there is a victimization or unfair labour practice;

(c) when the management has been guilty of a basic error or violation of a principle of natural justice and;

(d) when on the materials the finding is completely baseless or perverse.

5. It has been argued by the counsel for the workman that the workman was dismissed on charge which is covered under minor misconduct under para 19.7 (a) of the first bipartite settlement for which the maximum punishment is stoppage of increment for maximum period of six months vide para 19.8 of the bipartite settlement. As such the only remedy is to reinstate the workman as Special Assistant with full back wages, continuity of service entitling him for all eventually for which he legitimately entitled. The counsel for the workman has drawn my attention to the ruling Hindustan Tin Workers (P) Ltd., Vs. The Employees Tin Works (P) Limited, 1978 II LLJ 474 (SC) wherein it was held;

> Ordinarily, therefore a workman whose services has been illegally terminated would be entitled to full back wages except to the extent he was gainfully employed during the enforced idleness. That is the normal rule. Any other would be a premium on the unwarranted litigative activity of the employer. And again, full back wages would be normal rule and the party objecting to it must establish circumstances necessiating departure.

6. In case of Shri N. B. Shukla V. Bank of Baroda 1979 I LLJ (HC) Bombay, wherein it was held :

It was contended that in the event of the impugned order being struck down, this was fit case where reinstatement should not be ordered as the bank had lost confidence on petitioner to date should be ordered to be paid to him. Held I do not agree to do so would defeat the very purpose of what all this about. If the bank acted with undue haste, which it did in dismissing the petitioner it can hardly be allowed in participate wrongful dismissal merely by buying out the petitioner instead of reinstatement for him as prayed for by this petition.

7. In the case of Shri Ved Prakash Gupta Vs Dalton Cable India (P) Limited wherein it was held;

Termination of service—validity of—no responsible employer would ever impose in like circumstances the punishment of dismissal to the employee and that victimisation or unfair labour practice could well be inferred from the conduct of the management in awarding the extreme punishment of dismissal for a flimsy charge of abuse of some worker or officer of the management by the appellant's service is invalid and unsustainable in law and that he is entitled to reinstatement with full back wages and other benefits including continuity of service.

That was a case of some positive act i.e. hurling abuses on co-worker or on officer where the court order that the extreme penalty of termination was victimisation, unfair labour practice.

8. In the instant case one of the charges was that the workman entered in the chamber of the agent, started shouting in the chamber at the top of his voice instigating other members of the staff and refused to leave the agent's chamber. The charge sheet is appendix 5 on the record filed alongwith the affidavit of the workman. The charges are regarding incident of 29-1-75 that he reached office 25 minutes late and when the accountant was recording time the workman objected in a disorderly manner and started shouting abusing as follows;
DEKHO YEH GUNDAGARDI KAR RAHA HAI ISE THEEK KARNA HOGA again incident of the same day at 3 p.m. in which the workman abused the same Accountant SALA HARAM KHAR HAI CHOR KAHI KA, and then the incident of 21st February, about shouting in agent's chamber and again a similar incident of shouting in the chamber and refusing to accept the office memorandum on 22-2-75 and lastly the incident of 3-3-75 and snatching away duplicate copy of the reply submitted by the workman and thereby destroying the banks record. The allegations are not such for which termination of service should have been granted. The very fact that the termination for this charges even if proved would be to much and go to the level of victimisation or unfair labour practice. Utmost the workman could have been transferred or his increment could have been withheld.

9. In these circumstances, the order of termination of service as punishment as victimisation and unfair labour practice. I am to substitute the same by ordering stoppage of his ONE increament which shall have effect on all future increment, as the charge can not be called to be a minor misconduct and the cases of disorderely behaviour abuse and snatching the document which is covered under gross misconduct as having indulge in disorderly behaviour in the premises of the bank or doing any act prejudicial act in the interest of the bank.

10. I, therefore, give my award holding that the action of the management Bank of India, Lucknow, in dismissing from service Shri Hardev Ji Nagar, Special Assistant Varanasi Branch w.e.f. 8-10-76 is not justified and that his punishment is substituted by stopping one increament from 8-10-76 which will have effect on all future increments subject to the punishment given and the result is that the workman will be entitled to all back wages and will be reinstated in the services of the bank management.

11. I, therefore, give my award accordingly.

Note : Order dated 10-5-85, passed by this Tribunal shall form part of this AWARD.

Let six copies of this award be sent to the Government for publication.
6-8-1985

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-12012/1994/80-D.II (A)]
K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer

BEFORE SHRI R. B. SHRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 99/81

BETWEEN

In the matter of dispute
Shri Hardeoji Nagar ...Workman

AND

The Management of Bank of India ...Management

ORDER on preliminary issue :

"WHETHER THE ENQUIRY IS VITIATED"

The case of the workman is that he was working in the management bank in its Varanasi Branch. He received a memo on charges dt. 22-2-75 alleging misconduct. Through another memo of the branch dated 28-2-75, as he has not received the earlier memo, he replied the same on 3rd March, 1975. The workman was again served with a show cause notice dated 6th March, 1975 by the Regional Manager of the bank at Lucknow by which he was asked to submit his explanation within 3 days why desciplinary action should not be taken against the workman. The workman submitted his explanation on 11th March, 1975, the two documents are annexure 3 and 4 to the workman's affidavit. The workman denied the allegations and asserted that the whole thing was being manipulated on the ground of his trade union activities and was aimed to harass.

The explanation of the workman was found unsatisfactory and the management decided to start departmental enquiry. The workman was served with a charge sheet on 12th July, 1975 on the same allegations as in the memo intimating that the enquiry will commence from 4th August, 1975 at the place and time mentioned in the charge sheet, to empower the enquiry officer whose name will be notified by the bank's notice board. The workman attended the enquiry proceedings on 16-9-75 and after 18-9-75 he fell ill and applied for 15 days leave. He remained ill thereafter and applied for leave on medical ground. In this way he submitted three applications for extension of his leave upto 28-11-75. All his leave applications were sanctioned by the branch manager. He was declared fit by the Medical Officer on 29-11-75 and went to join his duty when he was told that the exparte enquiry was held in his absence and he was awarded punishment of stoppage of 4 increments permanently and special allowance for the post of special assistant. He being shocked hearing the punishment given to him on the basis of exparte enquiry proceeded on leave and filed a writ in the Hon'ble High Court against the punishment. The punishment order of the enquiry officer is dated 29-10-75. The workman thereafter, learnt through the news paper that he was requirement to be present an enquiry to be held on 13-9-76 on some charges of gross misconduct. On that he represented through registered letter sent on 10-9-76 as he be allowed to be represented by some lawyer in the enquiry. He was waiting for the reply when he received information by telegram in the night between 12/13th September, 1976, that he was required to be present on 13th September, 1976. and similar letter was also received on 13th September, 1976. As the enquiry was to be held at Varanasi and he was at Allahabad. it was not possibe for him to attend the enquiy at Varanasi and he learnt in the news paper on 27-9-76 that the enquiry proceedings were being held exparte against him. The workmen presonally appeared before the enquiry officer on 29-9-76 and requested

for time and hearing. The enquiry officer did not listen to him and passed final orders on 1-10-76, dismissing the workman which was published in the news papers on 8-10-76. The above averments were contained in the affidavit filed by the workman on which he was cross examined by the management. In cross examination he admitted that his address CK-5/27 Bhikari Das Lane is correct. He was however, asserted that he was not at his address when letters and notices were taken there and it is wrong to say that he refused accepting the same. He has admitted that he did asked Shri J.C. Srivastava to bring register in enquiry on 18-9-75 and in the end he denied that he evaded enquiry despite knowledge.

The parties representative agreed that all the documents filed by the management be read as evidence without formal proof, consequently management did not examined any witness. It was on that account that the management did not examine any enquiry officer to prove the report which are on records.

The workman representative had contested the case broadly on the ground that the enquiry officer did not inform the workman after 18-9-76, that the enquiry will be held day to day till it finished. Thus it was a hurried enquiry.

It is further argued that in the first enquiry by way of powers special allowance can not be withdrawn as for minor mistake, his increments could be stopped for six months but special allowance could not be withdrawn by way of punishment. This is a point to be considered on the quantem of punishment when the entire case is argued and the award is given. For the present I have simply to see if the enquiry is fair and proper.

The counsel for the management has drawn my attention to para 13.5 and 13.6 of the bipartite settlement which lays down that no leave or extension of leave shall be deemed to have been granted unless an order to that effect passed and communicated to the employee concerned. Further it is laid down in para 13.6 that leave of all can not be claimed as rights. The workman himself has admitted that from 19-9-75 he did not attend the office and applied for medical leave and again that when he was declared fit on 29-11-75 went to join duties but being informed about the punishment proceeded on long leave. The management representative has argued that the second enquiry officer was from Bihar, hence after receipt of the telegram, the workman should have been attended the enquiry and as the management witness had arrived for the enquiry, there was nothing wrong if the enquiry officer proceeded with the enquiry and held exparte proceedings from day to day till 30-9-76 and awarding punishment of dismissal. Despite absence of the workman even after knowledge of the exparte proceedings, the enquiry officer sent a telegram and also a letter to this effect was sent to the workman to appear on 17-9-76 and cross examine the witnesses. The enquiry officer also issued a show cause notice on 22-9-76 proposing the punishment as to why he should not be dismissed and the same was also published in the news paper in daily Hindi AAJ on 23rd September, 76 but no reply was received to any of them. It was on that final orders were passed on 30-9-76.

All this go to show that the workman was not cooperative. All the notices regarding the enquiry were affixed on the notice board of the Bank on 26-9-76.

In support of the contention, the management representative has drawn my attention to the ruling Major U.R. Bhatt Versus Union of India, Factories Journal Reports, page 478 S.C. wherein it was observed.

> "An officer holding a departmental enquiry into alleged acts of misconduct of an employee is not bound by the strict rules of the law of evidence and when the employee declines to take part in the proceedings and fails to remain present, it will be open to the enquiry officer to proceed on the materials which were placed before him. It is not necessary in such a case that enquiry officer should examine all the witnesses for the employer, and, if the employee's ignorance of the statements of witnesses which had been tendered in evidence is the direct result of his own non co-operation with the proceedings, it can not be held that the enquiry was vitiated because the employee did not have access to such evidence or that he was not given a reasonable opportunity to show cause."

On the issue if the enquiry is vitiated, the Tribunal can not sit in appeal over the order. It has simply to see whether the enquiry was conducted in good faith and the principle of natural justice were observed and that the workman was not unnecessarily victimised on account of some unfair labour practice.

In G. Mac. Canjee Versus Its Workman 1959 1st LLJ page 285 wherein law laid down in 1958 I LLJ page 260 in the following words;

> "In case dismissal on misconduct, the Tribunal does not, however, act as court of appeal and substitute its own judgement for that of the management. It will interfere (i) where there is want of good faith, (ii) where there is victimisation or unfair labour practice (iii) where the management is guilty of basic error or violation of principle of natural justice and (iv) where on materials findings is completely baseless and perverse."

I have gone through the two enquiry reports and the documents filed by the parties. The findings can not be called to be perverse as they are based on what ever exparte evidence was available with the enquiry officer. The enquiry officer took utmost care to intimate the workman about the conduct of the proceedings and the same was completed only when the workman did not attend the enquiry despite being declared fit by the doctor after the workman fell ill on 18-9-76. Further they allowed time to the workman and when the workman did not attend the enquiry proceedings after having applied for medical leave even though he was found fit by the doctor, the enquiry was proceeded exparte when it was completed before he was declared fit by the private doctor on 29-11-75 and went to join his duties. At the time of second enquiry also the enquiry officer did his best to intimate the workman by telegram, Letters and ultimately by publication in the news papers but when the workman did not appear to contest and face the enquiry proceedings, there was nothing wrong if the management proceeded exparte and completed the enquiry exparte.

It can not be said that the enquiry was proceeded in hurry and fair opportunity was not allowed to the workman to defend the case.

In view of the circumstances and law dismissed above, I hold that the enquiry is not vitiated as alleged and the issue is decided against the workman accordingly.

Dated : 2-5-85

Sd/ R.B. SRIVASTAVA, Presiding Officer
C.G.I.T., Kanpur.

नई दिल्ली, 2 सितंबर, 1985

का. आ. 4310.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार नेशनल बैंक आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 20-8-85 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 2nd September, 1985

S.O. 4310.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 20th August, 1985.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 103/83

In the matter of Shri Jitendra Kumar Pathak, resident of D-34, New Agra, Agra.

AND

The Chief Manager, Central Bank of India, Divisional Office Belanganj, Agra.

APPEARANCES :

Shri Mangalwadekar representative—for the workmen.

Shri S. Trivedi representative—for the management.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour vide its Notification No. L-12012/233/81-D.II(A) dated 30th January 1982 has referred the following dispute for adjudication :

"Whether the action of the management of the Central Bank of India, Agra in terminating the services of Shri Jitendra Kumar Pathak, an ex-temporary clerk with effect from the close of business on 7-12-74, is an act of unfair labour practice ? In either case to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. The case of the workman Shri J. K. Pathak is that he entered in the management's service on 11-1-74 in temporary capacity as clerk and after more spells of duty was last posted at Agra. There he worked against a permanent vacancy and had put in not less than 239 days of service against permanent vacancies when on 9th December, 74 after close of business hours was orally told that his service will come to an end w.e.f. 7-12-74, no letter of termination was given to him, no notice of termination was given or no amount paid to him in lieu of notice. At times letters of appointment were issued but after expiry of the period of service mentioned therein the services allowed to continue without giving any extension letter and no letter of termination was ever issued nor any notice was given that after termination of the workman several new hands were appointed but he was never given any opportunity to work in place of such new appointment and thus provisions of section 25-H and 25-G of the I. D. Act were disputed Written test for clerk were taken in the year 1971 and 73 but the result of those test were never declared. Action of the management in terminating the services of the workman from 7-12-74 and appointing others was a unfair labour practice and thus the applicant has prayed to be reinstated with full back wages.

3. The management admits workman's having worked in the management banks for some time on purely temporary basis as clerk in leave gap arrangement. The management denied that the workman worked for 239 days in one continuous year. The management has admitted that after giving appointment letters some times orally extension were granted depending upon exigency of work. They assert that no notice is required in view of para 522 of Sastri Award. The management has further averted that temporary appointments were given to the workman from time to time never confirmed any entitlement on him for his employment in the bank on permanent basis. According to the management for claiming the post of clerk on permanent basis a candidate is required to qualify written test as well as interview. According to the management the workman did not qualify the written test held in 71 and 73. In the end it is reiterated that the workman could not complete 240 days of continuous service, hence no notice and retrenchment compensation was required for his termination.

4. In the rejoinder the workman has given details of the work as follows :

(a) Worked at Phawara Agra between 11-1-74 to 2-4-74 for about 76 days.

(b) worked at Civil Lines Branch Agra for 61 days from 8-5-74 to 7-7-74.

(c) worked at Cantt. Branch Agra between period 17-4-74 to 1-9-76 for 52 days and lastly ;

(d) worked at Toondla Branch between 17-10-74 to 7-12-74 for 52 days ;

thus the workman's total working days in the above period comes 241 days including Sundays.

In support of his contention the workman has filed annexures I, II, III and IV. It may be mentioned here that the certificates given by Civil Line Branch, Agra Annexure II speaks about working days about 60 days where as the workman has averred that he worked for 61 days there. Thus there is descripency of one day because the management does not certify that workmen worked on 7-7-74 also whereas the workman in his rejoinder's para 1'(a) has shown working days including 7-7-74. Similarly certificate issued by Cantt. Branch annexure III shows that the workman worked from 12th July 74 to 31st August, 74 there for 51 days and not on 1-9-74 as claimed by the workman. Annexure IV is certificate issued by Toondla Branch of the management for the period 17-10-74 to 7-12-74 and there the number of working days of the workman is 52 days thus according to the management the admitted number of working days in one span of year counting backward from 7-12-74 would came to 239 days.

4. The management has filed annexure M-1 showing that the workman's name did not appear in the list of successful candidates who appeared for written test in June 73.

5. On behalf of the management Shri P. K. De Chief Officer Personnel department filed his affidavit supporting the management's contention. He has proved the documents M-2 to M-5 filed by the management. In cross examination he has deposed that in temporary appointment no notice of termination is required. It may be mentioned here that in view of para 522 of Sastri Award which is in the nature of agreement and binding on the bank as standing Orders in view of para 561 of the same. Para 522 sub-clause IV lays down "that the services of any employee other than permanent employee of probationary (meaning thereby temporary) may be terminated or he may leave service after 14 days notice". This means that even in the case of termination of a temporary employee 14 days notice or notice pay should have been given. Management witness has admitted different spells of work from 11-1-74 to 7-12-74 the total number of working days come to 239 days and the same is in one year counting back were from 7-12-74 He has expressed ignorance if any other temporary workman was appointed after termination of the workman's service.

6. On the other hand workman Shri Jitendra Kumar Pathak has given affidavit that in one year in all he worked for 240 days which period includes 1st September 74, 6th July, 74 and 8th December 74, and these dates are not admitted to the management and for which no service certificate is given to the workman. The workman has averred that those dates 7-7-74, 1-9-74 8-12-74 were all Sundays and his services were orally terminated on monday and those Sundays were not counted which is an unfair labour practice. He has however, averred in his affidavit that he has been paid bonus for those Sundays. He has further stated that he worked against permanent post and yet his services were terminated when other vacancies were existing therein the management. He has further averred that after his termination as many as 12 persons mentioned in paragraph 6 of the affidavit were given temporary appointment on 8-1274 or soon thereafter i.e. after his termination. The workman specifically mentioned that one Shri Suneel Kumar Agrawal who was given appointment on 8-12-74 and worked upto 31-12-74. It is argued on his behalf that not allowing the workman after 6th or 7th December, 74, and appointing Shri Suneel Kumar Agrawal on 8-12-74 and allowing him to work till 31-12-74 is an unfair labour practice with a view that the workman may not complete his 240 days in this way. The workman has also given the name of five other persons in paragraph 8 of his affidavit mentioning that they all given permanent appointment even when they had not completed 240 days and has also not qualified written test.

7. In Kapporthala Central Cooperative Bank Limited Vs. Presiding Officer, Labour Courts, Punjab and Haryana High Court 1984 Lab. IC 976 wherein it is held :

> Termination of service of employees on verge of their completing 240 days service with notional brake—other persons employed in their place—work of former satisfactory—action of the management would be unfair labour practice.

I see no reason to disbelieve the affidavit of the workman given on 18-12-84 wherein he has deposed that Shri S. K. Agarwal was appointed on 8-12-74 just on the very day on 6th December, 74, as alleged when 7-12-74 was Sunday would be an unfair labour practice. If the averment was wrong the management could have filed affidavit later. When the question of confronting the management witness came on 18-12-84. the management witness stated that he had no knowledge that anyone was appointed or not. In the above said ruling in the end it was held :

> To conclude we hold that the practice of retrenching a workman close to this attaining a year's continuous service in order to frustrate his attaining rights under chapter VII Industrial Disputes Act, is an unfair labour practice, unless there are reasons with the employer with regard to the conduct and service of the workman being unsatisfactory. How close should be such period towards attaining a year's continuous service and to come within a purview of unfair labour practice is a question dependent on the facts and circumstances of each case.

8. Workman has admitted that on dates mentioned in his affidavit they being Sunday he had worked on Saturday and when he went to resume on Monday, he was told that his services were no more required. He stated that he went for duty on Monday also as on Saturday he was not told not to come for future for further duties. In this way the workman worked for 240 days and it is including Sundays but whereas according to the service certificate given by the management a number of workman's working days comes to 239 days. The management did not question the workman on the point of bonus when in the said paragraph he averred that bonus for those days paid to the workman. The workman could have completed 240 days had his services not been abruptly terminated on 8-12-74 when he went to bank and another man Shri S. K. Agarwal was appointed on the same day.

9. I accordingly held that this termination was illegal. Workman had actually counting three Sundays worked for more than 240 days in one span of year and was entitled to retrenchment compensation under section 25F besides notice pay and this having not been done ,the termination would be void ab initio and the workman will be entitled to be put back in service with full back wages.

10. The management also vioated provision of section of 25-G as several persons who were junior to him should have terminated first under principal of last come first go, the termination would be illegal on this count and the workman will be entitled to be reinstated in service with full back wages.

11. I am supported in my view by law laid down in workman of Sudder Workshop of Jorehaut Tea Company Limited Vs. The Management of Jaurhaut Tea Company, 1980 Lab. IC 742, S.C. 1454.

12. In Central Bank of India Versus State of Jammu and Kashmir and others wherein it was held :

> If the industrial court is satisfied that the order is punitive i.e. malafide or it amounts to victimisation or unfair labour practice it is competent to set aside the order and direct reinstatement.

13. Similarly in Kheda District Central Bank Vs. Bhargava Balwantrai Vyas 1984 II LLJ page 330 Gujarat High Court wherein it was held :

> There is clear breach of clause 22 of the standing order which provides for termination of the employment of a permanent employee or probationer by one month's wages in lieu of notice since this condition is precedent has not been satisfied the termination is void and ineffective and the respondent is deemed to be continued in service and entitled to order of reinstatement with full back wages.

14. In the instant case termination of a temporary employee could be only by way of 14 days notice under section 522(4) of Sastri Award. This having not been done the termination is void ab initio and the workman is entitled to be reinstated with full back wages.

15. Thus in any view of the matter the termination of the workman is illegal and is an act of unfair labour practice.

16. I, accordingly, give my award holding that the action of the management of the Central Bank of India Agra in terminating the service of Shri J. K. Pathak, temporary clerk with effect from close of business hours on 7-12-74 without giving him a termination notice is an act of unfair labour practice. The result is that the workman is entitled to be reinstated with full back wages.

17. I, therefore, give my award accordingly.

18. Let six copies of this award be sent to the Government for publication.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-12012/233/84-81-D.II (A)]

K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer.

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1985

शुद्धि पत्र

का०आ० 4311:—श्रम मंत्रालय की तारीख 23 जुलाई, 1985 की समसंख्यक अधिसूचना में, उक्त अधिसूचना की पांचवी पंक्ति में "जबलपुर" शब्द के लिए "संख्या 2, बम्बई" अंतःस्थापित किया जाए ।

[सं० एल-12012/110/83-डेस्क-II (ए)]

के. जे. दैव प्रसाद, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 2nd September, 1985

CORRIGENDUM

S.O. 4311.—In this Ministry's Notification of even number dated 23rd July, 1985, the word 'Jabalpur' may be substituted by 'No. 2, Bombay' in the fourth line of the said Notification.

[No. L-12012/110/83-D.II (A)]

K. J. DYVA PROSAD, Desk Officer

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1985

का०आ० 4312:—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 91क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1427 तारीख 16 अप्रैल, 1984 के क्रम में मैसर्स नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (तमिलनाडु और पांडिचेरी) लिमिटेड कोयम्बटूर, के जो भारत सरकार का एक उद्यम है, प्रधान कार्यालय के नियमित कर्मचारियों को, उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 अक्तूबर, 1984 से 30 सितंबर, 1985 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए छूट देती है।

2. उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् :—

(1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दर्शित किए जाएंगे ;

(2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते ;

(3) छुट-प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही संदत्त किए जा चुके हैं तो वे वापस नही किए जाएंगे ;

(4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ;

(5) केन्द्र द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी,—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अवधि को बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं ; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं को, जो ऐसी प्रसुविधाएं हैं, जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबन्ध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा,—

(क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे ; या

(ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग में के कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखे, बहियां और अन्य दस्तावेजें, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की उसके अभिकर्ता या सेवक को या ऐसे किसी व्यक्ति को जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है परीक्षा करना, या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेजों की नकल करना या उससे उद्धरण लेना।

[सं० एस. 38014/11/85 एस.एस. आई]

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस मामले में छूट का भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के लिए आवेदन देर से प्राप्त हुआ था। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

New Delhi, the 26th August, 1985

S.O. 4312.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) hereinafter referred to as the said Act, and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1427 dated the 16th April, 1984, the Central Government hereby exempts the regular employees of the Head Office of M/s. National Textile Corporation (Tamil Nadu and Pondicherry) Limited, Coimbatore, a Government of India enterprise, from the operation of the said Act for the period from 1st October, 1984 upto and inclusive of the 30th September, 1985.

The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;

(2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates ;

(3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded ;

(4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and required any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/11/85-SS. I]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the application for exemption was received late. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का. आ. 4313—मैसर्स मैसूर किर्लोस्कर लिमिटेड, डाकघर—गंगापुर, हरिहर—577602 (कर्नाटक/33) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3392 तारीख 2-9-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 25-9-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 24-9-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देह रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस.-35014/119/82पी. एफ. II एस. एस.-4]

S.O. 4313.—Whereas Messrs Mysore Kirloskar Limited, P.O. Yantrapur, Harihar-577602 (KN|33) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. 3392 dated the 2-9-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 25-9-1985 upto and inclusive of the 24-9-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintainance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme of the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/119/82-PF.II(SS.IV)]

का. आ. 4314.—मैसर्स गोयटजे (इण्डिया) लिमिटेड, भलाहन्का' बंगलौर—560064 (कर्नाटक/6722) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3552 तारीख 23-9-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 9 अक्तूबर, 1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 8 अक्तूबर, 1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में

नियोजित किया जाता है तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिति को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस.-35014/31/82-पी. एफ.—II (एस. एस.-4]

S.O. 4314.—Whereas Messrs Goetze (India) Limited, Yelahanka, Bangalore-64 (KN|6722) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. 3552 dated the 23-9-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 9-10-1985 upto and inclusive of the 8-10-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintainance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014|31|82PF.II(SS.IV)]

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1985

का. आ. 4315 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कुडस एग्रो केमिकल्स, मिनी इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पामपैडी, कोट्टायम और इसका मुख्यालय कार्यालय—एम. डी. सी. सैन्टर कोट्टायम— 686001 केरल नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा- (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस.—35019(320)/85—एस. एस.-2]

New Delh, the 29th August, 1985

S.O. 4315.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relaton to the establishment known as Messrs. Coods Agro Chemicals, Mini Industrial Estate, Pampady, Kottayam including its Head office at MDC Centre, Kottayam-686001. Kerala have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(320)|85-SS.II]

का. आ. 4316 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सुवेना डीजलस, क्लब रोड, हुबली—20 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस.-35019 (318)/85-एस. एस.-2]

S.O. 4316.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Suvern Diesels, Club Road, Hubli-20 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(318)|85-SS-II]

का. आ. 4317 —केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 243, तारीख 8 जनवरी, 1982 के क्रम में, मैसर्स हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड पूजापुरा, त्रिवेन्द्रम के, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, प्रधान कार्यालय के नियमित कर्मचारियों को, उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 अक्तूबर, 1982 से 30 सितम्बर, 1985 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है अवधि के लिए छूट देती है।

उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्:—

(1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दर्शित किए जाएंगे;

(2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते;

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही संदत्त किए जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए जाएंगे ;

(4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात्

उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी —:

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए, या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं को, जो ऐसी प्रसुविधाएं है जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं, या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :—

(क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग में के कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसी लेखाबहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना।

[संख्या एस.-38014/4/85-एस.-एस.-I]

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के लिए आवेदन बहुत देर से प्राप्त हुआ था। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

S.O. 4317.—In exercise of the powers conferred by Section 88, read with Section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 243 dated the January, 1982, the Central Government hereby exempts the regular employees of the head office of M/s. Hindustan Latex Ltd., Poojappura, Trivandrum, a Government of India Undertaking from the operation of the said Act for the period from 1st October, 1982 upto and inclusive of 30th September, 1985.

The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;

(2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;

(3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;

(4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of —

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory be empowered to -

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/4/85-SS.I]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemptions in this case as the application for exemption was received very late. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1985

का.आ. 4318.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय औजार कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्र, बनहुगली औद्योगिक क्षेत्र, कलकत्ता के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 जनवरी, 1979 से 30 सितम्बर, 1985 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए छूट देती है ।

उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् --

(1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दर्शित किए जाएंगे;

(2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त, अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते;

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही संदत्त किए जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए जाएंगे,

(4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उस उक्त अवधि की बाबत देनी थी;

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 का उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी,—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए, या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं को, जो ऐसी प्रसुविधाएं हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा,—

(क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग में के कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा

करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसी लेखाबहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत कर और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक को, उसके अभिकर्ता या सेवक को या ऐसे किसी व्यक्ति को जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उनसे अवतरण लेना ।

[संख्या एस-38014/5/84-एच. आई. (एसएस-I]

स्पष्टीकारक ज्ञापन

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है, क्योंकि छूट के लिए आवेदन देर से प्राप्त हुआ था। किन्तु, यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

New Delhi, the 29th August, 1985

S.O. 4318.—In exercise of the powers conferred by section 88, read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts the regular employees of Central Tool Room and Training Centre, Bonhooghly Industrial Area, Calcutta from the operation of the said Act for the period with effect from 1st January, 1979 upto and inclusive of the 30th September, 1985.

The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;

(2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;

(3) The contributions for the exemption period, if already paid, shall not be refunded;

(4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of —

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/5/84-HI(SS-I)]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemptions in this case, as the application for exemption was received very late. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का. आ. 4319.—मैसर्स एण्डियन एक्सप्रैस न्यूजपेपर (बम्बई), प्रा. लिमिटेड, एक्सप्रैस बिल्डिंग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 (दिल्ली/114) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में

फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिस इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं को रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या ए स-35014/193/85 एस एस-IV]

S.O. 4319.—Whereas Messrs Indian Express Newspapers (Bombay) Private Limited, Express Building, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110002 (DL|114) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(193)/85-SS.IV]

का. आ. 4320.—मैसर्स शिखर ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, 209 कम्पीटेण्ट हाउस, एफ 14, मिडिल सर्कल, कनाट सर्कस, नई दिल्ली 1 (दिल्ली/7162) (जिसे उसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम का सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की

बहुसंख्यक की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरंत दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस.-35014/194/85-एस. एस.-4]

S.O. 4320.—Whereas Messrs Shikhar Travels Private Limited, 209, Competent House, F-14, Middle Circle, Connaught Circus New Delhi-110001 (DL/7162) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as apprved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would

be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/194/85-SS.IV]

का. आ. 4321.—मैसर्स एक्सपे मशीनरी लिमिटेड, छटी मंजिल, प्रगति टावर, 26-राजिन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 (दिल्ली/5864) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे विनियोग प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बोधा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वार्षिक आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/195/85-एस.एस-4]

S.O. 4321.—Whereas Messrs Expo Machinery Limited, 6th Floor, Pragati Tower, 26 Rajindera Place, New Delhi-110008 (DJ.|5864) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Schem the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(195)|85-SS IV]

का.आ. 4322.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जयाराम थियेटर, कामराज सलाए, पॉडिचेरी नामक स्थापन के संबंद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019(315)/85-एस.एस-2]

S.O. 4322.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Jayaram Theatre 3 Kamaraj Salai, Pondicherry have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(315)/85-SS. II]

का.आ. 4323 :– केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इनफोसिस कंसलटेंटस (प्रा.) लिमिटेड न. 554, 10–ए मैन रोड 36 क्रास, पांचवी ब्लाक, जयानगर, बंगलौर–41 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा–1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं० एस–35019(317)/85–एस०एस०-2]

S.O. 4323.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Infosys Consultants (P) Limited, No. 554, 10-A Main Road, 36th Cross Vth Block Jayanagar, Bangalore-41, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(317)/85-SS. II]

का.आ. 4324:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कल्याण नर्सिंग होम नं. 6, फर्स्ट मैन रोड, कस्तूरबा नगर, अदयार, मद्रास–600020 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा–1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस–35019(314)/85–एस. एस.–2]

S.O. 4324.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Kalyan Nursing Home No. 6, First Main Road, Kasturba Nagar Adyar, Madras-600020, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(314)/85-SS. II]

725 GI/85—15

का.आ. 4325 :—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रिसिन एण्ड सोलवन्टस नं. 49, बैनरघाटा रोड, बगलौर–560030 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा–1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस–35019(312)/85–एस. एस.–2]

S.O. 4325.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Resins and Solvents, No. 49, Bannerghatta Road, Bangalore-560030 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(312)/85-SS. II]

का.आ. 4326 :—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अलवे चिट्टीज एण्ड फाईनैन्स (प्रा.) लि. प्रसाद बिल्डिंग्स, ब्रिज रोड, अलवे–1 केरल नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा–1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस–35019(327)/85–एस. एस.–2]

S.O. 4326.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Alwaye, Chitties and Finances (P) Ltd., Prasad Buildings Bridge Road, Alwaye-1, Kerala, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(327)/85-SS. II]

का.श्रा. 4327 :—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स खोसला इन्देर लिमिटेड, पोथी रेड्डी, पेली गांव मेढ़क कस्बा आन्ध्र प्रदेश नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(326)/85-एस. एस.-2]

S.O. 4327.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Khosla Indair Limited Pothireddy Pelli Village Medak District, Andhra Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(326)/85-SS. II]

का.श्रा. 4328 :—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रायठारा सेवा सहकारा संघ नियमिता काम्पली, हॉसपेट तहसील, बैलरी कस्बा और इसकी कं. कोट्टाला और रामागर में स्थित शाखाएं नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(325)/85-एस. एस.-2]

S.O. 4328.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Raithara Seva Sahakara Sangha Niyamitha Kapli, Hospet Aaluk, Bellary Dist. Including its Branches at K. Kettala and Ramagara, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(325)/85-SS. II]

का.श्रा. 4329 :—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दी इण्डियन रेअर अर्थस इम्प्लायस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नं. क्वाटर 425, चावरा पो. आ. कूलन कस्बा, पिन-691583 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(313)/85-एस. एस.-2]

S.O. 4329.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. The Indian Rare Earths Employees' Co-operative Society Ltd., No. Q. 425 Chavara P. O. Quilon Dist. Pin-691583, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(313)/85-SS. II]

का.श्रा. 4330 :—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स विनसम प्लास्टिक, सरोजा बिल्डिंग्स, थोडुपुझा इन्दुकी कस्बा केरल नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(310)/85-एस. एस.-2]

S.O. 4330.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Winsom Plastics, Saroja Buildings, Thodupuzha Idukki Dist. Kerala have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(310)/85-SS. II]

का.आ. 4331:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स माइक्रोसैन्स कम्प्यूटर्स लिमिटेड, दूसरी मंजिल इमराल्ड हाउस, एस. डी. रोड सिकन्दराबाद–500003, और इसकी दिल्ली, बम्बई और बंगलौर में स्थित शाखाएं और हैदराबाद स्थित फैक्ट्री नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा–1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस–35019(316)/85–एस. एस.–2]

S.O. 4331.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Microsense Computers Limited 2nd Floor, Emarald House, SD Road, Secunderabad-500003 including its branches at Delhi, Bombay, Bangalore and Factory in Hyderabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(316)/85-SS. II]

का.आ. 4332:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मसर्स विराजपट ताल्लुक एग्रीकल्चरल, प्रोड्यूज को–ओपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड विराजपट नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा–1 की उपधारा–(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[स. एस–35019(319)/85–एस. एस.–2]

S.O. 4332.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Virajpet Taluk Agricultural Produce Co-operative Marketing Society Limited Virajpet have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(319)/85-SS. II]

का.आ. 4333:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कामाख्या जनरल फाइनेंस एण्ड इनवैस्टमैंट कं. लिमिटेड रेहाबारी गौहाटी–781008, और इस की शाखाएं (1) एल. एन. बी. रोड, मंगलदोई (2) बारपेटा रोड (हिलाशी सिनेमा के निकट) (3) डिबरूगढ़ (4) नबाद्वीप प. बंगाल (5) दीमपुर (गौहाटी) (6) कालिया गांव (आसाम) (7) इसलामपुर (प. बंगाल) नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा–1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[स. एस–35019(324)/85–एस. एस.–2]

S.O. 4333.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Kamakhya General Finance and Investment Co. Ltd., Rehabari, Gauhati-781008, including its branches at (1) LNB road, Mangaldoi (2) Barpeta road (near Hilashi Cinema) (3) Dibrugarh (4) Nabadwip (W.B.) (5) Dispur (Gauhati) (6) Kaliagaon (Assam) (7) Islampur (W.B.) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(324)/85-SS. II]

का.आ. 4334:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गुरुकृपा एन्टरप्राइजेज, 6–ए, आई. डी. ए., फेज–1, पटानचेरू, मेडक कस्बा–502319 और इसकी विद्यानगर हैदराबाद–500044 में स्थित शाखाएं नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा–1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[स. एस–35019(309)/85–एस. एस.–2]

S.O. 4334. Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Gurukrupa Enterprises, 6A-I.D.A. Phase I, Patanacheru, Medak Dist. 502319 including its Branch at Vidyanagar, Hyderabad-500044, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-3519(309)/85-SS. II]

का.आ. 4335:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स शिमोगा रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लिमिटेड पो. बाक्स नं. 29, शिमोगा–577201, कर्नाटक नामक स्थापन के संबद्ध और नियोजक कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा–1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस–35019(308)/85–एस. एस–2]

S.O. 4335.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Shimoga Roller Flour Mills Private Ltd., Post Box No. 29, Shimoga-577201, Karnataka, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. 35019(308)/85 SS. II]

का.आ. 4336:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इलक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन आफ तमिलनाडु, एल. एल. ए. बिल्डिंग, 735 अन्नासलाए, मद्रास और इसकी (1) तिरुवानमीयूर, मद्रास–41(2) ए एफ सी प्रोजेक्ट प्लाट नं. 16 सिपसाट इंडस्ट्रीयल काम्पलैक्स होशूर-635126 में स्थित शाखाएं नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस–35019(323)/85–एस. एस.–2]

S.O. 4336.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Electronic Corporation of Tamil Nadu Limited, LLA Building, 735 Anna Salai Madras including its branches at (1) Tiruvanmivur Madras 41(2) AEC Project at Plot No. 16, SIPCOT Industrial Complex Hosur-635126, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(323)/85-SS. II]

का.आ. 4337:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स लिबर्टी केरियर्स, नं. 3, केलिस रोड केलिस, मद्रास–10 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा–1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस–35019(322)/85–एस. एस.–2]

S.O. 4337.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Liberty Carriers, No. 3, Kellys Road, Kellys, Madras-10, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(322)/85-SS. II]

का.आ. 4338:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एम. एस. एम. एण्ड कम्पनी, (पेन्ट्स) 29-ए, मिल रोड कोम्बेतूर–1 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा–1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस–35019(321)/85—एस. एस.–2]

S.O. 4338.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. M.S.M. and Company (Paints) 29-A, Mill Road, Coimbatore-641001, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(321)/85-SS. II]

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1985

का. आ. 4339.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि इंडियन ऑयल ब्लैंडिंग लिमिटेड, पी-68, सी. सी. आर. डाइवर्जन रोड, पहाड़पुर, कलकत्ता और दि इंडियन आयल ब्लैंडिंग लिमिटेड, पिर. पाउ, ट्रांम्बे, मुम्बई-74 के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 जुलाई, 1984 से 30 सितम्बर, 1985 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिए छूट देती है।

उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् :—

(1) पूर्वोक्त कारखना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दर्शित किए जाएंगे;

(2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते,

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही संदत्त किए जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए जाएंगे;

(4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी,

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी,—

(1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए, या

(2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथाअपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या

(3) यह विनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं को, जो ऐसी प्रसुविधाएं हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु-रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या

(4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :—

(क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग में के कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसी लेखाबहियों और अन्य दस्तावेजें, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना, या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उसमें उद्धरण लेना।

[सं० एम-38014/9/84-एच. आई. (एसएस-1)]

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के आवेदन संबंधी प्रक्रिया में समय लग गया था। किंतु, यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

New Delhi, the 31 August, 1985

S.O. 4339.—In exercise of the powers conferedy by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts the regular employees of the Indian Oil Blending Limited P-68, C.C.R. Diversion Road, Paharpur, Calcutta and the Indian Oil Blending Limited Pir Pau, Trombay

Bombay-74, from the operation of the said Act for a further period with effect from 1st day of July, 1984 upto and inclusive of the 30th day of September, 1985.

The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names all designations of the exempted employees;

(2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates ;

(3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded ;

(4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/9/85-SS I]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

S.O. 4340,—Whereas it appears to the Central Govern-exemption in this case as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1985

का. आ. 4340:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित छिन्दवाड़ा (म. प्र.) और इसकी शाखाएं (1) खिरसादोह परासिया (2) लाल बाग (3) शकल धारा (4) गुलबाड़ा (5) और तहसील पैलेस नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(344)/85-एस. एस. 2]

New Delhi, the 2nd September, 1985

S.O. 4340.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs District Whole Sale Consumer's Co-operative Store Ltd., Chhindwara Including its Branches at (1) Khirsadah Parasia (2) Lal-Bag (3) Sekludhana (4) Gulbra (5) Tahsil Place have agreed that the provisions of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the establishment.

[No. S-35019 (344)|85-SS-II]

शुद्धि-पत्र

का. आ. 4341:—भारत सरकार के तत्कालीन श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, (श्रम विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 3599, तारीख 23 अक्तूबर, 1984 जो कि तारीख 10 नवम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, की लाइन 2 में "(ए. पी./6630)" के स्थान पर "(ए. पी./6330)" पढ़ें।

[संख्या एस-35014/104/84-एस. एस. 4]

CORRIGENDUM

S.O. 4341.—In the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) No. S.O. 3599 dated 23rd October, 1984 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 10th November, 1984, in line 2 for "(AP|6630)" read "(AP|6330)"

[No. S-35014(104)84-SS-IV]

का. आ. 4342.—मैसर्स एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड मानचेरियल सीमेंट वर्क्स, जिला आदिलाबाद (आन्ध्र प्रदेश) (ए. पी./239), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है), ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3934, तारीख 6-11-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को 26-11-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 26-11-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश से पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/338/82-पी.एफ 2 एस.एस.4]

S.O. 4342.—Whereas Messrs Associated Cement Companies Limited, Mancheriar Cement Works, District Adilabad, Andhra Pradesh (AP/239) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3934 dated the 6-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 27-11-1985 upto and inclusive of the 26-11-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made y the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/388/82-P.F.-II-SS.IV]

का. आ. 4343.—मैसर्स एस्कोर्ट्स इम्पलाइज एन्सीलरीज लिमिटेड, 20/4, मथुरा रोड, फरीदाबाद, (हरियाणा/4628), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है), ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 39, तारीख 9-12-1982 के अनुक्रमण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को 1-1-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 31-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य

निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त हरियाणा के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/302/82/पी एफ 2-एस.एस.-4]

S.O. 4343.—Whereas Messrs Escorts Employees Anciliaries Limited, 20/4 Mathura Road, Faridabad (PN/4628) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 39 dated the 9-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 1-1-1986 upto and inclusive of the 31-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employeees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|302|82-PFII SS.IV]

का. आ. 4344.—मसर्स स्नोटेम्प इंजीनियरिंग कम्पनी लि. 14, माईलस्टोन, दिल्ली मथुरा रोड, फरीदाबाद (हरियाणा) पंजाब/24-14), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है), ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/196/85-एस. एस -4]

S.O. 4344.—Whereas Messrs Snowtemp Engineering Company Limited, 14 Milestone, Delhi Mathura Road, Faridabad (Haryana) (PN/2414) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the condition specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said estabblishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(196)|85-SS.IV]

का.आ. 4345 :—मैसर्स वैडनैक मशीनरी कम्पनी प्राइवेट लि. 244-गोदासुर, डाकघर बाक्स नं. 9007, मनीनगर, अहमदाबाद (गुजरात/6087), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात की पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय सत्वरता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस. 35014/197/85-एस. एस. 4]

S.O. 4345.—Whereas Messrs Cadmach Machinery Company Private imited, 244 Godasar, P.O. Box No. 907, Maninagar Ahmedabad (GJ/6087) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme by less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/1921/85-SS-IV]

का. आ. 4346 :—मैसर्स को-आपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, एलुरु, वेस्ट गोदावरी, जिला (आन्ध्र प्रदेश/2350) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है), ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3542, तारीख 23-9-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन 9-10-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 8-10-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश, के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों की जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस.-35014/117/82-पी. एफ. 2 (एस.एस 4)]

S.O. 4346.—Whereas Messrs The Co-operative Central Bank Limited, Eluru, West Godavari District, (AP|2350) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3542 dated 23-9-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 9th October, 1985 upto and inclusive of the 8th October, 1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of defult, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|117|82-P.F.II(SS-IV)]

का. आ. 4347 :—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स फैन्सी साड़ी निकेतन, गली परांठे वाली, चांदनी चौक, दिल्ली-6 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 10) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019(339)/85-एस. एस.-2]

S.O. 4347.—Whereas it appears to the Central Govt. that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Fancy Saree Niketan, Gali Prathewali, Chandni Chowk have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (10 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(339)|85-SS-II]

का. आ. 4348 :—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जैकम इलैक्ट्रोनिक्स सिस्टम्स, 1-1-36, मुशीराबाद, हैदराबाद-500020 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 10) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

[सं. एस-35019(332)/85-एस. एस.-2]

S.O. 4348.—Whereas it appears to the Central Govt. that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Jaks Electronics Systems, 1-1-36, Musheerabad, Hyderabad-500020 have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (10 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment,

[No. S-35019(332)/85-SS-II]

का. आ. 4349:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अशोक बिजनेस सर्विसेस, डोर नं. 6-3 609/16/1, आनंद नगर, हैदराबाद नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 10) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(331)/85-एस. एस.-2]

S.O. 4349.—Whereas it appears to the Central Govt. that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ashok Business Services, Door No. 6-3-609/16/1, Anand Nagar Hyderabad have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (10 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(331)/85-SS-II]

का. आ. 4350:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नवभारत एनवीरोटैक प्रा. लिमिटेड, मोहन मैन्शन, नं. 2-3, तिरू-वी-का रोड, मद्रास-600006 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 10) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(333)/85-एस. एस.-2]

S.O. 4350.—Whereas it appears to the Central Govt. that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Navabharat Envirotech Private Ltd., Monan Mansion. No. 2-3, Thiru-Vi-Ka Road, Madras-600006 have agreed that the Provisions of the employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (10 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment,

[No. S-35019(333)/85-SS-II]

का. आ. 4351:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स फार्मा सिंडीकेट, 1177 इनोक, चेम्बर्स, चिन्नाकादा, केलन-691001, केरल नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 10) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(338)/85-एस.एस.-2]

S.O. 4351.—Whereas it appears to the Central Govt. that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Pharma Syndicate, 1177 Enoch, Chambers, Chinnakkada, Quilon-691001, Kerala, have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (10 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(338)/85-SS-II]

का. आ. 4352:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मडोन्ना फ्रोजन फूड्स, मुक्का श्रीनिवासनगर दक्षिण कन्नड़, 574157 कर्नाटक नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 10) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(337)/85-एस. एस.-2]

S.O. 4352.—Whereas it appears to the Central Govt. that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Madonna Frozen Foods, Mukka Srinivasanagar Dakshina Kannada 574157 Karnataka have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (10 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(337)/85-SS II]

का. आ. 4353 : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इन्सपैक्सन एण्ड क्वालिटी सर्विसिज 2680, बिडन पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-5 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 10) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(340)/85-एस. एस.-2]

S.O. 4353.—Whereas it appears to the Central Govt. that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Inspection and Quality Services 2680, Beadon Pura, Karol Bagh, New Delhi-5, have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (10 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(340)/85-SS-II]

का. आ. 4354 : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स द तमिलनाडु इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड कंडक्टर्स, मारथानडाम इण्डस्ट्रियल इस्टेट, काप्पूकाडु, कन्याकुमारी कस्बा नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कमचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 10) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(329)/85-एस. एस.-2]

S.O. 4354.—Whereas it appears to the Central Govt. that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Tamil Nadu Electronics and Conductors Marthandom Industrial Estate, Kappukadu, Kanyakumari Distt. have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (10 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(329)/85-SS-II]

का. आ. 4355—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स यूनाईटेड हैण्डलूम्स, 8/1, एम. के. लेन, महल, तीसरी गली, मदुराई-625001 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 10) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(343)/85-एस. एस.-2]

S.O. 4355.—Whereas it appears to the Central Govt. that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs United Handlooms, 8|1, M. K. Lane, Mahal 3rd Street, Madurai-625001, have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (10 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(343)/85-SS-II]

का. आ. 4356—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत है कि मैसर्स शन्तनु स्वीट्स लि., 1430, गली संधियान चांदनी चौक, दिल्ली-6 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 10) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(342)/85-एस. एस.-2]

S.O. 4356.—Whereas it appears to the Central Govt. that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shantanu Sweets Ltd., 1430, Gali Sanghian, Chandni Chowk, Delhi 6 have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (10 of 1952), shhuld be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(342)/85-SS-II]

का. आ. 4357—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सुधा होम्यो फोर्मासिटीकल्स प्रशासकीय कार्यालय, 10-12, रामानाथापुर, हैदराबाद-500013 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 10) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस.-35019(341)/85-एस.एस.-2]

S.O. 4357.—Whereas it appears to the Central Govt. that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sudha Homoeo Pharmaceuticals, Administrative Office, 10-92 Ramanthapur, Hyderabad-500013, have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (10 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(341)/85-SS-II]

का. आ. 4358.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इन्टरनेशनल ट्रेडिंग कम्पनी, फाइनैन्सिंग यूनिट, मालीगेथोप, अंबूर-635802, नार्थ आरकाट, कस्बा तमिलनाडु नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

..... [सं. एस-35019(335)/85-एस. एस.-2]

S.O. 4358.—Whereas it appears to the Central Govt. that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs International Trading Company, Finishing Unit, Maligaithope, Ambur, 635802, North Arcot Distt., Tamil Nadu, have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (10 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(335)/85-SS-II]

का. आ. 4359:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सुन्दरम् प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज-6 (एस. पी.) डैवलप्ड प्लाट फैक्टरी, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, मद्रास-32 और इसका नं.-42, एंडरसन एंस्टी., मद्रास स्थित कार्यालय नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस.-35019(334)/85-एस. एस.-2]

S.O. 4359.—Whereas it appears to the Central Govt. that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sundram Plastic Industries, 6(SP) Developed Plot Factory-Industrial Estate Madras-32 including its office at No. 42, Anderson Street Madras-1, have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (10 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(334)/85-SS-II]

का. आ. 4360:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एम. एस. मणीकम एण्ड कम्पनी, 29 मिल रोड, कोम्बेतूर-641001 तमिलनाडु नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(347)/85-एस. एस. 2]

S.O. 4360.—Whereas it appears to the Central Govt. that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs M. S. Manickam and Co., 29, Mill Road, Coimbatore-641001, Tamil Nadu have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (10 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(347)/85-SS-II]

का. आ. 4361:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स देवी विकली 727, अन्ना रोड, थाऊजेंड एट्स, मद्रास-600006 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(349)/85-एस. एस.-2]

S.O. 4361.—Whereas it appears to the Central Govt. that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Devi Weekly, 727, Ana Road, Thousand Eights, Madras-600006, have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (10 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(349)/85-SS-II]

का. आ. 4362 :—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कालाहांडी अंचालिक ग्राम्या बैंक स्थित/पो. आ. भवानी पटना, कस्बा कालहांडी उड़ीसा और इसकी कालहांडी कस्बा पर स्थित पैंतीस शाखाएं नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा–1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस–35019(350)/85–एस. एस.-2]

S.O. 4362.—Whereas it appears to the Central Govt. that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kalahandi Anchalik Gramya Bank, At|Post Office Bhawanipatna, District Kalahandi, Orissa including its 35 Branches in Kalahandi district., have agreed that the Provisions of the Employes' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (10 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019|350|85-SS-II]

का०आ० 4363.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स क्लीन फूड्स कारपोरेशन लि. नं. 5, रेजीडेंसी रोड, विमला बिल्डिंग, बंगलौर-560025, और इसकी बंगलौर-76 में स्थित फ़ैक्टरी और प्रोजेक्ट कार्यालय मदनापल्ली (आंध्र। प्रदेश) नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(351)/85-एस एस-2]

S.O. 4363.—Whereas it appears to the Central Govt. that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Clean Foods Corporation Limited., No. 5, Residency Road, Vimala Building, Bangalore-560025 including its Factory at Bangalore-76 and Project office at Madanpalle (AP), have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (10 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019|351|85-SS-II]

का०आ० 4264.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स स्पेशल इलक्ट्रोड्स, 3/86-ई, अम्बात्तूर इंडस्ट्रियल इस्टेट, मद्रास-600058 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(352)/85-एस.एस-2]

S.O. 4364.—Whereas it appears to the Central Govt. that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Special Electrodes, 3/86-E, Ambattur Industrial Estate, Madras-600058, have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (10 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019|352|85-SS-II]

का. आ. 4365.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स विद्युत अग्निफ़र्निशस (प्रा.) लिमि. ब्लाक ए-8, (पुराना नं. 3197) 2 एवेन्यू रोड, अन्ना नगर, मद्रास-600102 और इसका बम्बई में स्थित रजि. कार्यालय तथा स्थानीय कार्यालय विलवाकाम, मद्रास-49 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(353)/85-एस एस.-2)

S.O. 4365.—Whereas it appears to the Central Govt. that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Vidyut-Agni Furnances (P) Ltd., Block A8, (old No. 3197) 2nd Avenue Road, Anna Nagar, Madras -600102 including its Regd. office at Bombay and Adm. office at Villvakkam, Madras-49, have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (10 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019|353|85-SS-II]

का. आ. 4366.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स भूपति एसोसिएटिड 7-सी (एस पी) इंडस्ट्रियल इस्टेट गुंडी, मद्रास-32 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(354)/85-एस. एस-2]

S.O. 4366.—Whereas it appears to the Central Govt. that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Boopathy Associated 7-C (SP) Industrial Estate, Guindy, Madras-32, have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (10 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(354)|84-PF-II]

का. आ. 4367.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जेमिनी आर्टस (प्रा.) लिमि, 601, माउंट रोड मद्रास-600006 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(335)/85-एस.एस-2]

S.O. 4367.—Whereas it appears to the Central Govt. that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Gemini Arts (P) Ltd., 601, Mount Road, Madras-600006, have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (10 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(335)/85-SS-II]

का. आ. 4368—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स टिटनियम टांटालम प्रोडक्ट (प्रा.) लि. वेगाएवसाल मेन रोड, गौरीवाकाम (पो. आ.) 601302 मद्रास और इसकी 161, वेलाचेरी रोड, ईस्ट टाम्बस्टाम मद्रास-59 स्थित शाखा नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(336) 85-एस. एस-2]

S.O. 4368.—Whereas it appears to the Central Govt. that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Titanium Tantalum Products (P) Ltd., Vengai-Vasal Main Road, Gowriwakkam (PO) 601302 Madras including its Branch at 161 Velachery Road, East Tambaram, Madras-59, have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (10 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(336)|85-SS-II]

का. आ. 4369.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डिस्ट्रिक्ट होल सेल कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स लि. कलक्टोरेट रोड, सतना, और इसकी शाखाएं (1) नागोड, (2) मोहर (3) कोठी और (4) चित्रकूट नामक स्थापन के संबंद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(345) 85-एस एस.2]

S.O. 4369.—Whereas it appears to the Central Govt. that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Distt. Wholesale Consumers Coop-stores Ltd., Collectorate Road, Satna including its branches at (1) Nagod (2) Maihar (3) Kothi and (4) Chitrkoot, have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (10 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(345)|85-SS-II]

का. आ. 4370—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सुपर आटो इलेक्ट्रोसिकल, प्लाट नं. 9-जे सैक्टर-6 फरीदाबाद नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[स. एस-35019(348)/85-एस. एस-2)

ए. के. भट्टाराई, अवर सचिव

S.O. 4370.—Whereas it appears to the Central Govt. that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Super Auto Electricals, Plot No. 9-J, Sector-6, Faridabad, have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (10 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the Provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(348)/85-SS-II]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1985

का. आ. 4271.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ़) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या का. आ. 1146 दिनांक 28 फरवरी, 1985 द्वारा भारत सरकार टकसाल कलकत्ता को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 28 फरवरी, 1985 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था।

और केन्द्रीय सरकार की राय है की लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ़) के उपखंड (vi) परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 28 अगस्त, 1985 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/6/85-डी-1(ए)[

श०ह०सु०अय्यर, अवर सचिव

New Delhi, the 28th August, 1985

S.O. 4371.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 1146 dated the 28th February, 1985 the India Government Mint, Calcutta to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months, from the 28th February, 1985.

And whereas, the Central Government is of opinion the public interest requires the extension of the said period by a further period of six months ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 28th August, 1985.

[No. S-11017/6/85-D.I (A)]

S. H. S. IYER, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1985

का. आ. 4372.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारत कोकिंग कोल लि. की जमुनिया ओपन-कास्ट परियोजना के प्रबंधतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं० 2 धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-8-1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 28th August, 1985

S.O. 4372.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jamunia Open Cast Project of M/s. Bharat Coking Coal Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 20th August, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD.

PRESENT:

Shri I. N. Sinha, Presiding Officer.

In the matter of Industrial Disputes under Section 10 (1) (d) of the I.D. Act., 1947.

PARTIES:

Employers in relation to the management of Jamunia Oppen Cast Project of Messrs. Bharat Coking Coal Ltd. and their workmen.

APPEARANCES:

On behalf of the employers : Shri B. Joshi, Advocate.

On behalf of the workman : Shri D. Mukherjee, Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dated, Dhanbad, the 12th August, 1985

AWARD

The Government of Inidia in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10 (1) (d) of the I.D. Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-20012(372)/84-D. III (A), dated the 18th March, 1985.

SCHEDULE

Whether the demand of Bihar Colliery Kamgar Union that S/Shri Ramchandra Prasad and Sachidanand Prasad of Jamunia Open Cast Project of Messrs. Bharat Coking Coal Limited, Post Office Nudkhurkee, District Dhanbad should be given Excavation Group 'C' with eight yearly increments is justified ? If so, to what relief the concerned workmen are entitled and from what date?

The case of the workmen is that the concerned workmen S|Shri Ramchandra Prasad and Sachidanand Prasad were appointed as Fitter helper in the month of April, 1976 and were posted at Damoda Colliery Workshop of Barora Area. They were ITI qualified and had experience of working prior to their joining in M/s. Bharat Coking Coal Ltd. In the year 1981 they were found suitable for promotion to Cat. IV by the Departmental Promotion Committee and they were promoted as Fitters. They were transferred to Jamunia Open Cast Project and since then they are working continuously as Excavation Fitter at Jamunia Open Cast Project. Many Junior fitters and Fitter helpers have been placed in Excavation Group C and D respectively with eight yearly increment, Shri Chaman Lal junior to the concerned workmen has been placed in Excavation Group D for performing the same and similar jobs as is being performed by the concerned workmen. Shri Shankar Prasad Singh, Fitter who is also junior to the concerned workmen by many years has been placed in Excavation Group C with five yearly increments for performing the same and similar jobs as is being performed by the concerned workmen. Shri Ramchandran Sinha has been working as Fitter helper under the concerned workman Shri Ramchandra Prasad and is getting Excavation Group-D with four yearly increments. Shri Devi Sharma, Fitter helper attached to the concerned workman Shri Sachidanand Prasad has been given Excavation Group-D. Many workmen junior to the concerned workmen are getting Excavaton Group C with 5 to 8 yearly increments for performing the same type of duties as are being performed by the concerned workmen. The concerned workmen represented before the management several times for allowing them Excavation Group-C with eight yearly increments but without any effect. hereafter the union raised an industrial dispute before the ALC (C), Dhanbad for conciliation but the same ended in failure and thereafter Govt. of India, Ministry of Labour has referred the dispute for adjudication by this Tribunal. The action of the management in placing the junior workmen in Excavation Group C with 5 to 8 yearly increments by superceding the concerned workmen is illegal, unjustified and against the principle of natural justice. The action of the management of denial of equal pay for equal jobs is against the decision of the Supreme Court and against the policy decision of the management. The demand of the union that the concerned workmen are entitled for Excavation Group C with eight yearly increments with retrospective effect with all consequential benefits is legal and justified and the concerned workmen should be allowed the same.

The case of the management is that the concerned workmen who were appointed as Fitter helper in Cat. II in April, 1976 were promoted by Departmental Promotion Committee in 1981 as Fitter in Cat. IV. They belong to E and M Cadre and worked at Damoda Colliery as Fitter from the date of their promotion till the transfer to Jamunia Open Cast Project of Block II in the year 1983. The concerned workmen continued to work as Fitter in Cat. IV after their placement at the Jamunia Open Cast Project and continued to remain in the E & M cadre of the management. They have not yet been transferred to Excavation cadre to enable them to claim for wages of Excavation Cadre. The change of cadre is done according to procedure after any workman applies for the same which depends upon the availability of job in that cadre and suitability of candidate. The concerned workmen did not apply for their change in the cadre of E & M to that of Excavation and the matter has not been examined by the management. The demand of the concerned workmen for fixing scale of pay in the excavation cadre is premature and without any merit. The mechanical Fitter belong to E & M (Electrical and Mechanical) cadre and they are capable of repairing and maintenance of machineries like pump, haulage winders, coal cutters drilling machines and equipment etc. used in the mines for the purpose of winning coal. The mechanical Fitter belonging to Excavation cadre is capable of repairing and maintenance of machines, used in removal of over burden such as Bulldozer scrapper, drag line operator shovels, dumper etc. In the underground mines coal is obtained without removing Over burden and therefore there is no scope for employement of Fitters belonging to excavation cadre. In the mechanically operated open cast project there is scope for employment of Fitters belonging to excavation cadre as well as Electrical & Mechanical cadre as Over burden remover and winning coal from two different points of mining operations used for the purpose. The concerned workmen belong to the electrical & Mechanical cadre and are performing the duties of Fitters belonging to E & M cadre and as such they cannot demand the grades of excavation cadre. There are sufficient number of Fitters belonging to excavation cadre in the Over burden removal and presently there is no scope for conversion of the concerned workmen to excavation cadre. The management denies that the concerned workmen are performing the duties of excavation fitter similar to the workmen performed by Chaman Lal and Shri Shankar Prasad Singh or that of excavation Fitter helpers are working under them. It is also denied that the junior workmen are getting excavation group-C with increments as alleged. The concerned workmen are not entitled to the exacavation grade as claimed by them.

The workmen have examined WW-1 Shri Ramchandra rasad who is one of the workmen in this reference. The management have not examined any witness in this case but have produced some documents which are marked Ext. M-1 to M-5 series. The workmen also have produced some documents which have been marked Ext. W-1 to W-4. It is the admitted case of the parties that the concerned workmen were working as Mechanical Fitter in Cat. IV in Damoda Colliery workshop prior to their transfer to Jamunia Open Cast Project in 1983. Ext. M-1 dt. 15-4-1976 and Ext. M-2 dated 1-4-76 are office orders showing the appointment of two concerned workmen as Fitter helper in Cat. II. Ext. M-3 is the order dated 6-8-83 to show that the two concerned workmen who were working as Mechanical Fitter in Damoda Workshop were transferred to Block II of Jamunia Open Cast Project to work in the same capacity and scale of pay. Ext. M-4 is the cadre scheme for Wage Board Personnel (E & M) in BCCL. Ext. M-5 to M-/2 are the office orders showing the appointment of Shri Ramchandar Prasad Sinha as Shovel helper from 1-4-84 Shri Shankar Prasad Singh as Fitter (Ex) from 12-9-83 and Chaman Lal O.E.P. Fitter in the excavation department. WW-1 Shri Ramchandar Prasad has stated that since 28-2-83 both the concerned workmen are continuously working as Excavation Fitter in Excavation section. He has further stated that they are maintaining and repairing shovel and Russian Drill of 230 M.H. He has further stated that there is no scrapper and drag line in Jamunia Open Cast Project. According to him Shri Shankar Prasad Singh is working in Jamunia Open Cast Project as Fitter is getting Excavation Grade-C with five yearly increment although Shri Shankar Pd. Singh is junior to him and was appointed after him. He has stated that one Shri Ramchandar Sinha Fitter helper is attached to him and is getting excavation Grade-D with four yearly increments and that one Devi Sharma Fitter helper was attached to the other concerned workman Sachidanand Prasad is getting Excavation Grade-D. He has stated that Chaman Lal is working along with him in the shovel and is getting excavation Grade-D with eight yearly increments, although they were all freshly appointed and were junior to the concerned workmen. According to him all the workmen working in Excavation Section get Excavation grade. but the concerned workmen did not get excavation grade. It is stated by him that there were no Fitters except the two concerned workmen when they had joined Jamunia Open Cast Project at its start. It appears from his evidence in cross-examination that the persons whose names he has stated as juniors were directly recruited in the Open cast Project in excavation cadre. He has stated that the persons appointed in the excavation cadre are given Grade-C, D & E whereas ppersons appointed in Electrical and mechanical cadre are given Grade-II, III IV, V and VI. He has stated that the excavation cadre is in the Open cast project to look after the machinery employed in removal of the over burden remover. He has admitted that they have not received any letter to work in excavation cadre and for the change of the cadre. There is no doubt that the concerned workmen were appointed in Electrical & Mechanical cadre but it appears as is stated by WW-1 that after the transfer of the concerned workmen to Jamunia Open Cast Project they were working as Fitters in the excavation cadre although they were not getting the salary or the wages of excavation cadre. It is submitted on behalf of the concerned workmen that in Open cast Project there is only excavation cadre for maintaining and repairing of earth moving machineries and

that the concerned workmen were maintaining those machines which were in use in the open cast project and as such they are entitled to the excavation cadre as claimed by them. No witness has come forward on behalf of the management to deny the assertion made on behalf of the concerned workmen. On the contrary the union have filed two certificates Ext. W-3 and W-4 dated 19-5-85 issued by the Project Manager Jamunia Open Cast Project which shows that both the concerned workmen are working under him in the excavation cadre. It will further appear that the concerned workmen Shri Sachidanand Prasad Fitter is working in excavation cadre from 15-1-1983 and the other concerned workman Shri Ramchandra Prasad Singh Fitter is working in the Jamunia Open Cast Project as Excavation Fitter from 28-2-83. These certificates are granted by the Project Manager of Jamunia Open Cast Project and no witness has come forward on the side of the management to falsify these certificates. Although the W.S. on behalf of the management was filed by the same Project Manager Jamunia Open Cast Project, the same has been given a go by and certificates have been issued by the Project Manager testifying to the fact that the concerned workmen were working in the capacity of Excavation Fitter in excavation cadre of the project. The case of the workmen, therefore, finds full support by the certificate Ext. W-3 and W-4 issued by the Project Manager of Jamunia Open Cast Project and now there is no room to doubt the truth of the case of the workmen. Accordingly I hold that the concerned workmen were working as Excavation Fitter in Excavation cadre of Jamunia Open Cast Project and that they are entitled to the excavation cadre as all other workmen employed in the Open cast Project.

It will appear from Ext. W-1 and W-2 that the concerned workmen had made demand for getting Excavation grade m September, 1983 and November, 1983. Thus it will appear that the concerned workmen had demanded for excavation grade from the management.

WW-1 has stated that Shankar Prasad who is workng as a Fitter in Jamunia Open Cast Project and was a fresh recruit was getting excavation grade-C with five yearly increments and that the concerned workman and Shankar Pd. Singh are doing the same job. He has named three fitter helpers who are getting Excavation Grade-D with some yearly increments. As Shankar Prasad Singh who is a new recruit in Jamunia Open Cast Project is getting exacavation grade-C with five yearly increment as Fitter the concerned workmen are also entitled to the same scale of wages of group-C. As the concerned workmen Shri Sachidanand Pd. Singh is working as Fitter in Jamunia Open Cast Project from 15th January, 1983 and the concerned workman Shri Ramchander Prasad Singh is working as Excavation Fitter in the Project from 28-2-83 (vide Ext. W-3 and W-4) they are entitled to Excavation Grade-C with five yearly increments from the dates stated above.

In the result, I hold that the demand of Bihar Colliery Kamgar Union that Shri Ramchandra Prasad and Sachidanand Prasad of Jamunia Open Cast Project of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. should be given Excavation Group-C is justified. I further hold that they are not entitled to 8 yearly increments but are entitled to five yearly increments in Excavation Grade-C from the date indicated above.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-20012(372)/84-D.III(A)]

A. V. S. SARMA, Desk Officer

Dated-: 12-8-1985.

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1985

का. आ. 4373 :—बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 3 के उप नियम (2) और नियम 16 के साथ पठित बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 62) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार दिनांक 10 नवम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र भाग-2, खंड-3, उप खंड (II) के पृष्ठ 3268-69 पर प्रकाशित अधिसूचना सं. का. आ. 3582, तारीख 23 अक्तूबर, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या-4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात् :—

4. श्री जी. रघुपति,
विधान सभा सदस्य,
कटपाडी।

[संख्या-यू-19012/5/83-कल्याण-2]

रवि दत्त मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd September, 1985

S.O. 4373.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 (62 of 1976) read with sub-rule (2) of rule (3) and rule 16 of Beedi Workers Welfare Fund Rules, 1978, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification S.O. 3582 dated 23rd October, 1984 published at pages 3268-69 of Part II Section 3 Sub-section (ii) of the Gazette of India dated the 10th November, 1984.

In the said notification, against serial number 4, the following shall be substituted namely —

4. Thiru G. Ragupathi,
Member Legislative Assembly,
Katpadi.

[No. U-19012/5/83-W. II]

R. D. MISHRA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985